RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 10 अंक 87
नई दिल्ली, बुधवार, 2 फरवरी, 2022
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में मिताली दूसरे स्थान पर
स्पोर्ट्स-12

राजनीति से परे अर्थव्यवस्था पर फोकस

- अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खोली तिजोरी
- महामारी काल में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और रोजगार सृजन पर जोर, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़े ठोस कदम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर होने के बावजूद कोई लोकलुभावन वादा नहीं, हवाई-हवाई घोषणा नहीं, बल्कि महामारी के नाजुक वक्त में मध्यम वर्ग को संभलकर कदम बढ़ाने के संदेश और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। इसमें सबसे ज्यादा जोर अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। इसके लिए उनकी डिजिटल पोटली से 39.45 लाख करोड़ रुपए निकले हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को गति देने वाले राजमार्गों, मकानों, कृषि, वित्त जैसे सेक्टरों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को तो प्रोत्साहित किया है और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव उन्होंने नहीं किया है। इससे सरकार ने एक बड़े मध्यम वर्ग के नाराज होने का खतरा मोल लिया है, लेकिन सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर मध्य वर्ग के आम जनजीवन को और आसान बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सीतारमण ने कहा कि बजट का रुख विकास के सात इंजन- सड़क, रेलवे, हवाईअड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे पर आधारित है। ये बुनियादी ढांचे के प्रमुख क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, जल (शेष पेज 9)

गंगा किनारे होगी प्राकृतिक खेती, खाते में जाएगी एमएसपी

अजीत तिवारी। नई दिल्ली

- रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, ड्रोन से की जाएगी फसलों की निगरानी

केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम देने और उनकी आय बढ़ाने के वादे को पूरा करने का जतन केंद्रीय बजट में किया गया है, जिसके तहत एमएसपी पर भारी मात्रा में फसलों की खरीदारी और उसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। मिट्टी को रसायन मुक्त करने और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े गलियारों में रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए देश भर के किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाएं सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र संकल्पित है जिसके तहत किसान ड्रोन, रसायन मुक्त जैविक खेती, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कुल 12 बार किसान शब्द का जिक्र किया। सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास, सरकार की आगे बढ़ने की चार प्राथमिकताओं में से एक है। समावेशी विकास के तहत सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी। सरकार कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के माध्यम से सह-निवेश मॉडल के तहत जुटाई मिश्रित पूंजी के साथ एक कोष की सुविधा देगी। जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप का वित्तपोषण करेगी। इन स्टार्टअप में किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए अंतर-क्षेत्रीय समर्थन, किसानों के हित में खेती के लिए किराए पर मशीनरी उपलब्ध कराना (शेष पेज 9)

एमएसपी पर होगी रिकॉर्ड खरीद

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 163 लाख किसानों से 1,208 लाख टन गेहूं और धान की खरीद करेगी। उन्होंने कहा, एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे डाले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज उत्पादों की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को सहायता देगी।

यह बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। **-नरेंद्र मोदी**

यह बजट मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा, मांग को मजबूती देगा और एक मजबूत, समृद्ध और विश्वास से लबरेज भारत की क्षमताओं का विकास करेगा। बजट ने आत्मनिर्भरता पर सरकार के जोर को रेखांकित किया है। **-राजनाथ सिंह**

आज केंद्रीय बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा हुई है। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। **-योगी आदित्यनाथ**

बजट में मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। हमारे देश में चारों ओर निराशा है, हमारे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है और मोदी सरकार के बजट ने एक बार फिर इस दुखद सच्चाई की अनदेखी की है। **-राहुल गांधी**

जनता महंगाई से परेशान है लेकिन इस बजट में राहत नहीं है। बहुत उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केन्द्र की भाजपा सरकार को चिंता सिर्फ बड़े पूंजी घरानों की रहती है उसकी सारी नीतियां उसके हित की ही बनती हैं। **-अखिलेश यादव**

बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। बड़ी-बड़ी बाते हैं और हकीकत में कुछ नहीं है। पेगासस स्पिन बजट है। **-ममता बनर्जी**

लगातार 8वें साल करदाताओं के हिस्से मायूसी

- इनकम टैक्स स्लैब में इस साल भी नहीं हुआ बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बरकरार
- टैक्स भरते समय गलती करने पर दो वर्ष के अंदर कर सकते हैं रिटर्न अपडेट

मंहगा	सस्ता
छाता	कैमरे वाले मोबाइल फोन
कृत्रिम ज्वैलरी	फ्रोजन मसल्स
लाउडस्पीकर	फ्रोजन स्क्विड
हेडफोन और इयरफोन	हींग
स्मार्ट मीटर	कोको बीन्स
सोलर सेल	मिथाइल अल्कोहल
सोलर मॉड्यूल	एसिटिक एसिड
एक्स-रे मशीन	तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे
इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे	

जाहिद अली। नई दिल्ली

कोरोना महामारी, महंगाई और निजी क्षेत्रों में वेतन कटौती के बाद भी बजट 2022 में वेतनभागी के लिए आयकर की छूट की उम्मीदों को झटका लगा है। वित्तमंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जब डिजिटल झोली खोली, तो हर बार की तरह जो नौकरीपेशा लोग आयकर में कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे मायूस हो गए।

वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। जो स्लैब पहले से लागू हैं, वहीं अगले साल भी लागू रहेंगे। वहीं मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई। हालांकि अब टैक्स भरते समय गलती करने पर दो वर्ष के अंदर रिटर्न अपटेड किया जा सकता है। राहत की बात करें तो केवल दिव्यांगों को इनकम टैक्स में मामूली सी छूट दी गई है। आखिरी बार वर्ष 2014 के बजट में आयकर छूट का दायरा बढ़ाया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार चौथा बजट पेश किया। बढ़ती महंगाई को लेकर माध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स में फेरबदल की उम्मीद लगाई थी ताकि भविष्य के लिए अतिरिक्त बचत को संजाया जा सके। लेकिन वित्त मंत्री ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया और मानक कटौती को भी यथावत रखा, उम्मीद की जा रही थी स्टैंडर्ड डिडक्शन को पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि केंद सरकार ने चुनिंदा स्टार्टअप्स को टैक्स राहत के लिए समयसीमा को बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया है।

वहीं रिटर्न अपडेट करने की अनुमति भी दी गई है। सरकार ने फैसला किया है कि अगर करदाता अपना रिटर्न अपडेट करना चाहता है तो वह खुद दो साल में सुधार कर सकता है। इसके पीछे मंशा लगातार हो रही मुकदमेबाजी थी। अकसर देखा गया है कि करदाता के एक गलती के कारण लंबी कानूनी प्रकिया से गुजरना पड़ता है। अब आम आदमी के पास इस बात की सहुलियत होगी कि दो साल में अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है। वहीं दिव्यांगों (शेष पेज 9)

सड़क परियोजनाओं को लगेंगे पंख

- देशभर में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य, मिले 20,000 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आर्थिक विकास का सेतु बने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की तमाम परियोजनाओं को पंख लगने वाले हैं। मौजूदा बजट में सरकार ने फैसला किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर सड़कों का विस्तार किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रतिदिन 70 किमी सड़कें बनाई जाएंगी, जो कि 2022 के लिए निर्धारित 40 किमी की दर से लगभग दोगुनी है। परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

वित्तमंत्री सीतारमण ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोगों एवं सामान की तेज आवाजाही के लिए सरकार एक्सप्रेसवे के बारे में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भी लेकर आएगी। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं देखरेख मुश्किल होने से रस्सियों से बने मार्ग (रोपवे) पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊविकल्प के रूप में उभरे हैं। इसके लिए सरकार पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू करेगी।

रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू करने के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही का सुगम मार्ग तैयार करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल आठ रोपवे परियोजनाओं के अनुबंध जारी किए जाएंगे। सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चार स्थानों पर (शेष पेज 9)

गांवों-शहरों में गरीबों के लिए 80 लाख घर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आवास क्षेत्र में एक बार फिर से रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख सस्ते घर बनाने का निर्णय लिया है। ये घर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों स्थानों पर होंगे। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान की। सीतारमण ने कहा कि पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरियों को लेकर समय कम करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी, ताकि शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा दिया जा (शेष पेज 9)

देशभर में चलेंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें

- रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ मिले

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

देश के रेलयात्रियों को अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों उपहार सरकार देने जा रही है। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट घोषणा करते हुए कहा कि बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 नई वंदे भारत ट्रेनें कम वजन की एल्यूमीनियम से बनाई जाएंगी। जिससे प्रत्येक ट्रेन करीब 50 टन हल्की होगी और इस्पात की रेलगाहड़ियों की तुलना में कम ऊर्जा खपत होगी।

सीतारमण ने केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 20,311 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि रेल क्षेत्र एक स्टेशन एक उत्पाद भी विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को रेलवे के जरिए ढुलाई का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा था कि रेलवे 44 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण कर रहा है और 15 अगस्त, 2023 तक कम से कम 75 मार्गों पर इन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि रेलवे में एक स्टेशन-एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आवश्यक मदद मिले सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो सुरक्षा (शेष पेज 9)

बाजार

संसेक्स	58,862	↑	848	
निफ्टी	17,576	↑	237	
सोना	47,844	↑	333	/10g
चांदी	61,164	↓	68	/kg

क्विक न्यूज

महामारी ने दिखाया रास्ता, खुलेगी डिजि यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली। दो साल पहले आई कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह शिक्षा का ऑनलाइन मोड बड़ा सहारा बनकर उभरा, उसे अब स्थायी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इससे स्कूल-कॉलेज जाने के बजाय पूरी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश मे शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एक क्लास एक टीवी चैनल की व्यवस्था लागू की जाएगी।

अगले वित्त वर्ष से चलेगा डिजिटल रुपया

- क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ सरकार ने लगाया 30 फीसदी टैक्स, वर्चुअली ट्रांसफर पर देना होगा एक फीसदी टीडीएस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत समेत दुनियाभर में क्रिप्टो या डिजिटल मुद्राओं को लेकर दीवानगी छायी हुई है। इसी को देखते हुए अब देश में एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में क्रिप्टो का देशी संस्करण पेश किया जाएगा, जो भौतिक रूप से प्रचलित मुद्रा के डिजिटल रूप को प्रतिबिंबित करेगा। इसे डिजिटल रुपया कहा जाएगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक डिजिटल रुपया नामक यह मुद्रा, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा। इस केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को नियंत्रित करने वाले विनियमन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए अगले वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी पेश कर सकती है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। भारतीय डिजिटल करेंसी से अर्थव्यवस्था को (शेष पेज 9)

केंद्र ने मनरेगा के लिए 73 हजार करोड़ आवंटित किए

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित आकलन से 25.51 प्रतिशत कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बजट में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि, बाद में काम की अधिक मांग के कारण इसे संशोधित कर 98,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। मनरेगा का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में हर परिवार के लिए कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से (शेष पेज 9)

इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी बदलने की मिलेगी सुविधा

- चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरियां बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए लाई जाएगी नीति

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरियां बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति लाई जाएगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में बैटरी चार्जिंग की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने से जुड़ी एक नीति लेकर आएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह की कमी को देखते हुए बैटरियां बदलने की सुविधा देनी जरूरी है। उन्होंने कहा, शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह की उपलब्धता से जुड़ी समस्या को देखते हुए बैटरी बदलने की नीति लाई जाएगी ताकि इससे जुड़े परिचालन को नियमित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैटरी या ऊर्जा सेवा के (शेष पेज 9)

ईवी क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्ताव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे: उद्योग

मुंबई। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने मंगलवार को कहा कि आम बजट 2022-23 का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। उद्योग ने कहा कि बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने की सुविधा देने के बारे में एक नीति लाने का प्रस्ताव रखा गया है जो ईवी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा, बैटरी अदला-बदली की नीति लाना और बैटरी या बिजली को एक सेवा के तौर पर मान्यता देने से ईवी का आधारभूत ढांचा बढ़ेगा और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैजेंटा में निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मैक्सवेल लुईस ने कहा कि आम बजट ने दिखाया है कि इरादा स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देने का है। लॉग9 मटैरियल्स के संस्थापक डॉ. अक्षय सिंघल ने कहा कि बैटरी अदला-बदली जैसे नए दौर के बिजनेस मॉडल अपनाने को लेकर खुलापन स्वागतयोग्य है। हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने ईवी क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रस्तावों के बारे में कहा कि इससे वृद्धि के लिए नए रास्ते खुलेंगे और देश में ईवी तथा ऊर्जा क्षेत्र का विकास होगा।

चुनावी खर्च का मिलान न होने पर 20 उम्मीदवारों को नोटिस

लेखा टीम ने प्रत्याशियों को 48 घंटे का दिया समय

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे खर्च का मिलान न होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 20 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। उम्मीदवारों को 48 घंटे के अंदर व्यय का मिलान कराने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास ने बताया कि सोमवार को विकास भवन स्थित कंट्रोल रूम में लेखा टीम के समक्ष निर्वाचन व्यय रजिस्टर का मिलान कराने के लिए प्रत्याशियों को बुलाया गया था। लोनी विधानसभा सीट से आप के प्रत्याशी सचिन शर्मा, एआइएमआइएम के प्रत्याशी डॉ महताब, हिदुस्थान निर्माण दल के प्रत्याशी अमित कुमार, मुरादनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अय्यूब खा, रालोद प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी, आप प्रत्याशी महेश त्यागी, विजय भारत पार्टी से प्रत्याशी राजकुमार त्यागी, निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात कुमार शर्मा, ललित मोहन त्यागी, साहिबाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी, बीएसपी प्रत्याशी अजीत कुमार पाल, सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा, जन अधिकार पार्टी से प्रत्याशी भूपेंद्रनाथ, एआइएमआइएम प्रत्याशी मनमोहन झा, सुभास पार्टी के प्रत्याशी सुजीत तिवारी, निर्दलीय प्रत्याशी गीतांजलि, विजय कुमार, गाजियाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी निमित, कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल, बीएसपी प्रत्याशी केके शुक्ला, निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष गुप्ता, रानी देव पिटू सिंह, रजनीश कुमार ठाकुर, मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुमारी, आप प्रत्याशी हरिद्र शर्मा, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी विजय को नोटिस भेजकर निर्वाचन व्यय रजिस्टर का मिलान कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कानून व्यवस्था पर नजर रखने को प्रेक्षक नियुक्त

निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से समस्त विधानसभा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए उमेश चंद्र दत्ता को निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षक बनाया है। इनका मोबाइल नं 9910589364 है। यदि किसी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन में कानून व्यवस्था से संबंधित कोई परेशानी हो तो इसके लिए वह पुलिस प्रेक्षक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 8वीं बटालियन सेक्टर 19 कमला नेहरू नगर गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दस प्रत्याशी आयोग के रडार पर

निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● मतदान से पहले इश्तेहार से देनी होगी मतदाताओं को जानकारी

गौतमबुद्धनगर जिले की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 उम्मीदवारों को नोटिस जारी करके उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर प्रकाशित एवं प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

अपर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने इन 10 उम्मीदवारों को नोटिस जारी करके कहा कि वे अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर तीन बार प्रकाशित एवं प्रसारित करें। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गौतमबुद्धनगर की नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीट से 39 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक, यदि किसी प्रत्याशी का आपराधिक इतिहास होता है, तो उसे नामांकन पत्र में इसका जिक्र करना होता है और मतदान से पूर्व अखबारों और टीवी चैनल पर इस संबंधी जानकारी तीन बार प्रकाशित एवं प्रसारित करनी होती है।

उन्होंने बताया कि 39 प्रत्याशियों में से 10 के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रत्याशी ने भी अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी समाचार पत्रों या टीवी चैनल में प्रसारित या प्रकाशित नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है, ताकि कि वे समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल के माध्यम से अपने अपराधिक इतिहास की जानकारी जल्द से जल्द जनता को दें। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रत्याशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौतमबुद्धनगर में 31 मार्च तक धारा-144 लागू

नोएडा। जनपद में मंगलवार से लेकर 31 मार्च तक दो महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में लगायी गयी धारा-144 अब मार्च के अंत तक लागू रहेगी। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस बाबत आदेश जारी किया है।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है और 10 फरवरी को जनपद में मतदान होना है। इन दो महीनों में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत कई त्योहार आने वाले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में एक फरवरी से 31 मार्च तक धारा-144 लागू रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता। शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।

द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

संक्षिप्त समाचार

पुलिस चौकी के पास स्थित दुकान जहां चोरी की वारदात हुई।

दुकान से 11 लाख का मोबाइल चोरी

नोएडा। शहर में मंगलवार सुबह एक बड़ी वारदात हुई। जनपद के फेस-2 थाना क्षेत्र भंगेल पुलिस चौकी के पास एक मोबाइल की दुकान से 11 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी हो गए। बड़ी बात यह है कि दुकान के ठीक सामने पुलिस चौकी है, बावजूद इसके इतनी बड़ी वारदात हुई है। यह गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के ऊपर एक बड़ा सवाल है। भंगेल चौकी के पास कुलदीप कुमार चौहान पिछले 4 साल से मोबाइल की दुकान चला रहे हैं। कुलदीप चौहान की मेन रोड पर कोने पर दुकान है। जहां पर कुलदीप की दुकान है, वहां से पुलिस चौकी केवल 10 कदम की दूरी पर है। उसके बावजूद भी मोबाइल की दुकान से 11 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हो गए। पीड़ित कुलदीप ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच की है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काटकर विभिन्न कंपनियों के 60 मोबाइल चोरी कर लिए।

चोरी के वाहनों के साथ दो गिरफ्तार

नोएडा। थाना बिसरख पुलिस ने बीती रात दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की तीन कार, एक मोटरसाइकिल तथा कार व मोटरसाइकिल के इंजन आदि बरामद किए हैं। बिसरख थाने के प्रभारी निरीक्षक यशपाल धामा ने बताया कि बीती रात गश्त पर निकली थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर शाहिद तथा शेर सिंह को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर तीन कार, एक मोटरसाइकिल तथा कई इंजन आदि बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संदिग्ध परिस्थितियों में दो किशोरी लापता

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र की अलग-अलग कॉलोनियों से दो किशोरी रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत की है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। संतपुरा कॉलोनी की रहने वाली किशोरी पास के ही एक स्कूल की छात्रा है। वह रविवार को किसी काम से घर से निकली थी, लेकिन रात तक भी नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं लगा। परेशान होकर पुलिस से शिकायत की गई। उधर, कस्बा रोड पर ट्यूशन के लिए गई एक किशोरी भी लापता हो गई।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, हालांकि यह सुपुर्द नहीं की जा सकी और इसलिए एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	जसविंदर सिंह, रिंपी, एच नंबर डी-2-27, हरि नगर एक्सटेंशन, बदरपुर, साउथ वेस्ट दिल्ली-110044 /खाता :-एलबीडीईएल00005154438	फ्लैट नंबर -सी 2/1104, 11वां तल, टावर सी 2, सेक्टर-10 वर्धमान गार्डेनिया, सोनीपत	10-11-2021 रू. 39,66,418/-	04-08-2021
2.	राकेश रंजन, श्यामली रंजन, एच नंबर डी 1/94, संजय कालोनी, सेक्टर-2, फरीदाबाद, हरियाणा /खाता :- एलबीजीयूआर00005134738	प्लॉट नंबर 3336, सेक्टर 56'56 ए. अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद	10-11-2021 रू. 30,40,805/-	04-08-2021
3.	कुमार आयुष, वंदना पांडे, बी 13, द्वितीय तल, प्रताप नगर, निकट फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल, मयूर विहार फेज-1, प्रताप नगर, नई दिल्ली/ खाता :-एलबीडीईएल00002393969	फ्लैट नंबर जे 1801, 18वां तल, टावर जे, अजनारा ली गार्डन, प्लॉट नंबर जीएच-02, सेक्टर-16, नोएडा	10-11-2021 रू. 36,95,147/-	10-07-2021
4.	रवीन्द्र दहिया, शिखा, एचनंबर 532 बी, ग्राम मडाना, सोनीपत, हरियाणा/खाता :- एलबीडीईएल00002421129	फ्लैट नंबर एच 1104, 11वां तल, टावर एच, केडीपी ग्रैंड सवाना, राजनगर एक्सटेंशन, एनएच 58, गाजियाबाद	10-11-2021 रू. 32,43,262/-	06-07-2021
5.	गौरव पगरोत्रा, भीकम सिंह पगरोत्रा, विकास पगरोत्रा, एस 5 मॉड्यूल 9, मंगलम अपार्टमेंट्स, अभय खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद/ खाता :-एलबीएनओडी00002339927	फ्लैट नंबर 23210, 23वां तल, टावर लॉरेल महागुन माइवुड्स फेज-3, प्लॉट नबर जीएच-04, सेक्टर 16 सी, नोएडा	10-11-2021 रू. 31,87,135/-	05-07-2021
6.	पूनम कुमारी, प्रताप चन्द्र, राज वर्धन, 801, गंगोत्री अपा. एग्जीबिशन रोड, पटना, बिहार / खाता :- एलबीजीयूआर00002318436	प्लॉट नंबर 10176, 10वां तल, मारवेला महागुन माइवुड्स, जीएच-04, सेक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा	10-11-2021 रू. 33,80,913.08/-	05-07-2021
7.	प्रवीण कुमार, खुशबू कुमारी, बी-123, प्रथम तल, पांडव नगर, शकरपुर, दिल्ली/ खाता :-एलबीडीईएल00003446307	फ्लैट नंबर जी 3046/जीसी-16, तृतीय तल, टावर जी, 16वां एवेन्यू गौड़ सिटी 2, प्लॉट नंबर 03, सेक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा	10-11-2021 रू. 31,31,971/-	28-02-2021
8.	रवि कांत सुमन, पूजा सुमन, प्लॉट नंबर 53, एफएफ 3, ज्ञान खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद/ खाता :-एलबीएनओडी00002853050	फ्लैट नंबर 07228, 7वां तल, एक्सल महागुन माइवुड्स, प्लॉट नबर जीएच-04, सेक्टर 16 सी, नोएडा	10-11-2021 रू. 30,13,785/-	01-07-2021
9.	रोहित रैना, रेणुका रैना, फ्लैट नबर 15/सी-348 ए, गौड़ एन्क्लेव-2, शालीमार गार्डन एक्स.-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद/खाता :- एलबीडीईएल00002091351	फ्लैट नंबर जे-606, छठा तल, टावर 0जे अजनारा ली गार्डन, प्लॉट नंबर जीएच-02, सेक्टर 16, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट नोएडा	20-10-2021 रू. 35,40,647/-	12-07-2021
10.	राखी गुप्ता, नकुल गुप्ता, वेलेनो इन्क. 6 अंडर हिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली/ खाता :-एलबीडीईएल00002356623	यूनिट नंबर 22185, 22वां तल, ब्लॉक मैनग्रोव महागुन माइवुड फेज-3, महागुन इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नंबर जीएच-04, सेक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा	20-10-2021 रू. 30,66,513/-	01-07-2021
11.	आदर्श कुमार, शिल्पा अग्रवाल एल 601, पर्ल्स गेटवे, टावर, सेक्टर-44, नोएडा/ खाता :-एलबीडीईएल00002432960	फ्लैट नंबर सी 2202, टावर सी 22वां तल, ऐमेडस, प्लॉट नंबर जीएच-02, सेक्टर 143, गौतमबुद्ध नगर,	20-10-2021 रू. 40,27,872/-	01-07-2021
12.	आदर्श कुमार, शिल्पा अग्रवाल एल 601, पर्ल्स गेटवे, टावर, सेक्टर-44, नोएडा/खाता:- एलबीडीईएल00002431882	फ्लैट नंबर सी 2202, टावर सी 22वां तल, ऐमेडस, प्लॉट नंबर जीएच-02, सेक्टर 143, गौतमबुद्ध नगर,	20-10-2021 रू. 40,69589/-	01-07-2021
13.	आकाश गुर्जर, अरूण नागर, 3 ए/103, भू तल, एनआईटी, फरीदाबाद/खाता :- एलबीएफडीबी00005108518	प्लॉट नंबर 154, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, सेक्टर 49, सैनिक कालोनी, फरीदाबाद	20-10-2021 रू. 58,29,803/-	13-07-2021
14.	चंदन कुमार गोस्वामी, सुदीप्ता लक्ष्मी खौंड 24181, होलीओक अपा. ई ऐलिसोविजो, कैलीफोर्निया/खाता :- एलबीजीएचजैड00001436579	फ्लैट नंबर टी-11-504, 5वां तल, आम्रपाली ग्रैंड, जीएच-09, जीटा 1, नोएडा	20-10-2021 रू. 30,20,716.45/-	31-07-2021
15.	नविता कुन्द्रा, विशाल मित्तल, फ्लैट नंबर 001, भू तल, टावर बी 5, इरोस सम्पूर्णम, सेक्टर-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा/खाता :-एलबीएनओडी00002549263	फ्लैट नंबर 626, छठा तल, टावर सिद्धि महागुन मंत्रा-II, प्लॉट नबर जीएच-01, सेक्टर 10, ग्रेटर नोएडा नोएडा	20-10-2021 रू. 35,63,792/-	01-07-2021
16.	निधि अरोड़ा, ऋषभ एच अरोड़ा, ए-2101, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स, सेक्टर-78, नोएडा/खाता :-एलबीएनओडी00002880906	फ्लैट नंबर 1012, 10वां तल,, प्लॉट नबर जीएच-01 बी, सेक्टर 10, बिल्डिंग ओम महागुन मंत्रा-1, नोएडा	20-10-2021 रू. 34,26,264/-	01-07-2021
17.	प्रमोद राय, शोभना राय, बीएच-135, प्रथम तल, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद/ खाता :-एलबीएनओडी00002391059	फ्लैट नंबर 1229, 12वां तल,, टावर सिद्धि प्लॉट नबर जीएच-01 ए, महागुन मंत्रा-II, सेक्टर 10, नोएडा	20-10-2021 रू. 26,63,957/-	01-07-2021
18.	रेणुका रैना, रोहित रैना, 15/सी-348, गौड़ एन्क्लेव-2, शालीमार गार्डन 2, गाजियाबाद/ खाता :-एलबीएनओडी00002253796	बी-205, द्वितीय तल, टावर बी, अजनारा ली गार्डन, प्लॉट नंबर जीएच-02, सेक्टर 16, नोएडा	20-10-2021 रू. 30,64,536/-	31-07-2021
19.	संजीव कुमार, स्मिता कुमार, फ्लैट 320 ई-डब्ल्यू सब मीटर, 621 अल वारसान, प्रथम, रिवीरा लेक व्यू, दुबई /खाता :- एलबीजीएचजैड00002558653	फ्लैट नंबर सी 1203 ए, 12वां तल, टावर सी, मनोरथ, जीएच-04 बी/1, सेक्टर 16, नोएडा	20-10-2021 रू. 29,37,543/-	06-07-2021
20.	सरिता संदीप नौटियाल, संदीप नौटियाल, 5 एम डेट सी/ओ 56 एपीओ, पिन 936841-936841, जैसलमेर/खाता :-एलबीएनओडी00003229032	फ्लैट नंबर 5211, 5वां तल, महागुन माइवुड्स, टावर कोरल वुड, प्लॉट नंबर जीएच-04, सेक्टर 16सी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा	20-10-2021 रू. 30,35,644/-	02-07-2021
21.	शरीक खान, राणा खान प्रीमियम मार्केटिंग सर्विसेज एलआईसी पी ओ बॉक्स 941, शारजाह/खाता :-एलबीएनओडी00002355234	फ्लैट नंबर 18178, 18वां तल, टावर मारवेला महागुन माइवुड्स,, प्लॉट नंबर जीएच-04, सेक्टर 16सी, ग्रेटर नोएडा	20-10-2021 रू. 45,47,182/-	01-07-2021
22.	सुनील कुमार, निशा शर्मा, ग्राम गिझोड़, सेक्टर-53, निकट होली चौक, नोएडा/ खाता :-एलबीएनओडी00003390508	फ्लैट नंबर 30092, टावर -30, 9वां तल, एटीएस पिक्चरस्क रिप्रीव्स, प्लॉट नंबर एससी-01, सेक्टर 152, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर	20-10-2021 रू. 36,89,235/-	31-07-2021
23.	तारीफ खान, मोहम्मद अहमद खान फाइनैंस दुबई सिलिकॉन ओएसिस आईटी प्लाजा, 810, शारजाह, दुबई/खाता :-एलबीएनओडी00002380736	फ्लैट नंबर 10173, 10वां तल, टावर मारवेला, प्लॉट नंबर जीएच-04, महागुन माइवुड्स, सेक्टर 16सी, नोएडा	20-10-2021 रू. 35,87,884/-	02-07-2021
24.	विनोद कुमार, मोनिका, फ्लैट नंबर 909, ब्लॉक जे, जीसी-1, गौड़ सिटी सेक्टर-4, प्रथम एवेन्यू, नोएडा, ग्रेटर नोएडा - 201308/खाता :- एलबीजीएचजैड00004897267	फ्लैट नंबर 0835, 8वां तल, टावर सरस्वती, महागुन मंत्रा 2, प्लॉट नंबर जीएच-01 ए, सेक्टर 10, नोएडा	20-10-2021 रू. 28,77,365/-	01-07-2021
25.	शालिनी शर्मा, संजय दधीच, एक्सप्लो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अपार्टमेंट नंबर 1619-ए, दि मंगोलियाज डीएलएफ गोल्फ कोर्स, गुरूग्राम, हरियाणा /खाता :- एलबीजीयूआर00003957467/ एलबीजीयूआर00004776573	फ्लैट नंबर पीआई-1/2101, 21वां तल, टावर पीआई-1, हाइड-1, पारस क्वार्टियर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, सेक्टर-2, गुरूग्राम, हरियाणा	28-10-2021 रू. 4,12,68,326.9/- एवं रू. 19,71,395.92/-	05-07-2021

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

तिथि : 02 फरवरी, 2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : दिल्ली/एनसीआर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

शराब तस्करी रोकने के लिए टीमें गठित

डीएम ने जिले की सीमा पर दलों को तैनात करने के दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशी अन्य प्रदेशों से मंगा रहे शराब

गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के वास्ते शराब का दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस तथा आबकारी विभाग के कई दल गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सीमा पर दलों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं हरियाणा और दिल्ली से जुड़ी हुई है और जानकारी मिली है कि चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशी दूसरे प्रदेशों से शराब मंगा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शराब की तस्करी करने वालों पर पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्ती की है लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने के लिए आबकारी विभाग को दल बनाकर उन्हें अलग-अलग सीमा पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए सात दलों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह बात सामने आती है कि प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोहरे के कारण हाइवे पर पलटा आलू से लदा ट्रक, लगा जाम

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा में बढ़ते कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कत आ रही है। मंगलवार सुबह कासना थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया। हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। ट्रक आलू की बोरियों से भरा हुआ था। डिवाइडर में टकराने के बाद सभी आलू की बोरियां सड़क पर बिखर गई। इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

इस दुर्घटना में सड़क पर लगे जाम के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रक के सड़क पर पलट जाने और आलू की बोरियां बिखर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। आपको बता दें कि 2-3 दिन से अधिक ठंड बढ़ने की वजह से कोहरा भी बढ़ गया है। जिस वजह से वाहन चालकों को सफर करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर, नोएडा और उत्तर प्रदेश में काफी इलाकों में विजिबिलिटी घटकर कुल 25 मीटर रह गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट

मंगलवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरा हो गया है। जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात अलर्ट जारी किया है। अधिकारी ने बताया कि सड़क पर कोहरा की अधिकता होने के कारण वाहन चालक अपने वाहन को उचित गति और उचित दूरी पर ही चलाये, दृश्यता कम है। यातायात संकेतों का पालन करते हुए अपने गंतव्य को जाना सुनिश्चित करें।

नेफोमा की महासचिव रश्मि पांडे ने छोड़ा पद

नोएडा। फ्लैट खरीदारों की आवाज को उठाने वाली सामाजिक संस्था से नेफोमा फ्लैट बायर्स एसोसिएशन की महासचिव रश्मि पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रश्मि पांडे काफी समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और अन्य स्थानों पर लोगों की सेवा कर रही थीं। रश्मि पांडे ने बताया कि पिछले दिनों उनको सूचना मिली कि नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान दादरी से चुनाव लड़ रहे हैं। यह जानकारी मिलने पर उनको झटका लगा, क्योंकि वह कभी राजनीति में नहीं जाना चाहती हैं और ना ही नेफोमा को राजनीतिक रूप से देखा था। इस कारण उन्होंने नेफोमा महासचिव पद छोड़ने का फैसला लिया।

ग्रेनो वेस्ट में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, फरार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● दो साल पहले हुई थी दोनों की शादी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बिसरख थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक बिसरख थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहबेरी में एक दंपत्ति रहता है। मंगलवार सुबह पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी की उम्र करीब 25 साल थी। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि दोनों में काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है।

एसटीपी संचालन सही नहीं होने पर कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● प्राधिकरण सीईओ ने की समीक्षा बैठक

नोएडा प्राधिकरण ने सीवरेज टर्मिनल प्लांट (एसटीपी) के सोसाइटियों में संचालित न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण सीईओ रितु महेश्वरी ने सोमवार को एनजीटी से पारित एक आदेश पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसटीपी के संचालित ना पाए जाने पर 4 बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक एसटीपी संचालित नहीं किए गए तो अधिकभोग प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर शहर में पूर्व में अलग-अलग सोसाइटियों के एसटीपी की जांच की गई। जांच के दौरान 95 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के एसटीपी में से 2 ही संचालित पाए गए।

इनके सैंपल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भेजे गए थे। जिनमें से 55 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। प्राधिकरण ने इन सभी सोसाइटियों को नोटिस भेजा है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद भी अभी तक कुछ सोसायटी द्वारा अंडरटेकिंग नहीं दी गई है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि इन सोसाइटियों के बिल्डरों पर आईपीसी धारा के मामले दर्ज कराई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीईओ ने ग्रुप हाउसिंग और नियोजन विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित सोसायटी स्काईटेक कंस्ट्रक्शन सेक्टर.76, मेसर्स ऐसोटेक विंडसोर सेक्टर.78, गार्डेनिया इंडिया सेक्टर.75 और फ्यूटेक शेल्टर्स सेक्टर.75 को एसटीपी को 15 तक संचालित करने को निर्देशित करें।

फर्जी आधार कार्ड लगाकर किशोरी से की कोर्ट मैरिज

गाजियाबाद। मुरादनगर की एक कॉलोनी में कथित तौर पर एक 17 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए शादी करने और एक साल तक तमंचे के बल पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। एक कमरे में बंधक बनाकर रखी गई किशोरी किसी तरह वहां से निकलकर थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी है। हालांकि, पुलिस जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। किशोरी का आरोप है कि गत 25 जनवरी को आरोपी ने फांसी लगाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन शोर मचाने पर पड़ोसियों की मदद से वह किसी तरह बच गई।

एक्सप्रेसवे पर काम में देरी से प्राधिकरण सीईओ सख्त

समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ तो एजेंसी पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा एक्सप्रेसवे पर काम करते मजदूर।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का कार्य काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। सीईओ ने कार्य समाप्त करने की अंतिम डेडलाइन 30 अप्रैल 2022 तक की दी है। अगर 30 अप्रैल तक एक्सप्रेसवे की मरम्मत करने वाली एजेंसी ने कार्य पूरा नहीं किया तो उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा।

नोएडा.ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का कार्य जनवरी 2021 से चल रहा है। इसका जिम्मा नोएडा प्राधिकरण ने इंफ्रा कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सौंपा है। इस कार्य को अब एक साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिसकी वजह से आम जनता को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर मरम्मत करने वाली कंपनी को काफी बार डेडलाइन भी जारी की है। उसके बावजूद भी कंपनी काफी धीमी गति से कार्य कर रही है। इसी के कारण नोएडा प्राधिकरण ने मरम्मत कार्य करने वाली कंपनी पर पहले लाखों का जुर्माना भी लगाया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मरम्मत करने वाली कंपनी अभी तक 4 डेडलाइन को मिस कर चुकी हं। जिसकी वजह से नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी काफी नाराज हैं। अब उन्होंने इसको लेकर कड़ा आदेश दिया है। ऋतु महेश्वरी ने मरम्मत का कार्य करने वाली एजेंसी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर आगामी 30 अप्रैल 2022 तक किसी भी हालत में एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ तो एजेंसी पर एक करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

केंद्रीय बजट निराशाजनक, किसानों व युवाओं को कुछ नहीं मिला : सिसोदिया

● कोविड-19 महामारी से नहीं ली सीख, हेल्थ-इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के नहीं बढ़ाया स्वास्थ्य बजट : वित्तमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

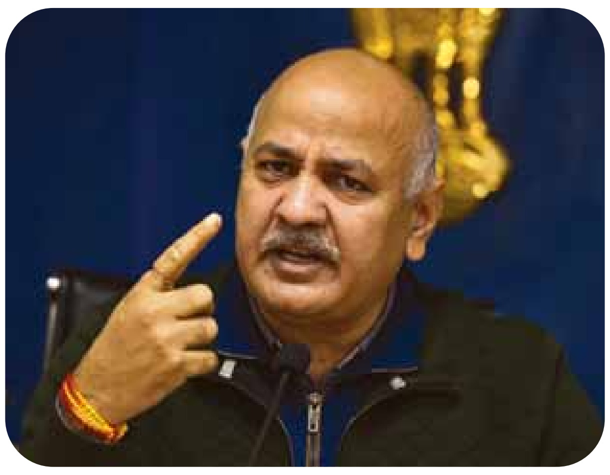

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया है। एमएसपी का पैसा कम कर दिया है।

पिछले साल एक करोड़ 97 लाख किसानों को इसका लाभ मिला था, मगर अब एक करोड़ 68 लाख किसानों को ही लाभ मिल सकेगा। पूरा देश कोरोना-19 महामारी से जूझ रहा है। मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार ने आंखें फेर ली है। बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। ऐसे माहौल में शिक्षा पर अधिक पैसा देने की जरूरत है। मगर शिक्षा का बजट कम कर दिया है। किसान विरोधी यह बजट किसानों के साथ-साथ रोजगार की तलाश करते युवाओं और मध्यवर्ग के भी खिलाफ है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह बजट कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के खिलाफ है।

कोविड-19 महामारी से सीख मिली कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर किया जाए लेकिन केंद्र सरकार ने बजट को ज्यों का त्यों ही रखा।

एक साल से अन्नदाता किसान एमएसपी की मांग करते हुए तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। दबाव में आकर केंद्र ने इन कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में किसान विरोधी बजट द्वारा किसानों को धोखा देने का काम किया है। इस बजट में एमएसपी का बजट जो पिछले साल तक कुल बजट का 2.48 लाख करोड़ था उसे घटाकर 2.37 लाख करोड़ कर दिया है।

एक ओर जहाँ केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रही थी, उसकी बजाय केंद्र कृषि का कुल बजट भी कम कर रहा है। पिछले साल तक कृषि का कुल बजट में 4.25 फीसद तक हिस्सा था उसकी जगह इस साल ये सिमट कर 3.84 फीसद ही रह गया है।

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति उदासीनता

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश 2 साल से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। महामारी के दौरान एक बहुत बड़ी सीख मिली कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की जरुरत है। लेकिन केंद्र सरकार ने हेल्थ-इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बजाय कठोरता के साथ उसपर से आँख फेर ली है और स्वास्थ्य बजट पिछले साल की तरह ज्यों का त्यों बना हुआ है।

निगम को नहीं दिया एक भी पैसा

केंद्र सरकार ने विभिन राज्यों के नगर-निगमों के लिए इस बजट में 69,421 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की, लेकिन दिल्ली नगर निगम में जहाँ भाजपा हमेशा पैसों का रोना-रोती है, उसे एक भी पैसा नहीं दिया। नगर निगम हमेशा यह दावा करती रही कि वो केंद्र से सीधे अपने लिए पैसे लेकर आएगी। दिल्ली के लिए भी केंद्र सरकार उदासीन बनी हुई है। केन्द्रीय करों में बाकि राज्यों को 42 फीसद की हिस्सेदारी मिलती है जबकि पिछले 21 सालों से दिल्ली सरकार को केवल 325 करोड़ ही दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय करों में सभी राज्यों की हिस्सेदारी के लिए आवंटित 8.16 लाख करोड़ के बजट में से दिल्ली को केवल 325 करोड़ देना दिल्ली के प्रति केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये है।

महंगाई कम करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं : केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट ने लोगों को मायूस किया है क्योंकि इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है उन्होंने ट्वीट किया कि करोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी। बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया।

शिक्षा को बेहतर बनाने की बातें निकली जुमला

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जबतक शिक्षा का बजट कुल जीडीपी का 6 फीसद नहीं होता है, तब तक इस पालिसी को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं की जा सकता। केंद्र सरकार शिक्षा का बजट साल दर साल कम करते जा रही है। पिछले साल शिक्षा बजट कुल बजट का 2.67 फीसद था। केंद्र सरकार ने उसे घटाकर इस साल 2.64 फीसद कर दिया। कोरोना की वजह से एजुकेशन सेक्टर को नुकसान हुआ, शिक्षा का घटता बजट शिक्षा के प्रति भाजपा की उदासीनता को दिखाता है।

मध्यम वर्ग की कमर तोड़ता बजट 2022

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग देश के अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। कोरोना के दौरान मध्यवर्ग की कमर टूटी पर उसे उम्मीद थी कि बजट में उसे आयकर को लेकर कुछ छूट मिलेगी। इससे न केवल मध्यम वर्ग को फायदा होता बल्कि उसकी क्रयशक्ति बढ़ती, और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती लेकिन केंद्र सरकार ने यहां भी मध्यवर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन्हें निराश करने का काम किया है।

अमृत महोत्सव का अमृत बजट : चौबे

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के बीच का यह अमृत बजट है। बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला है। सबका साथ-सबका विश्वास मूल मंत्र पर आधारित है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों व्यापारियों सभी का ख्याल रखा गया है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अन्य देशों की तुलना में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रही। वर्ष 2022-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। देश के विकास को और अधिक गति मिलेगी।

पुलिस को मिली 1701 करोड़ की अतिरिक्त राशि

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सातों दिन आठों पहर कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के मकसद से सम्मानित किया।

दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए इस बार के बजट में उसे 1701 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा मिले हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में जहां उसे 8654.26 करोड़ रुपये की राशि मिली थी तो वहीं वर्ष 2022-23 के बजट में 10355.29 करोड़ रुपए मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे दिल्ली पुलिस को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 के बजट में इस्टैब्लिशमेंट से संबंधित खर्च के लिए दिल्ली पुलिस को 9808 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 287 करोड़ रुपए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट में दिए गए हैं।

राशि से सीसीटीवी के अलावा विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे जिससे कानून व्यवस्था और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे साइबर हाईवे और डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सहित कुछ योजनाओं पर भी यह राशि खर्च की जा सकेगी। इसके अलावा 259 करोड़ रुपए पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मजबूत बनाने के लिए दिए गए हैं। इस राशि से ऑफिस की बिल्डिंग, रिहायशी बिल्डिंग, नए पुलिस मुख्यालय के रखरखाव का काम किया जाएगा। साथ ही नए घर बनाने पर यह राशि खर्च की जाएगी ताकि पुलिसकर्मियों के आवास की समस्या का समाधान हो सके।

दिल्लीवासियों के लिए जीरो बजट रहाः कांग्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए यूनियन बजट में दिल्ली के लिए कुछ नही दिया है।

बजट पूरी तरह से जीरो बजट है जिसमें आसमान छूती मंहगाई और कोविड संक्रमण के कारण आर्थिक मंदी झेल रही राजधानी के लोगों को कोई राहत नही दी है। पेट्रोल-डीजल सहित रसोई गैस की बढ़ती दरों में कमी और पेट्रोल और डीजल पर एक्साईज ड्यूटी में राहत की उम्मीद कर रहे दिल्लीवासी, बजट के बाद खाली हाथ रह गए है। केन्द्र सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी ने कीर्तिमान स्थापित किए है।

कैट ने वित्त मंत्री सीतारमण के बजट को दिए 10 में से 8 अंक

● व्यापारिक संगठन ने केंद्रीय बजट को एक प्रगतिशील आर्थिक दस्तावेज बताया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए केंद्रीय बजट को कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 10 में से 8 अंक देते हुए एक व्यापक और प्रगतिशील दस्तावेज बताया है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि बजट संरचित तरीके से प्रत्येक क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट व्यापार एवं लघु उद्योग के चरणबद्ध विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र और सेवाओं में मजबूत विकास के पैरामीटर्स को रेखांकित करता है और कुल मिला कर हम इसे एक संपूर्ण विकासशील बजट कह सकते हैं। 5 लाख करोड़ के साथ ईसीजीएल योजना के विस्तार, पीएलआई योजना को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने सहित कई नई घोषणाओं से न केवल छोटी विनिर्माण इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र को भी लाभ होगा।

गैंग रेप पीड़िता को दस लाख देगी सरकार

● फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीड़िता की मदद के लिए सरकार काबिल वकील नियुक्ति किया जाएगा

पीड़िता से मिले मंत्री कैलाश गहलोत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कस्तूरबा नगर में कथित रूप से गैंगरेप की शिकार 20 वर्षीय महिला के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक काबिल वकील की नियुक्ति करेगी। पिछले हफ्ते, पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर की सड़कों पर 20 वर्षीय महिला को उसके हमलावरों द्वारा कथित रूप से अपहरण, सामूहिक बलात्कार के बाद सार्वजनिक रूप से इलाके में घुमाया गया था। इस दौरान महिला के बाल कटे हुए थे, चेहरा काला किया गया था और उसके गले में जूते की एक माला डाली गयी थी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैंने इस बेटी की मदद के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार इस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, हर संभव कोशिश करेगी। हम उसके लिए अच्छा वकील नियुक्त कर रहे हैं। इस मामले को फास्ट ट्रैक भी करेंगे ताकि जल्द से जल्द बेटी को न्याय मिल सके।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है जबकि तीन नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने कहा था कि महिला पर 26 जनवरी को व्यक्तिगत रंजिश में हमला किया गया था।

कस्तूरबा नगर पहुंचे निहंगों को पुलिस ने लौटाया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विवेक विहार के कस्तूरबा नगर इलाके में 26 जनवरी को महिला के साथ हुई हैवानियत के मामले में जमकर राजनीति हो रही है।

सोशल मीडिया पर पीड़िता के सिख होने की बात कर इस मामले को तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी ऊहापोह के सोमवार देर रात को पंजाब से करीब 100 निहंग सिख कस्तूरबा नगर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसके हाथ-पैर फूल गए। तुरंत वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे और समझा-बुझाकर निहंगों को वहां से वापस भेजा।

मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित परिवार के कुछ वीडियो भी जारी किए जिसमें परिवार के सदस्य खुद को भेरकूट जाति और हिन्दू होने की बात कर रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस ने पूरे कस्तूरबा नगर इलाके की नाकाबंदी है। साथ ही स्थानीय पुलिस के अलावा इलाके में बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कस्तूरबा नगर में हुई वारदात के बाद कुछ शरारती तत्वों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए सोशल मीडिया पर लड़की को सिख बताकर उसके साथ जुल्म की झूठी बात फैलाना शुरू कर दी। इसमें कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी शामिल हो गए।

सोशल मीडिया पर हुए दुष्प्रचार के बाद पुलिस को सामने आकर ऐसा न करने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर हुए दुष्प्रचार के बाद सोमवार देर रात करीब 11 बजे बसों में सवार होकर करीब सौ से अधिक सिख निहंग कस्तूरबा नगर इलाके में पहुंच गए।

सभी पंजाब से दिल्ली पहुंचे थे। बाद में आला अधिकारियों ने समझा-बुझाकर इन सभी को वहां से भेजा दीया और उन्हें आसपास के गुरुद्वारों में ठहरने को कहा। इलाके में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए रात में ही पूरे इलाके की किलेबंदी कर दी गई।

● इलाके में सुरक्षा सख्त, स्थानीय पुलिस के साथ अर्द्धसैनिक बल तैनात

पुलिस ने पीड़ित परिवार का वीडियो ट्वीट कर हिंदू होने की दी जानकारी

शाहदरा जिला पुलिस ने पीड़िता की बहन और उसके नाना के वीडियो ट्वीट कर उसके हिन्दू होने की जानकारी मीडिया को दी। वीडियो में पीड़िता का नाना अपनी जाति भेरकूट और धर्म हिन्दू बता रहा है। उसकी छोटी बहन भी अपनी जाति व धर्म बता रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता सिख नहीं बल्कि हिन्दू है, कुछ शरारती तत्व मामले को सांप्रदायिक रंग देने के मकसद से सिख बता रहे हैं।

31 मार्च के बाद भी जारी रहेगी पुरानी आबकारी नीति

● याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में दी जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसकी 2021 की आबकारी नीति मार्च 2022 के बाद भी जारी रहेगी और अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आबकारी नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ को दिल्ली सरकार की ओर से यह जानकारी दी गयी।

शराब के एक थोक कारोबारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले में एक तात्कालिकता थी क्योंकि नीति समाप्त होने के साथ 31 मार्च के बाद सब खत्म हो जाएगा। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को सूचित किया कि नीति पिछले साल 16 नवंबर को लागू हुई और नीति की समाप्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का रुख सही नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अब कोई नया बदलाव नहीं होगा। यह जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी अंतरिम चरण में नई व्यवस्था के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप नहीं किया। अदालत ने सरकार के इस कथन को रिकार्ड में शामिल किया और सभी पक्षों को मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।

बुजुर्ग महिला हत्या मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत

दिल्ली दंगा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी अरुण कुमार और रवि कुमार को राहत दे दी, लेकिन मामले के तीसरे आरोपी विशाल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने में दर्ज अकबरी बेगम की हत्या के मामले में आरोपी अभियोजन का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला घर में थी, तभी भीड़ ने कथित तौर पर उन्हें आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष बताया परिवार के अन्य सदस्य खुद को बचाने के लिए छत पर चढ़ गए।

दुर्घटनावश गोली चलने से 3 वर्षीय बच्चा घायल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक महिला से दुर्घटनावश गोली चल गई, जिसमें तीन साल का बच्चा घायल हो गया।

उन्होंने कहा कि घटना शनिवार को हुई और पुलिस को रात करीब एक बजे एक अस्पताल से इस बारे में सूचना मिली, जहां घायल बच्चे को इलाज के लिए ले जाया गया था। पुलिस ने कहा कि बच्चे के बाएं कंधे में गोली लगी। उन्होंने कहा कि बच्चे की संबंधी 47 वर्षीय महिला ने घटना के बारे में झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने अपनी बहू तथा बच्चे की मौसी को बचाने के लिये ऐसा किया, जिसने दुर्घटनावश बच्चे पर गोली चला दी थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि महिला ने शुक्रवार को बताया था कि वह बच्चे के साथ अपनी बहन से मिलने शास्त्री नगर गई थी। बच्चे को वहां बेचैनी महसूस हुई और उसने दान सिंह नगर में स्थित अपने घर वापस जाने का फैसला लिया। अधिकारी ने कहा कि उसने बताया कि करीब 12 बजे जब वह बच्चे के साथ अपने घर की ओर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार दो लोग आए और उन पर गोलियां चला दीं और सराय रोहिल्ला फ्लाईओवर की ओर भाग गए। लड़के को गोली लगी। हालांकि, जब पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की।

शॉपिंग मॉल की पार्किंग में ई चर्जिंग को बढ़ावा

चार फरवरी को होगी गाइडबुक जारी, दिल्ली बनेगा पहला राज्य

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली (डीडीसी) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई) ईवी चार्जिंग गाइडबुक लॉन्च करेंगे।

डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट और विभिन्न शॉपिंग मॉल संघों के सदस्यों की ओर से 4 फरवरी को 11 बजे गाइडबुक लॉन्च की जाएगी।

इस तरह की मार्गदर्शिका शॉपिंग मॉल मालिकों को ईवी चार्जिंग के महत्व को समझने में सहायता करती है। इसके साथ ही ईवी चार्जिंग के अवसर का आंकलन और प्रभावी निर्णय लेने के लिए इससे जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी देती है। मॉल के पार्किंग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की योजना और कार्यान्वयन के लिए आगे का रास्ता तय करने में मदद करता है। दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ, अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की।

सिंगल-विंडो सुविधा की शुरुआत

शहर में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगवाने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा की शुरुआत की गई। सिंगल-विंडो की सुविधा ने दिल्ली में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। मॉल या किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में धीमे चार्जर न्यूनतम 2,495 रुपये में लगवाए जा सकते हैं।

इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा 100 या इससे अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ईवी चार्जर के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पांच फीसदी पार्किंग स्थान आरक्षित करने के निर्देश दिए गए।

ICICI Bank | शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वरा, आईसीआईसीआई बैंक के आधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया कि वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सभी नीलामीयां, जो **जनवरी 20, 2022** से **फरवरी 28, 2022** तक के बीच की अवधि में आयोजित की जानी निर्धारित थी, कोरोना वायरस (कोविड-19) के अभूतपूर्व प्रसार के कारण, अगली सूचना तक प्रास्थगित की जाती है। प्रास्थगित नीलामी की सूची यहां निचे दिया गया है:

क्र. सं.	मामले का विवरण	आस्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा	नीलामी की निर्धारित तिथि और समय
1.	सोम्या जैन (कर्जदार), LBNOD00002007549	सी-3/125, टावर-सी3, 12वीं मंजिल, अरावली हाइट्स, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, एरिया-1555 वर्ग फीट	रू. 31,00,000/-	रू. 3,10,000/-	फरवरी 05, 2022 सु. 11:00 बजे से
2.	धर्मेंद्र कुमार (कर्जदार)/ सुमिता सिंह (सह कर्जदार) LBNOD00002029333	सी-4/121, टावर- सी4 12वीं मंजिल, अरावली हाइट्स, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, एरिया- 1548 वर्ग फीट	रू. 31,00,000/-	रू. 3,10,000/-	फरवरी 05, 2022 सु. 11:30 बजे से
3.	धर्मेंद्र कुमार (कर्जदार)/ सुमिता सिंह (सह कर्जदार) LBNOD00002030018	डी-5/134, टावर- डी5, 13वीं मंजिल, अरावली हाइट्स, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, एरिया- 1207 वर्ग फीट	रू. 25,00,000/-	रू. 2,50,000/-	फरवरी 05, 2022 दो. 12:00 बजे से
4.	मांगे राम जैन (कर्जदार)/ अनामिका जैन (सह कर्जदार) LBNOD00002011506	डी-2/134, टावर- डी2, 13वीं मंजिल, अरावली हाइट्स, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, गुड़गाँव, एरिया-1207 वर्ग फुट	रू. 25,00,000/-	रू. 2,50,000/-	फरवरी 05, 2022 दो. 12:30 बजे से
5.	मांगे राम जैन (कर्जदार)/ अनामिका जैन (सह कर्जदार) LBNOD00002029715	डी-2/131, टावर- डी2, 13वीं मंजिल, अरावली हाइट्स, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, गुड़गाँव, एरिया-1207 वर्ग फुट	रू. 25,00,000/-	रू. 2,50,000/-	फरवरी 05, 2022 दो. 01:00 बजे से

तिथि : फरवरी 02, 2022
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

16 करोड़ के टीके से अब अयांश की सेहत में सुधार

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

करीब दो साल के बालक अयांश मदान को 16 करोड़ रुपये का टीका (वैक्सीन) लगने के बाद सेहत में सुधार के संकेत मिले हैं। अब वह ठीक से बैठने लगा है। शरीर का बैलेंस बन रहा है। यानी यह कहा जा सकता है कि 16 करोड़ रुपये की दवा का अयांश के शरीर पर सकारात्मक प्रभाव हो रहा है।

बता दें कि गुरुग्राम के प्रवीन मदान एवं वंदना मदान का बेटा अयांश जन्म से ही स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रॉफी (एसएमए) नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए

बैठने की क्षमता बढ़ी, अब एक मिनट तक बैठ जाता है बालक

हर सप्ताह टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं एम्स के डॉक्टर

अयांश को अमेरिका से आयात किया हुआ 16 करोड़ रुपये का टीका नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में चार दिसंबर 2021 को लगाया गया था। चार दिसम्बर 2021 को एम्स में चाइल्ड न्यूरो सर्जन डॉ. शैफाली गुलाटी के नेतृत्व में टीम ने अयांश को पूरी ऐहतियात बरतते हुए यह टीका लगाया। टीका लगने के एक माह के भीतर ही अयांश के शरीर में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। परिजनों द्वारा पूरी सावधानी के साथ उसे दवाएं दी जा रही हैं। साथ ही घर पर ही उसकी फिजियोथैरेपी की जा रही है।

अयांश पर माता-पिता हर समय रखते हैं नजर

अयांश के माता-पिता हर समय उस पर नजर रखते हैं। पिता प्रवीन मदान के मुताबिक अब अयांश के बैठने की क्षमता पहले से काफी मजबूत हुई। पहले वह मात्र कुछ सैकेंड ही बैठ पाता था। अब उसके बैठने का समय 15 मिनट तक हो गया है। पहले वह बैठाते ही एक तरफ लुढ़क जाता था। अब बैठाने के बाद वह झुक जाता है और खुद ही उठ जाता है। फर्क साफ है कि उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं।

खड़े होने के लिए बनाया है फ्रेम

उसे स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, इससे उसकी इम्युनिटी कम हो रही है। चिकित्सकों की सलाह पर ठंड को कोरोना की वजह से उसे घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा। पांवों को मजबूती देने के लिए फ्रेम बनवाया गया है ताकि वह खड़े होने में भी समर्थ हो सके। एसएमए बीमारी की वजह से उसके पैर भी टेढ़े होने लगे थे। चिकित्सकों का कहना है कि दवा लगने के 8-9 माह के बाद अयांश में अधिक शारीरिक बदलाव नजर आएंगे।

दो साल की उम्र तक लगाया जा सकता है टीका

डॉक्टरों के मुताबिक एसएमए से पीड़ित बच्चे को टीका मात्र दो साल की उम्र तक ही लगाया जा सकता है। एसएमएस बीमारी से शरीर का सकारात्मक विकास नहीं हो पाता। यानी इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं बन पाती। इस कारण उसमें उठने-बैठने, संभलने की क्षमता नहीं रहती। समय के साथ यह समस्या बढ़ती ही जाती है।

16 करोड़ का टीका लगने के एक महीने भीतर ही अपने सहारे मेज पर बैठा बालक अयांश।

किसी ने आशा तो किसी ने निराशावादी बताया आम बजट

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर लोगों की राय भिन्न है। किसी ने बजट को आशावादी तो किसी ने निराशावादी बताया। किसी ने इसे सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बताया तो किसी ने इसे देश के हर नागरिक के अनुकूल बताया। बजट पर हमने कुछ खास लोगों से बात कीं।

बजट में 25 साल के विकास का खाका: ओमप्रकाश धनखड़

आम बजट को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने आगामी 25 साल के विकास का बजट बताया है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, गरीबों को विकास की धारा में लाने, बेरोजगारों को रोजगार देने और बेघरों को छत देने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट देश की व्यवस्था को और मजबूत करने वाला बजट साबित होगा। इस बजट से साफ है कि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मोदी जी संकल्पित हैं। ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि वर्ष 2022-2023 के इस बजट में किसानों को एमएसपी के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला एतिहासिक है। एमएसपी पर किसानों की फसलों की रिकार्ड तोड़ खरीद हो सकेगी।

अनेक क्षेत्रों को मजबूती देगा बजट: सुधीर सिंगला

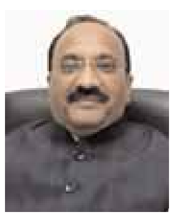

गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि आम बजट देश के हर नागरिक के लिए खास है। हर वर्ग का विशेष ख्याल इस बजट में रखा गया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रक्षा का, चाहे रेलवे हो या अन्य कोई क्षेत्र, सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। यह बात उन्होंने मंगलवार को घोषित किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहीं। विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में भी सरकार ने बजट को हर आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। यह ग्रोथ-ओरिएंटेड बजट पेश किया है, जिसमें प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

डिजिटल यूनिवर्सिटी शिक्षा ढांचा करेगी मजबूत: नवीन गोयल

पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की यह घोषणा देश के शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगी। अब छात्र शिक्षण संस्थानों तक नहीं बल्कि संस्थान छात्रों तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही अन्य कई बड़ी घोषणाएं करके देशवासियों को राहत देने का काम किया गया है। नवीन गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में जिस तरह से शिक्षा प्रभावित हुई, सभी जानते हैं। इसी दौर में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हुई। वर्चुअल शिक्षा का चलन शुरू हुई। यह आपदा में अवसर रहा। इसी अवसर को अब केंद्र सरकार द्वारा विस्तार दिया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो चुकी है।

यह बजट भविष्य का बजट है: अरविंद कुमार

भारत सरकार में एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि यह बजट भविष्य का बजट है। बजट में डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। बजट 2022 में डिजिटल क्षेत्र पर काफी फोकस दिया गया है। हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और सुविधाएं शुरू होंगी। इसमें किसानों को डिजिटल सेवाएं देने के साथ ही डिजिटल करेंसी से लेकर डिजिटल यूनिवर्सिटी, ई-पासपोर्ट, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल एप्लीकेशन, बैंकिंग और पोस्ट-ऑफिसेज में ऑनलाइन सुविधाएं जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। एपीआई आधारित कौशल क्रेडेंशियल्स के माध्यम से कौशल उप-स्किल, रिस्किल के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए डिजिटल पुश द्वारा इस सेक्टर में नौकरियों का सृजन भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।

कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को राहत देने वाला है बजट: बुवानीवाला

राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि केन्द्रीय बजट को आम जन, लघु-मझौले व खुदरा व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा जारी बजट अपनी पसंद के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को राहत देने वाला तथा बाकी सभी वर्गों को निराशा देने वाला है। केन्द्र सरकार को बताना चाहिए, ये देश का पैसा कहा जा रहा है। देश का लघु उद्योग भी केन्द्र सरकार से उम्मीदें लगाए बैठा था कि एमएसएमई में सुधार कर उनके उत्थान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया गया। व्यापारी नेता ने कहा कि केन्द्र सरकार अगर लघु एवं मझले उद्योगों के जरिए देश की आर्थिक रीढ़ सुदृढ़ करना चाहती है तो उसे बजट में प्राथमिकताएं देनी चाहिए थी।

जैसी उम्मीद थी वैसे बजट नहीं आया: डॉ. शुचिन बजाज

उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फाउंडर एवं निदेशक डॉ. शुचिन बजाज ने कहा कि जब हम पिछले साल बड़े पैमाने पर महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे थे, तो हमने सोचा था कि इस भयानक बीमारी का एकमात्र फायदा यह होगा कि देश में हेल्थकेयर सेक्टर की वर्तमान स्थिति सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचेगी। इससे हमें हेल्थकेयर सेक्टर में बजट में दिए जा रहे आवंटन में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। हेल्थकेयर का बजट सरकार बढ़ाकर जीडीपी का तीन प्रतिशत करेगी। हालांकि यह नहीं हो पाया है। दुर्भाग्य से हमने इस बजट में हेल्थकेयर और शिक्षा पर ज्यादा कुछ नहीं देखा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य टेली हेल्पलाइन शुरू की जा रही है।

बजट 2021 से लिया गया है बजट 2022: डॉ. तुषार ग्रोवर

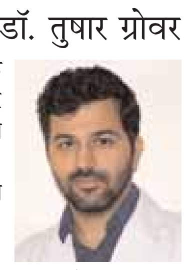

विजन आई सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. तुषार ग्रोवर का कहना है कि बजट-2022 विकास वाला बजट होने के साथ-साथ यह बजट-2021 से लिया गया है। गतिशक्ति के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जो ध्यान दिया गया है, वह मुख्य रूप से चार प्राथमिकताओं में से एक है। बजट पर सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर उठाया गया कदम सरकार के दीर्घकालिक उद्देश्य को दर्शाता है। भले ही महामारी अपना नकारात्मक रूप बरकरार किये हुए है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ईको सिस्टम के रूप में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से डिजिटल बनाने के प्रयास के साथ-साथ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की घोषणा एक अच्छा तथा स्वागतयोग्य कदम है।

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाला है बजट: डॉ. पायल

एमएम फाउंडेशन की ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में की गई घोषणाओं ने लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए संसाधन उपलब्ध और सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम न केवल दो लाख आंगनबाड़ियों को लाभ प्रदान करेगा, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास को भी सुनिश्चित करेगा। ऑनलाइन लर्निंग ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र को बदल दिया है। स्कूली बच्चों के लिए 200 टीवी चैनल, पीएम ई-विद्या की पहुंच का विस्तार और स्किलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल जैसी घोषणाएं निश्चित रूप से डिजिटल लर्निंग के भविष्य की नींव रखेगी।

स्वास्थ्य पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया: डॉ. प्रदीप

आम बजट-2022 पर प्रतिक्रिया में सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर के सीईओ डॉ. प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यह बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये निराशा भरा है। हेल्थकेयर इंडस्ट्री के लिये इसमें कुछ नहीं है। बजट में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और उपकरणों सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के लिए बहुत अधिक वादा नहीं किया है। सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए था। कोरोना महामारी से जूझते हुए हमने अनेक समस्याओं का सामना किया। ऐसे में जरूरी था कि बजट में चिकित्सा क्षेत्र को भी छूना चाहिए थे।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के छात्रों को टीका लगाने में गुरुग्राम अव्वल

गुरुग्राम। जिला में कोई भी हेल्थ केयर वर्कर व फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी व बूस्टर डोज से अछूता ना रहे, इसी उद्देश्य को लेकर मंगलवार को सिविल सर्जन डॉ डा. वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला में चल रहे टीकाकरण अभियान के मौजूदा कार्यों की समीक्षा करने के साथ साथ इसे और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। यह बैठक लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया कि स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से राजकीय विद्यालय के 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण करने में गुरुग्राम जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने 31 जनवरी तक के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि 10 जनवरी 2022 से जिला में 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक राजकीय विद्यालयों के 43172 बच्चों में से 41148 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने दोनो विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब आप लोगों की अथक मेहनत से गुरुग्राम जिला सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का शत प्रतिशत टीकाकरण करने वाला पहला जिला होगा। सिविल सर्जन ने बैठक में उपस्थित निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि जो भी स्कूल अपने परिसर में कोविड टीकाकरण का कैम्प आयोजित करना चाहते हैं। उन्हें स्वास्थ्य विभाग से तत्काल मंजूरी प्रदान की जाएगी। डॉ. यादव ने बैठक में उपस्थित सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के प्रमुख, निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों व फ्रंट लाइन में शामिल सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि वे अपने अपने विभागों में सभी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी व बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे सभी निजी अस्पताल जिन्होंने जिला में विभिन्न स्थानों पर वैक्सीन की पहली डोज़ के टीकाकरण कैम्प आयोजित किए थे, वे उन्हीं स्थानों पर पुन: वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए, दूसरा कैम्प भी लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि जिन नागरिकों की दूसरी डोज पेंडिंग है उनका जल्द से जल्द टीकाकरण किया जा सके।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आज मनाया जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड-डे

गुरुग्राम। बुधवार को वर्ल्ड वेटलैंड डे का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिले के सुल्तानपुर उद्यान में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर हरियाणा सरकार के वन एवं वन्य प्राणी विभाग, पर्यावरण विभाग तथा हरियाणा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय राज्यमंत्री अशोक कुमार चौबे विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। हरियाणा सरकार में वन, शिक्षा, पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति मंत्री कंवर पाल भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव लीना नंदन, हरियाणा के वन तथा पर्यावरण विभागों के एसीएस सिद्धीनाथ रॉय, हरियाणा के पीसीसीएफ तथा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जगदीश चंद्र, हरियाणा वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डा. विवेक सक्सेना उपस्थित रहेंगे। अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी के साथ नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर का अवलोकन भी किया जाएगा। मुख्य अतिथि तथा अन्य सभी अतिथि सुल्तानपुर पक्षी विहार में बर्ड वॉचिंग टूर करेंगे और वहां पर विश्वभर के विभिन्न देशों से आए पक्षियों को देखेंगे। हरियाणा की प्रथम रामसर साईट-गुरुग्राम जिला में सुल्तानपुर और झज्जर जिला में भिंडावास पर ब्रोशर भी जारी होगा। कार्यक्रम में पंचकूला में होने वाली ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट का प्रतीक चिन्ह भी जारी किया जाएगा।

कोहरे ने वाहनों की गति पर लगाए ब्रेक

मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर कोहरे का नजारा।

सोहना। मंगलवार को छाया कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र कोहरा अधिक होने से वाहन चालकों को परेशानियां हुई। सोमवार की देर रात से शुरू हुए कोहरे ने मंगलवार की सुबह होने का अहसास तक नहीं होने दिया। कोहरे की छाई चादर से सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति को धीमा कर दिया। पैदल चलने वालों को भी अपने से आगे दस कमद दूर के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया होने के कारण सूर्य देव के दर्शन तक नहीं होने दिया। उसके बाद कोहरा कम होता चला गया। कोहरा अधिक होने के कारण सर्दी की ठिठरन कम थी। सूर्य निकलने के बाद सर्दी का अहसास कम होता चला गया। वाहन चालकों को परेशानी: देर रात से कोहरा छा जाने से सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की गति पर ब्रेक लग गए। वाहन सड़कों पर रैंगते हुए चल रहे थे। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में कोहरा अधिक गहरा था। जिससे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर वाहन चालकों को काफी परेशानियां हुई। दिन निकलने के बाद भी वाहनों की लाइटों को जलाकर चलना पड़ा। किसानों को अपने खेतों में रास्ते तक दिखाई नहीं दे रहे थे। किसान भगत सिंह का कहना कोहरा से गेहूं व सरसों की फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर बने गड्ढे कोहरे के कारण दिखाई कम दे रहे थे।

स्वास्थ्य बीमा के साथ पाएं टैक्स में छूट का लाभ

पायनियर समाचार सेवा। मेरठ

भारत तेजी से तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य बीमा बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है क्योंकि यह इस बीमारी के कारण होने वाले अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि भारत सरकार भी लोगों को हेल्थ पॉलिसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए वह मेडिकल कवरेज प्रीमियम के खिलाफ टैक्स लाभ भी प्रदान करती है।

इसलिए मार्च के अंत तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से पहले, हेल्थ पॉलिसी का पुनः विश्लेषण, उनकी नवीनीकरण तिथियों का निरीक्षण और सबसे महत्वपूर्ण उनके खिलाफ टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए यह समय बिलकुल ठीक है। 2022 को एक स्वस्थ और समृद्ध नोट पर शुरू करने के लिए हम यहां विस्तार से इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य बीमा के साथ टैक्स छूट का सर्वोत्तम लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के हेल्थ इंश्योरेंस प्रमुख श्री अमित छाबड़ा ने कहा, 'स्वस्थ बीमा पॉलिसी, एक बार भुगतान करने पर दो गुना लाभ प्रदान करती है, अर्थात पॉलिसीधारक को बढ़ते चिकित्सा बिलों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ टैक्स लाभ भी मिलता है।'

उन्होंने आगे कहा, आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80क के तहत, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति को प्रीमियम पर पर्याप्त टैक्स छूट प्रदान करती है। इसके अलावा, यह केवल बीमाधारक तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों, यानी पति या पत्नी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए भी इसका लाभ उठाया जा सकता है, जिससे यह परिवार के लिए एक लाभकारी पॉलिसी साबित होती है। यह हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि वे भी भारत में खरीदी गई। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80क् के विभिन्न लाभों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-

1. स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चे

एक व्यक्ति अपने एवं अपने परिवार के लिए खरीदे गए स्वास्थ्य बीमा के तहत 25,000 तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है।

2. माता-पिता

माता-पिता के लिए खरीदे गए चिकित्सा कवरेज के मामले में उम्र बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, यदि बीमा धारक के माता.पिता की आयु 60 वर्ष से कम है, तो वह उच्चतम 25,000 प्रति वर्ष टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है। हालांकि, यदि वे 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो वार्षिक छूट राशि बढ़कर 50,000 हो जाती है। यह राशि पहले 30,000 थी, लेकिन केंद्रीय बजट 2018 में 60 और उससे अधिक (80 वर्ष से कम) आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था।इसमें एक तीसरा विकल्प भी होता है, जिसके अनुसार यदि माता-पिता और पॉलिसीधारक दोनों बताये गए वर्षों से अधिक हैं, तो दोनों के लिए अधिकतम छूट 1,00,000 तक बढ़ जाती है।

ब्लूरोज पब्लिशर्स की ये पांच पुस्तकें छू रही हैं पाठकों का दिल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हरि शंकर गुप्ता द्वारा लिखित देवत्व की ओर पुस्तक में हमारी आर्य सभ्यता और सनातन धर्म सभी धर्मों के प्रणेता हैं। ईस्वर अपनी आत्मा का एक अंश इस संसार में इस उद्देश्य से भेजता है कि योग के द्वारा संसार का उचित भोग करने से मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आत्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात जन्म चक्र से मुक्ति और मौत। मनुष्य स्वयं परमात्मा है। उसमें दिव्यता छिपी है और इस दिव्यता को उजागर करने के लिए आपको स्वयं का साक्षात्कार करना होगा।

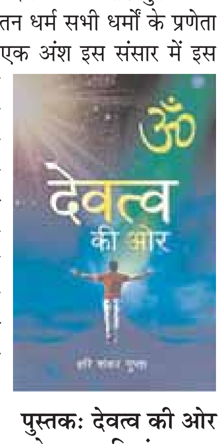

पुस्तक: देवत्व की ओर
लेखक: हरि शंकर गुप्ता

सुनील गोयल के द्वारा प्यार का सफर पुस्तक महज कुछ पेजों का संग्रह ही नहीं है। पुस्तक में जमीनी स्तर पर मानवीय भावनाओं को प्राथमिकता दी गयी है। कल बूढा हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, कोई छूट जाएगा, समय की हड़बड़ी में खो जाएगा, वही सिलसिला चलता रहेगा, आता रहेगा, इतिहास बिगड़ता रहेगा।

पुस्तक: प्यार का सफर
लेखक: सुनील गोयल

पुस्तक माही एक खुवाब में हिंदी पध्य और गद्य का एक संग्रह है। पुस्तक रवि कुमार द्वारा लिखित है। उनमें से ज्यादातर स्थितिजन्य कविताएं हैं जो घर बनाने वाली महिलाओं के लिए स्नेह, प्रेम और प्रशंसा के विषय पर आधारित हैं और आराध्य और प्रिय 'माही' के एक काल्पनिक चरित्र के लिए एक भावनात्मक तड़प है।

पुस्तक: माही एक खुवाब
लेखक: रवि कुमार

पुस्तक दूसरा पहलू निर्मला रावत द्वारा लिखी हुई है। पुस्तक 'दूसरा पहलू' (भाषा-हिंदी अंग्रेजी के एक छोटे से रंग के साथ) में पालन-पोषण और स्कूली शिक्षा के दूसरे पक्ष को दर्शाया गया है। पुस्तक सुंदर उद्धरणों, संदर्भों (विभिन्न लेखकों के), अंतर्दृष्टि, उपमाओं से भरी है। ऐसे उदाहरण जो विस्तृत करते हैं कि कैसे निर्णय या लेबल किसी बच्चे के संज्ञानात्मक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अशख्त वयस्क बच्चों को कमजोर करते हैं जो आगे जटिल व्यवहार पैटर्न में बदल जाते हैं या हम व्यक्तित्व विकार कह सकते हैं (जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है और हटाया जा सकता है)। एक बच्चे की बहुत ही साधारण जरूरतें यदि प्रारंभिक अवस्था में अधूरी रह जाती हैं, तो विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं और ऐसे पैटर्न को फिर से बना लेती हैं जो आत्म-विनाशकारी हो सकते हैं (उन अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए) पुस्तक लेखक के गहन अवलोकन, अनुभव, दृष्टि और जुनून का परिणाम है। और यह निश्चित रूप से माता-पिता-बच्चे के समीकरण को सुधारने में एक बड़ी मदद साबित होगी जहां बच्चे को एक समान माना जाएगा न कि अधीनस्थ के रूप में।

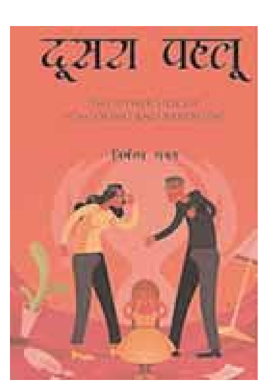

पुस्तक: दूसरा पहलू
लेखिका: निर्मला रावत

धीरज निहालंदे द्वारा लिखित पुस्तक जल्लाद एक महिला की भावनाओं को उजागर करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की देश में गति पर आधारित है। किसी अति संगीन जुर्म जैसे निर्भया के मामले की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित होना लाजमी है, लेकिन उस विशेष मामले में भी, एक किशोर को तीन साल बाद मुक्त कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि न्याय हुआ? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे देश में, विशेष रूप से छोटे शहरों और गांवों में सामाजिक कलंक के डर से एक महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाने वाले कई मामले दर्ज नहीं होते हैं।

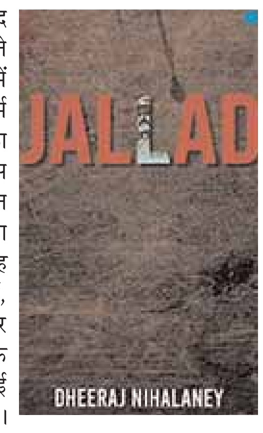

पुस्तक: जल्लाद
लेखक: धीरज निहालंदे

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 2 फरवरी , 2022

बसंत पंचमी : मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप

कविता। फरीदाबाद

बसंत पंचमी का त्योहार इस बार पांच फरवरी को मनाया जा रहा है, जिसे लेकर शहर में मां सरस्वती की मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। मूर्तिकार जल्द से जल्द मूर्तियां बना रहे हैं। जहां स्कूलों में बसंत पंचमी में मां की पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंदिरों में भी बसंत पंचमी की पूजा विशेष रूप से की जाती है।

जानकारी के मुताबिक हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार यानी सरस्वती पूजा मनाई जाती है। यह त्योहार इस वर्ष पांच फरवरी को मनाया जाएगा। इसकी तैयारी में मूर्तिकार लग चुके हैं। हिंदू धर्म में इस त्योहार का अत्यधिक महत्व है। माता सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। इस खास दिन पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। इसलिए विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इस दिन विधिपूर्वक इनका स्मरण व पूजा करने से भक्त को बुद्धि और विद्या का वरदान मिलता है।

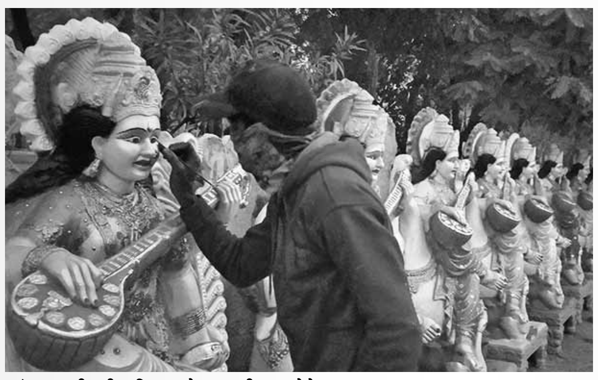

मां सरस्वती की प्रतिमा को आखरी टच देते कलाकार।

अंतिम रूप दे रहे हैं मूर्तिकार

विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा जिले में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके लिए सप्ताह भर पहले से तैयारियां की जाती है। मूर्तिकार भी मूर्ति निर्माण करने में लग चुके हैं। मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार कोरोना के कारण अधिकतर छोटी प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। सरस्वती पूजा को लेकर कुछ मंदिरों में भी मूर्तियों को बनाने में मूर्तिकार जुटे हुए है। वहीं सड़क किनारे मौजूद छोटे-छोटे मूर्तिकार मूर्तियां बना रहे है। इसी कड़ी में सेक्टर-55, अजरौंदा और मेट्रो मोड़ और नहरपार इलाके में सड़कों के किनारे मूर्तिकार मूर्तियां तैयार करने में तेजी के साथ जुटे हुए हैं।

बसंत मौसम शुरुआत का संकेत

यह त्योहार बसंत मौसम की शुरुआत का संकेत होता है। बताया गया कि बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है और इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। यानि कि इस दिन में किसी भी अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इस दिन परिवार में छोटे बच्चों को पहली बार किताब और कलम पकड़ाने की भी मान्यता है। विद्या का आरंभ करने के लिए ये दिन सबसे शुभ माना गया है।

18 साल से फरार हत्यारोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की पुलिस टीम ने हत्या के मामले में 18 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपी बाबूलाल फरीदाबाद के फरीदपुर गांव में रहता है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी ने दिसंबर 1999 में आपसी रंजिश के कारण अन्य आरोपी ने के साथ मिलकर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने उपरांत आरोपी ने हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। जमानत मिलने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान कभी उपस्थित नहीं हुआ।

कर्मचारियों की रैली ने किया शहर का चक्का जाम

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बीके चौक से एक-दो चौक होते हुए बड़खल तहसील पर ज्ञापन देकर किया गया रैली का समापन

आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर यूनियन की हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में व चंडीगढ़ बिजली विभाग को पूंजीपतियों के हवाले करने के विरोध में मंगलवार को सीटू और सर्व कर्मचारी संघ के हजारों कर्मचारियों ने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। मंगलवार के आक्रोश, प्रदर्शन से पहले नगर निगम बीके चौक पर कर्मचारियों ने विशाल सभा की।

इस सभा की अध्यक्षता सीटू के प्रधान निरन्तर पाराशर और सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव बलवीर बालगुहेर ने की। संचालन सीटू के जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह डंगवाल ने किया। सभा के बाद कर्मचारियों ने बीके चौक से तिकोना पार्क बस स्टैंड होते हुए एक नंबर मार्किट तथा 1-2 के चौक पर प्रदर्शन कर बड़खल तहसील पर भी प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य अध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आंगनवाड़ी वर्करों एवं हैल्परों के खिलाफ दमनकारी नीतियों का अपनाना बंद नहीं किया तो प्रदेश में आन्दोलन को तेज कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल 8 दिसम्बर से चल रही है। हड़ताल का मंगलवार को 56वां दिन था। सरकार मांगों को लागू करने के बजाय हड़ताली वर्करों एवं हैल्परों की बर्खास्त कर रही है। सैकड़ों वर्करों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रही है। यह सारे ओछे हथकंडे हड़ताल को कमजोर करने के लिए अपनाने जा रहे है, लेकिन सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्यवाही से हड़ताल नहीं हो रही है। सभी कार्यकर्ताओं के हौंसले बुलंद है।

कर्मचारी झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। प्रदेश की सरकार को दमन का रास्ता छोड़कर इनकी मांगों को लागू करना चाहिए। प्रदर्शन को सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव बल्लभगढ़ के सुभाष देशवाल, अध्यापक संघ के जिला प्रधान भीम सिंह, आशा वर्कर यूनियन के जिला सचिव सुधापाल, नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान गुरचरण खाड़ियां, सीटू के नेता ओमप्रकाश, रिटायर कर्मचारी संघ के राज्य के नेता यूएम खान, किसान संघर्ष समिति के प्रधान सतपाल नरवत, मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन के राज्य कमेटी के हितेश शर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर्ज यूनियन की राज्य प्रधान देवेन्द्री शर्मा, जिला सचिव मालवती, मिडे-डे-मील की जिला प्रधान कमलेश, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान देवीराम, जिला सचिव दिनेश पाली, मुकेश बेनीवाल, राजकुमार, पूरन दहिया, हेमलता आदि ने सम्बोधित किया। मांग की है कि मुख्यमंत्री के साथ 29 दिसम्बर को मांगों को लेकर मीटिंग में लिए गए निर्णय लागू किया जाएं।

वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्करों के वेतन में 1500 सौ की बढ़ोतरी और हैल्पर के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोत्तरी लागू करने, वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री के द्वारा 10 वर्ष की सेवाकाल के बाद कुशल एवं अकुशल को घोषणा को लागू किया जाये, वरिष्ठता के आधार पर वर्करों को सुपरवाईजर पदोन्नत किया जाये, प्ले व स्कूलों के नाम पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का निजीकरण बंद किया जाये। महंगाई भत्ते की किस्तों को मानदेय में जोड़कर एरियर का भुगतान किया जाये। दमन विरोधी दिवस में अन्य के अलावा कर्मी नेता सुभाष देशवाल, मुकेश बेनिवाल, मा. भीम सिंह, सुधापाल, गुरचरण खाण्डिया, ओमप्रकाश, कमलेश, देवीराम, बल्लू चिण्डालिया, विजय चावला, राकेश चिण्डालिया, कृष्णा चिण्डालिया भी शामिल थे।

मार्केट में रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन करते कर्मचारी।

युवाओं की प्रेरणा स्त्रोत है कल्पना चावला

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनआईटी तीन फरीदाबाद की जूनियर रेडक्रॉस, गाइड्स और सैंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड ने प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा की अध्यक्षता में कल्पना चावला को युवाओं की प्रेरणा स्त्रोत बताया। विद्यालय की सैंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड और जूनियर रेडक्रॉस प्रभारी प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने कहा कि 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया था। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार सातों यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे थे और सबसे सफल कहा जाने वाला यह अभियान समाप्त हो गया।

इसी दुर्घटना में अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला व नासा वैज्ञानिक कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष और खगोलीय विज्ञान में बहुत अधिक रुचि थी। वे अपने पिता से पूछा करती थीं ये अंतरिक्षयान आकाश में कैसे उड़ते हैं क्या मैं भी उड़ सकती हूं और पिता हंसकर उनकी बातों को टाल दिया करते परंतु सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता।जब वे छत पर सोते थे तो उनकी छोटी बेटी कल्पना चावला तारों को देखती थी और चमकते समूहों के बारे में पूछती थी। कल्पना को बचपन से ही लंबी दूरी की पैदल यात्रा और पढ़ने के साथ-साथ हवाई जहाज में भी रुचि थी अपने इन्हीं सपनों की उड़ान भरने के लिए कल्पना 1982 में अमेरिका गईं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री ली। 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में सम्मिलित हुई और 1998 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। प्राचार्य मनचंदा ने कहा कि कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थीं जो नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में सम्मिलित हुईं। अपने पहले मिशन में कल्पना ने 1.04 करोड़ मील दूरी तय कर पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए।

कल्पना चावला की पुण्य तिथि पर एनएचतीन सरकारी स्कूल की छात्रा द्वारा बनाई गई पेंटिंग।

7वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों वैक्सीन लगाने के दिए आदेश

बैठक में दिए सीआरसी और एबीआरसी को निर्देश: डीईओ

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला के सभी स्कूलों में 15 से अधिक आयु के सातवीं से बारवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण के बचाव का कोविड वैक्शीनेशन करवाना सुनिश्चित हो। यह वैक्शीनेशन सरकार द्वारा जारी कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए जरुरी है।

जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने सभी सीआरसी को वैक्सीनेशन कक्षा सातवीं से 12वीं तक 100 फीसदी बच्चों को करवाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में खंड कार्यालय बल्लभगढ़ में सीआरसी बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी बलवीर कौर ने दी। इस बैठक में सभी सीआरसी को वैक्सीनेशन कक्षा सातवीं से 12वीं तक 100 प्रतिशत करवाने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा स्कूलों में विद्यार्थियों की वैरीफिकेशन की यूसी भिजवाने, स्कूल मुखिया अपनी सीआरसी में आने वाले सभी विद्यालयों में विजिट के लिए अवश्य जाएं। एमआईएस पर सेट-3 के मार्क्स 100 फिसदी अपलोड करवाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग किया जाएं। एवं विद्यार्थियों को बाहर धूप में न बिठाया जाएं। कक्षा कक्ष का प्रयोग किया जाए। इन कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

बल्लभगढ़ खण्ड शिक्षा कार्यालय में सीआरसी की बैठक में भाग लेते टीचर्स।

59 दिनों बाद फिर से विद्यालयों में लौटी रौनक

जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी स्कूलों का निरीक्षण करते हुए।

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला के स्कूलों में 59 दिनों के बाद आज सोमवार को रौनक लौट आई है। जिला में 10वीं से 12वीं कक्षाओं में 30430 विद्यार्थियों ने स्कूलों में सोमवार को पहुंचे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने बताया कि गत सोमवार को 10 वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूलों के खुलने से 59 दिनों के लंबे समय बाद स्कूलों में विद्यार्थियों की चहल पहल की रौनक देखने को मिल रही है। छात्र-छात्राएं स्कूल पहुंचे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिला के सभी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश दिए हैं। कि वे अपनी वैक्सीन लगवाने की रिपोर्ट अवसर एप पर भरें। जिन विद्यार्थियों और शिक्षकों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सीएचसी, स्कूल स्तर पर वेक्सीनेशन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने बताया कि यह उपस्थित कोविड-19 कोरोना वायरस काल के चलते 9709 विद्यार्थी दसवीं कक्षा के, 12447 विद्यार्थि ग्यारहवीं कक्षा और 8274 विद्यार्थि बारवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने स्कूलों में शिरकत की। उन्होंने बताया कि देखी जाए तो यह विद्यार्थियों की उपस्थिति संतोषजनक है। उन्होंने बताया कि परंतु सभी स्कूलों को यह कहा गया है कि उपस्थिति 100 प्रतिशत करने पर जोर दें।

स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही भाजपा : सिंगला

युवा कांग्रेसियों ने दी स्व. रणवीर सिंह हुड्डा को विनम्र श्रद्धांजलि

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

भारत के संविधान सभा के सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी स्व. रणवीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को जिला युवा कांग्रेस (शहरी) अध्यक्ष नितिन सिंगला के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-17 स्थित स्व. रणवीर सिंह हुड्डा पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा को गंगाजल से साफ किया। माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्व. रणवीर सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन सिंगला ने कहा कि स्व. रणवीर सिंह हुड्डा एक युगपर्वतक, गांधीवादी व किसानों-मजदूरों के मसीहा थे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से आम आदमी की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शो को हमें अपनाना चाहिए तभी एक सशक्त समाज का निर्माण संभव हो सकता है। नितिन सिंगला ने कहा कि स्व. रणवीर हुड्डा के उनके द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि हम आजादी की खुली हवा में सांस लें रहे है। इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए समाजसेवा व जनसेवा के कार्यो में अपनी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि समाज से बुराईयों का अंत हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने पर तुली है।

उन्होंने स्व. रणवीर सिंह हुड्डा पार्क में व्याप्त अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले इस पार्क को बेहतर तरीके से सुसज्जित किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस पार्क में विकास के नाम पर एक ईट भी नहीं लगी, जो सरकार को प्रशासन की लचर कार्यशैली को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि अपने पिता स्व. रणवीर सिंह हुड्डा के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रदेश की जनता की आवाज बनकर सडक़ से लेकर विधानसभा तक भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जनता जनार्दन के हकों के लिए संघर्ष कर रहे है।

स्वतंत्रता सेनानी स्व. रणवीर सिंह हुड्डा को श्रद्धांजलि देते कांग्रेसी।

वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है अनेक योजनाएं

फरीदाबाद। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों के सदस्यों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है।

उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंकों के सहयोग से इन परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार रूपए तथा शहरी क्षेत्रों में 60 हजार रूपए तक है उनका नाम बीपीएल सर्वेक्षण सूची में शामिल हैं, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे- पशु पालन, हथकरघा, किरयाने की दुकान, कपड़े की दुकान, ई-रिक्शा/साईकल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाना, चमड़ा और चमड़े के कार्य, फोटोग्राफी तथा ई-रिक्शा इत्यादि योजनाओं के लिए डेढ़ लाख रूपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

संक्षिप्त समाचार

कोरोना: 224 मिले संक्रमित, 690 हुए ठीक

फरीदाबाद। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने केवल 224 नए संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि की है। वहीं 690 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है। जिले में 12वें दिन मंगलवार को किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। वर्ना पिछले कुछ समय से एक से दो पॉजिटिव मृतकों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 124152 हो गई है, जिसमें से 120291 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी तक जिले में 736 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें से 562 ऐसे थे, जो कोरोना के साथ दूसरी गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त थे। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामभगत ने बताया जिले में अब कोरोना के 3125 एक्टिव केस रह गए हैं। इनमें से 3019 घरों में दाखिल हैं, जबकि 106 को अस्पतालों में दाखिल किया गया है। अस्पतालों में दाखिल 15 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं, 21 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण के साथ दूसरी गंभीर बीमारियां भी हैं। इनमें से पांच मरीज वेंटिलेटर पर हैं। डॉ. रामभगत ने बताया कि अब जिले में कोरोना का एक्टिव केस रेट ढाई प्रतिशत के आस - पास पहुंच गया है। रिकवरी रेट 97 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 4032 नए सैंपल लिए गए हैं। अभी 2927 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है।

नहर में कूदी लड़की की पुलिस टीम ने बचाई जान

फरीदाबाद। थाना सेक्टर-8 प्रबंधक इंस्पेक्टर-नवीन कुमार ने अपनी टीम पुलिस चौकी सेक्टर-8 के साथ नहर में कूदी हुई लड़की जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है। लड़की मूलरूप से बिहार की रहने वाली है और अभी लड़की अपने परिजनों के साथ सीही गांव सेक्टर-8 में रह रही है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम करीब आठ बजे पुलिस चौकी सेक्टर-8 में लड़की के नहर में कूदने की सूचना मिली। जिसपर तुरन्त अमल करते हुए चौकी इंचार्ज, मुख्य सिपाही सतीश कुमार, मुख्य सिपाही ज्योतिप्रसाद और सिपाही राकेश मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस टीम ने देखा की लड़की नहर में कूदी है। लड़की को निकालने के लिए मुख्य सिपाही ज्योतिप्रसाद साथी पुलिस कर्मियों की सहायता से नहर में उतरकर लड़की को निकाला। लड़की को तुरन्त प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी हस्पताल बल्लभगढ़ ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद लड़की से पूछताछ कर उसके परिजनों से सम्पर्क किया गया। लड़की ने बताया कि उसका झगड़ा उसके दोस्त से हो गया है। जिसके बारे लड़की के घर वालों को नहीं पता था। लड़की को परिजनों के हवाले सकुशल किया गया। लड़की के परिजनों ने पुलिस टीम का तहेदिल से धन्यवाद किया।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बिहार से गिरफ्तार

फरीदाबाद। महिला थाना एनआईटी की टीम ने पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी अमरजीत को बिहार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अमरजीत उत्तर प्रदेश के गांव लठूडीह जिला गाजिपूर का रहने वाला है। फरीदाबाद के दयाल नगर में किराए के मकान पर रह रहा था। मई 2021 को आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत महिला थाना एनआईटी में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमे आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अपने गांव लठूडीह जिला गाजिपूर चला गया था। इस मामले में आरोपी को भगोड़ा घोषित किया हुआ था। जिसके खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। आरोपी को पकड़ने के लिए महिला थाना एनआईटी फरीदाबाद की प्रबंधक थाना इस्पेक्टर माया के दिशा-निर्देश अनुसार टीम गठित की गई। पुलिस टीम में शामिल अनुसंधान अधिकारी स्ढ्ढ जितेन्द्र, सोनिका और सिपाही सुमित के द्वारा आरोपी के गांव में तीन बार दबिश दी। आरोपी पहली दो रेड में पुलिस के हाथ नही लगा। महिला थाना एनआईटी की टीम एएसआई सोनिका और एएसआई जितेंद्र ने तीसरी रेड में पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर फरीदाबाद लाया गया है। आरोपी से पूछताछ पूरी करने के पश्चात आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया ।

एसीसी ने यूके स्पोर्ट्स को सात विकेट से हराया

फरीदाबाद। 17वें रविंद्र फागना मिक्स कॉरपोरेट क्रिकेट लीग सेमीफाइनल मैच में एसीसी क्रिकेट क्लब ने यूके स्पोर्ट्स इलेवन को 7 विकेट से हराया। यह मुकाबला रविंद्र फागना क्रिकेट अकादमी स्थित मैदान पर खेला गया। इस मौके पर बीसीसीआई कोच धर्मेन्द्र फागना ने बताया कि यह मैच 20-20 ओवर का था। ये मैच एसीसी क्रिकेट क्लब और यूके स्पोर्ट्स इलेवन के साथ खेला गया। एसीसी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया और यूके स्पोर्ट्स टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 20 ओवर में छह विकेट पर 152 रन बनाए। टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए संती ने 52 रन, मुकुल ने 35 रन, करण डेढ़ा ने 31 रन, शुभम ने 14 रन बनाए। एसीसी क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए गौरव सिंह ने दो विकेट , साहिल दत्ता ने एक विकेट ली और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एसीसी क्रिकेट क्लब की टीम ने 16.3 ओवर में तीन विकेट पर 153 रन बनाकर जीत हासिल की। टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए गौरव डुडेजा ने 59 रन, साहिल ने 32 रन, विक्रम धारीवाल ने 23 रन, भावेश ने 12 रन बनाए। यूके स्पोर्ट्स की और से गेंदबाजी करते हुए राजेश ने दो विकेट , मनन ने एक विकेट ली। मैन ऑफ दा मैच गौरव डुडेजा को दिया गया।

गांजे की तस्करी में दो गिरफ्तार

फरीदाबाद। डीसीपी क्राइम नरेद्र कादियान ने अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश पर क्राइम ब्रांच एनआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हरबीर और बृजेश उर्फ फौजी को थाना मुजेसर क्षेत्र से काबू किया है। गिरफ्तार आरोपी हरबीर उत्तर प्रदेश के गांव मिलकपुर जिला सिकंदराबाद हाल जीवन नगर पार्ट, मुजेसर और बृजेश उर्फ फौजी उत्तर प्रदेश के गांव ओबरा जिला आजमगढ़ हाल संजय कॉलोनी मुजेसर फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच टीम ने सुत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी हरबीर और बृजेश उर्फ फौजी को 1.155 किलोग्राम गांजा पत्ती सहित थाना मुजेसरक्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियो के खिलाफ थाना मुजेसर में अवैध नशा तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे किसी महिला से गांजा पत्ती खरीदकर लाते हैं जो गांजा पत्ती को मोटरसाईकिल की सहायता से आने-जाने वाले लोगों को पुड़िया बनाकर बेच देते हैं। आरोपी 8-9 महिने से गांजा पत्ती बेच रहे हैं। आरोपियों से मौके पर 1.155 किलोग्राम गांजा और 4380 रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोपियों ने बताया कि आरोपी मच्छी मार्कीट में गांजा पत्ती बेचते हैं। मच्छी मार्किट से पुलिस ने आरोपी आशीष और मृत्क लाला की मां को गांजा पत्ती बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

डालसा चलाया ने जागरूकता अभियान

फरीदाबाद। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डालसा टीम के पैनल अधिवक्ताओं ने आज मंगलवार को कानूनी जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को विभिन्न कानूनी पहलुओं पर जागरूक किया गया। सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में डोर टू डोर जागरूकता अभियान के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लोगों को नालसा, हालसा और डालसा की विभिन्न कानूनी जागरूकता योजनाओं से अवगत कराया गया। लोगों को कोविड -19 वैश्विक महामारी संक्रमण के बचाव के लिए उचित सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया। उन्होंने बताया कि कानूनी जागरूकता अभियान के तहत एनआईटी में शिविर आयोजित कर लोगों को मध्यस्थता के लाभों के बारे में शिक्षित करने, पीड़ित मुआवजा योजना,माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा भावना तथा उनका सामाजिक सरोकार के कल्याण बारे जागरूक किया।

न्यायिक पारदर्शिता

सजीव प्रसारण

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बार फिर अदालती कार्यवाहियों की वीडियो स्ट्रीमिंग पर जोर दिया है। इससे लोगों को अदालत की कार्रवाई देखने का मौका मिलेगा। इससे जज और वकील लगातार निगरानी में रहेंगे। इस कदम से दोनों पक्षों को एक दूसरे के सरोकार बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। भारत में पांच उच्च न्यायालयों ने अदालती कार्यवाहियों को रिकार्ड करना शुरू कर दिया है जो यूट्यूब या अदालत की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। जून में सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी ने अदालती कार्यवाहियों की रिकार्डिंग तथा लाइव स्ट्रीमिंग के नियमों का प्रारूप पेश किया। जस्टिस चंद्रचूड़ का प्रस्ताव इस मुद्दे पर बहस में योगदान करेगा। भारत में टीवी का पर्दा आमतोर से मनोरंजन का साधन है, चाहे वह स्किट, सीरियलों, सिनेमा या यहां तक खबरों के रूप में हो। अदालती कार्यवाहियों को इसी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। उनसे पता चलता है कि 25 उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में बिना पूर्वाग्रहों के न्याय की प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। कुछ लोगों का तर्क है कि अदालती कार्यवाहियों के खुलेपन में कुछ जोखिम भी है। लेकिन इसके साथ जुड़ा तर्क यह भी है कि न्यायिक प्रक्रिया देखने से हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि कानूनों की स्वतंत्र व्याख्या करने तथा संविधान की रक्षा करने में न्यायपालिका किस प्रकार योगदान करती है। लेकिन इसके साथ ही हमें समझना होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय संदर्भ में अदालती कार्यवाहियों को सजीव करने की जटिलताओं पर भी गंभीरतापूर्वक विचार

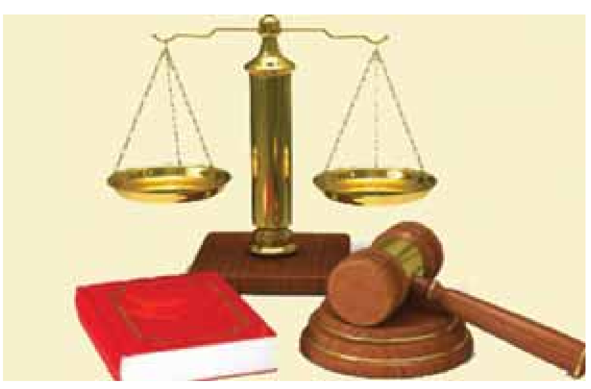

किया होगा। सबसे ड़ी संभावना किसी संवेदनशील मामले में सुनवाई पर दर्शकों का ध्रुवीकरण हो सकता है।

निर्भया, सबरीमाला या अयोध्या जैसे मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की समस्यायें समझी जा सकती हैं। ऐसे बहुसंख्य मामले संवेदनशील होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पक्षों के बीच औद्योगिक, संपत्ति संबंधी या वैवाहिक विवाद हो सकते हैं जिनमें निजता की आवश्यकता होती है। जासूसी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले स्वाभाविक रूप से एक अपवाद होंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक या अन्य समकालीन मुद्दों का एक छोटा हिस्सा ही वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए खुला होगा। हमारी भाषाई, क्षेत्रीय या उप-राष्ट्रीय विविधता के कारण भी अनेक प्रकार के नियंत्रण और अपवाद होंगे। इसी तरह शुरुआती वर्षों में कम से कम पूरी कार्यवाही का सजीव प्रसारण संभव नहीं होगा। प्रमाण संबंधी सुनवाइयां भी समान रूप से जटिल होती हैं। उनमें अनेक प्रकार के चश्मदीदों की गवाहियां शामिल होती है, अत: गवाहों की पहचान गुप्त रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर वीडियो स्ट्रीमिंग का सर्वाधिक सकारात्मक हिस्सा 'तारीख पर तारीख' लेने के दृष्टिकोण को हतोत्साहित करेगा और लोग लगातार जनता की नजर में रहेंगे। ऐसे में कैमरों के सामने सुनवाई लंबी खींचने के प्रयास विभिन्न पक्षों के लिए लाभदायक नहीं होंगे। अदालती कार्यवाहियां देखने से लोगों के मन में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पैदा होगी तथा उनमें जजों व वकीलों के प्रति व्याप्त भय कम होगा। रिकार्डिंगों की उपलब्धता से जजों की मौखिक टिप्पणियों तथा गवाहों के बयानों की गलत व्याख्या के जोखिम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ यह तथ्य भी है कि उनके शब्द व कार्रवाइयां देखने के कारण विधि कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की ड्रेस व व्यवहार को प्रभावित करेगा। कैमरों में जजों के हावभाव भी दिखेंगे।

आय में असमानता के मूल कारण

बिजनेसों की प्रकृति या अन्य क्षेत्रीय जुड़ाव चाहे जो हों, उनके ढांचे के परिणामस्वरूप स्वामियों के हाथों में संपत्ति का संकेद्रण होता रहता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक नीति विश्लेषक एवं स्तम्भकार हैं)

इस माह के प्रारंभ में डावोस में विश्व आर्थिक मंच का एजेंडा सामने आने के पहले आक्सफैम की रिपोर्ट 'इन्क्वीलिटी किल्स' जारी हुई। इसके अनुसार, 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपदा 5,700,000 करोड़ रुपये या 775 बिलियन डालर हो गई तथा भारत में अरबपतियों की संख्या भी 102 से बढ़ कर 142 हो गई। वैश्विक महामारी के दौरान इन अरबपतियों की संपदा में मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच 2,300,000 करोड़ या 313 बिलियन डालर की वृद्धि हुई। इसके साथ ही 84 प्रतिशत परिवारों की आय घटी तथा नीचे के पचास प्रतिशत लोगों का राष्ट्रीय संपदा में हिस्सा घट कर केवल 6 प्रतिशत रह गया। 2020 में 46 मिलियन से अधिक भारतीय अत्यधिक गरीबी की स्थिति में पहुंच गए जो दुनिया में नए गरीबों का लगभग आधा है। यह समझना जरूरी है कि केवल वैश्विक महामारी के कारण असमानतायें नहीं पैदा हुईं, बल्कि ये पहले से थीं।

आक्सफैम द्वारा डब्लूईएफ की जनवरी, 2020 में पचासवीं बैठक से पहले जारी 'टाइम टु केयर' रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों की संपदा 953 मिलियन लोगों की संपदा की चार गुनी थी जो जनसंख्या के सबसे नीचे के 70 प्रतिशत लोग थे। इसके साथ ही भारत के 63 अरबपतियों की कुल संपदा वित्त वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय बजट से अधिक थी। लोगों की आय अपरिहार्य रूप से देश की जीडीपी से जुड़ी है। आय में असमानता के कारण दो स्थितियां बन सकती हैं। 1. बढ़ती जीडीपी के बावजूद पिरामिड के शिखर पर बैठे एक प्रतिशत लोगों की आय की तुलना में जनसंख्या के बहुसंख्य हिस्सों की आय में बहुत धीमी वृद्धि हो। 2. घटती जीडीपी की स्थिति में अमीरों की तुलना में बहुसंख्य जनता की आय में गिरावट ज्यादा तेजी से हो। हालांकि, दूसरा परिदृश्य विरले ही सामने आता है, पहला काफी सामान्य है।

घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए एक चीज पर गौर करें। यदि जीडीपी में एक रुपये की वृद्धि होती है तो इसका 80 प्रतिशत ऊपर के एक प्रतिशत लोगों के पास जाएगा, नीचे के 70 प्रतिशत लोगों को 6 पैसे मिलेंगे तथा बाकी 14 पैसे 71-99 प्रतिशत जनसंख्या के बीच बंटेंगे। इस अत्यधिक विकृत वितरण के कारण यदि जीडीपी में 10 प्रतिशत वृद्धि होती है तो भी ऊपर के एक प्रतिशत को 8 रुपये मिलेंगे, जबकि नीचे के 70 प्रतिशत लोगों को केवल 60 पैसे से संतोष करना होगा।

उच्च वृद्धि दर के पैरोकारों द्वारा हमें विश्वास दिलाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यह तथ्य है कि उसका लाभ ऊपर बैठे कुछ लोगों को मिलेगा, जबकि पिरामिड में नीचे के बहुसंख्य लोगों को बहुत कम मिलेगा। यह बिजनेसों की योजना का अंतर्निहित हिस्सा है। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा ऐसे नीतिगत परिवेश से होती है जहां निवेशकों को अपने निवेश पर आकर्षक दर पर मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है। यह आकर्षक दर क्या होगी, इसे आमतौर से परिभाषित नहीं किया जाता है। हालांकि, बिजली व उर्वरक जैसे क्षेत्रों में यह न्यूनतम मुनाफे की ही गारंटी करती हैं। इस प्रकार स्तर चाहे जो हो, उच्च दर 'आकर्षक' की श्रेणी में आती है। अनेक प्रकार के बड़े बिजनेसों को मूल्य निर्धारण का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, तांबे, जस्ते या अल्यूमीनियम जैसी धातुओं या तेल व गैस जैसे हाइड्रोकार्बनों में बिजनेस करने वालों का स्वाभाविक एकाधिकार है। इस कारण वे ऊंचे दाम रख कर भारी मुनाफा कमाते हैं। निजी बैंक भी 3-4 प्रतिशत मार्जिन रख कर भारी मुनाफा कमाते हैं। आईटी व आईटी सक्षम क्षेत्र की कंपनियां अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग कर साल दर साल भारी मुनाफा कमा रही हैं। रसायन, पेट्रोरसायन, दवा व कृषि रसायन क्षेत्रों में उद्यमों को संरक्षणवादी परिवेश से भारी मुनाफा हुआ है। उनको आयात पर भारी छूट तथा लाइसेंसिंग व पंजीकरण आवश्यकताओं में काफी रियायत मिलती है। वे किसानों समेत लाखों उपभोक्ताओं की कीमत पर पैसा कमाते हैं। इन बिजनेसों के मालिक व प्रमोटर अपना कर दायित्व न्यूनतम रखने के सारे प्रयास करते हैं।

सरकार उनके मुनाफे अधिकतम करने में उनकी पूरी सहायता करती है। नए उद्यमों के लिए कार्पोरेट कर घटा कर 15 प्रतिशत तथा वर्तमान उद्यमों के लिए 22 प्रतिशत करने की सितंबर, 2019 की घोषणा को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अधिक पूंजी व गहन कौशल वाले इन उद्योगों में से अधिकतम में मुनाफे का मामूली साझा देश की 500 मिलियन श्रमशक्ति से किया जाता है। दूसरी ओर टेक्सटाइल, वस्त्र, फुटवियर, भोजन सेवाओं तथा अतिथि सत्कार क्षेत्र में ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है और यहां बड़े पैमाने पर अकुशल श्रमिकों को भी काम मिलता है।

लेकिन इन कामगारों को मुनाफे में अच्छा हिस्सा नहीं मिलता है। 60 मिलियन से अधिक छोटे व मझोले उद्योग-एसएमई निजी स्वामित्व में हैं, लेकिन सृजित संपदा के वितरण में ये बड़े उद्यमों से पीछे रहते हैं। उनके स्वामी श्रमिकों को कम से कम पैसा देकर अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। कृषि एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता है। यहां अधिकांश किसान स्वामी होने के साथ ही किसान और कामगार की भूमिका निभाते हैं। इनमें से लाखों किसान थोड़े से व्यापारियों की दया पर निर्भर रहते हैं। व्यापारी उनकी फसलें औने-पौने दामों में खरीदते हैं तथा उसे उपभोक्ताओं को अधिक दाम पर बेचते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी आमतौर से केवल कागजों पर ही रह जाता है।

अमीरों का एक और वर्ग है जो सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर लाभ उठाता है। इसमें भ्रष्ट नौकरशाह, राजनेता और बिचौलिए शामिल हैं जो कल्याणकारी योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से कर्ज वितरण तथा फर्जी कंपनियों के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन एकत्र करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो बिजनेस की प्रकृति चाहे जो हो, वह छोटा या बड़ा हो अथवा वह कृषि, उद्योग, सेवा या व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हो, सबका ढांचा इस तरह का होता है कि वे अपने स्वामियों या शक्तिशाली व प्रभावशाली लोगों के हाथों में आय का संकेन्द्रण करते हैं।

ऐसे में कामगार तबके को लगातार नुकसान होता है जिनमें खासकर एसएमई के कामगार, लाखों किसान तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर शामिल हैं। यहां तक कि कार्पोरेट व एसएमई को दी गई कर रियायतों से भी ऊपर के कुछ लोगों की जेबें भरती हैं। दूसरे स्तर पर अनेक कल्याण योजनाओं से केवल गरीबों को जीवित रहने में सहायता मिलती है जिनमें मुफ्त भोजन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ते उर्वरक, आदि शामिल हैं। ऐसे में उद्योगों के बिजनेस तरीके में आमूल परिवर्तन के साथ ही राजनेताओं व नौकरशाहों के व्यवहार में परिवर्तन भी जरूरी है। बिजनेसों को अपने मुनाफे के लालच का संवरण कर उपभोक्ताओं से कम पैसे लेने चाहिए, कामगारों को ज्यादा पैसे देने चाहिए तथा ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए। राजनेताओं व नौकरशाहों को सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों के कल्याण और सशक्तीकरण पर खर्च अधिकतम किया जाए।

डब्लूईएफ 2022 में शामिल 100 से अधिक अरबपतियों के समूह ने स्वयं को 'देशभक्त करोड़पति' कह कर राजनेताओं व बिजनेसमैनों के लिए एक अपील जारी की है कि वे अब ज्यादा टैक्स अदा करें। इस समूह में भारतीय अरबपति भी शामिल हैं। यह हास्यास्पद किस्म की बात है क्योंकि वे तो अपनी संतुष्टि के लिए व्यवस्था बनाते हैं जिससे बहुसंख्य जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसके बावजूद वे जनता की देखभाल करने का ढोंग करते हैं। क्या ये स्वघोषित देशभक्त बहुसंख्य गरीबों का खून पीना बंद करेंगे?

उच्च शिक्षा संस्थानों पर महामारी के दुष्प्रभाव

"डिजाइन उद्योग आज प्रमुख नियोक्ताओं में से एक है क्योंकि सभी उद्योग अपनी उर्ध्व डिजाइन और नवाचार क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं।"

संजय गुप्ता
(लेखक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आफ डिजाइन के कुलपति हैं)

शिक्षा के महामारी से प्रेरित ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड ने उच्च शिक्षा संस्थानों पर आर्थिक रूप से जोर दिया है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों पर। रचनात्मक क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों ने आवश्यक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बनाने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया है। इसलिए, इन संस्थानों की एक बड़ी उम्मीद इस वित्तीय तनाव का निवारण है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और अतिरिक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास की लागतों के साथ-साथ एड-टेक प्लेटफार्मों को वित्तपोषित करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी (चौथी औद्योगिक क्रांति) से प्रेरित व्यवधान को देखते हुए, समग्र आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के किसी भी कदम में डिजाइन शामिल होना चाहिए। सरकार की 'मेक-इन-इंडिया' पहल को 'डिज़ाइन-इन-इंडिया' के साथ जोड़े जाने की ज़रूरत है ताकि लोग नए उत्पाद बना सकें, व्यावसायिक प्रक्रियाएं तैयार कर सकें और समाज के लिए सेवा वितरण के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। यह इसलिए जरूरी है ताकि हम एक अधिक कुशल और रोजगार योग्य भारत का निर्माण कर सकें क्योंकि तथ्य यह है कि डिजाइन उद्योग आज प्रमुख नियोक्ताओं में से एक है क्योंकि सभी उद्योग वर्टिकल अपनी डिजाइन और नवाचार क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं।

हालांकि, डिजाइन उद्योग और शिक्षा के महत्व और सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान को शायद ही पहचाना जाता है। ऐसा होने के लिए, सरकार को अपनी और जनता की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यह माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अधिक

रचनात्मक शिक्षा को शामिल करके और एक रचनात्मक थिंक-टैंक की स्थापना करके शुरुआत कर सकता है जो नीति को चुनौती देता है और नियमों को फिर से लिखता है। रचनात्मक उद्योगों के लिए कैबिनेट में भूमिका खोलने से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। दक्षिण कोरिया में उन्होंने भविष्य, विज्ञान और रचनात्मकता मंत्रालय का गठन किया है। यह विज्ञान को संस्कृति में बदलने में डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मुझे लगता है कि भारत में भी हमें ऐसी ही पहल की जरूरत है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता को एक साथ ला सके; और एक क्रॉस-कटिंग रणनीति बनाएं जो गेमिंग, दृश्य कला उद्योग, औद्योगिक डिजाइन क्षेत्र, संगीत क्षेत्र, संचार क्षेत्र, और रचनात्मक-औद्योगिक क्षेत्रों को सक्षम बनाता है जो उनके संकरण से उभरकर तकनीकी अनुसंधान के समेकन में एकीकृत होते हैं। आर्थिक विकास। डिजाइन विशेष रूप से एमएसएमई के लिए अनुसंधान और विकास के द्वार भी खोलता है, जो अपने सीमित संसाधनों के साथ अपने व्यापार मॉडल में आर एंड डी शामिल नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण तक रचनात्मक कौशल में निवेश करने से व्यापक नवाचार होगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में डिजाइन कौशल के मूल्य को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। यह सरकार द्वारा डिजाइन शिक्षा का समर्थन करके और इसे वहनीय बनाकर किया जा सकता है।

रोजगार के अवसर पैदा करने के किसी भी गंभीर प्रयास के लिए विज्ञान पर जोर देने के साथ-साथ रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। देखें कि कैसे एक मेटावर्स की कल्पना और निर्माण किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों, प्रशिक्षकों और नेताओं के अलावा गेम डिजाइनरों, निर्माताओं, कहानीकारों, डेटा प्रदाताओं, विश्लेषकों, स्थानिक मानचित्रकारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए अवसरों का एक नया ब्रह्मांड खुल रहा है।

भविष्य की कला और डिजाइन की दुनिया वर्तमान और भविष्य, संवर्धित और आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकियों का पूरा उपयोग कर रही होगी। इस उभरते हुए नए युग के लिए शिक्षा को भी मांग के अनुरूप बनाए जाने की जरूरत है। सरकारी मिशन डिजाइन, रचनात्मकता और नवाचार को स्कूली पाठ्यक्रम के लिए गणित और अंग्रेजी के रूप में महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, डिजाइन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना चाहिए ताकि आने वाले दो दशकों में हम घरेलू कंपनियों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार करें। और गेंडा; और हम वित्तीय निदेशकों के रूप में कई रचनात्मक निदेशकों का उत्पादन करने में सक्षम हैं। सरकार, जैसा कि केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देती है, यह याद रखना अच्छा होगा कि आज के डिजाइनर कल के नवप्रवर्तक और उद्यमी हैं।

आप की बात

सोशल मीडिया का दौर

आज के दौर में सोशल मीडिया क्या अहमियत रखता है? इस सवाल के जवाब का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की आज भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 51.8 करोड़ लोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रिय है। यानी, सोशल मीडिया आज एक अहम हिस्से के तौर पर लोगो के जीवन में अपनी जगह बना चुका है। आज जिसको देखो वह सोशल मीडिया में जीता नजर आता है और वो भी वास्तविकता से बहुत दूर। समाज की आज यही सच्चाई है की वो सोशल मीडिया के अधीन होकर खुद गुम होन के साथ-साथ अपनो से भी दूर हो रहा है। बेशक, सोशल मीडिया सामंजस्य बनाने और बरकरार रखने की काबीलियत रखता है, लेकिन जिस तरह से ये रिश्तों के बीच हस्तक्षेप करता दिखाई देता है - वह इसे कहीं न कहीं रिश्तों के बीच बेंत का बाड़ा बनाता है। अब बात है की आखिर सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचा कैसे जाएं? समय निर्धारित कर और लक्ष्य निर्धारित करके। अंतत: इन सुझावों को परख कर यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम पर ही निर्भर करता है, ये हम पर है कि हम इससे अपना भला करते हैं या बुरा।

- **निखिल रस्तोगी**, कुरुक्षेत्र विवि

कदम-कदम बढ़ाए जा

गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन तीनों सेनाओं का विजय गान राष्ट्रपति भवन के सामने जिस ढंग से दर्शाया गया वह तीनों सेनाओं के शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन था। ब्रीटिंग द रिट्रीट समारोह को देखना अपने आप में अद्भुत है तीनों सेनाओं के बैंड वादक जिस तरह से अपनी-अपनी सेना के वादक लिए अपनी अपनी सेना के लिए अद्भुत संयोजन के साथ धुने निकालते हैं राजपथ पर बैठी जनता के साथ-साथ टीवी पर उसे देख रहे दर्शक भी अभिभूत हो जाते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी धून ने किया तो वह था ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। नेहरू जी के जमाने से लेकर आज तक भी इस गीत में आज भी ऐसा कुछ अभिमान है कि जिसे आज भी सुने तो उन वीरों के लिए जिन्होंने देश के लिए जान दे दी उनकी उनके याद में आज भी दिलों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। हमारे सैनिक आज जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा पर कश्मीर में एवं चीन की सीमा पर गलवान में पराक्रम का जो अद्भुत जौहर दिखाते हुए शहीद हुए हैं देश की रक्षा के लिए। अत: उनको याद करते हुए देश का आंसू बहाना आज भी लाजमी है। इस कार्यक्रम के आखिर में झंडा उतारने की सरेमेनी होती है उसका तो कहना ही क्या।

- **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

नए दौर के डाकघर

पोस्टऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे। सरकार का सराहनीय फैसला इसी किअगली कड़ी के रूप में बैंक आउटलेट की तरह छोटे गांव में भी डाकघर आउटलेट खोले जाएं पोस्ट ऑफिसों को अब कूरियर वालों की तर्ज पर काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसकी खोई हुई साख उसे पुन: प्राप्त हो सके और लोगों को सस्ती डाक पार्सल सुविधा उपलब्ध हो सके! साथ ही बैंकों की ब्याज दर भी डाकघरों की जमा बचत ब्याज दरों के अनुरूप की जाना चाहिए, ताकि लोगों की अपनी बचत पर पर्याप्त ब्याज की राशि मिल सके। अन्यथा अभी तो हालात यह है कि 5प्रतिशत ब्याज मिल रहा है और 8प्रतिशत रुपए की वैल्यू गिर रही है ऐसे में एफडी घाटे का सौदा हो गया है!

- **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

फरमाया

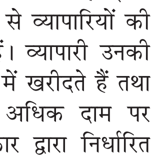

ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार ने संसद, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है और भारत के लोगों (पेगासस पर) से झूठ बोला है।

- **अधीर रंजन चौधरी**
कांग्रेस नेता

रूस से जुड़ी यूक्रेन की सीमा पर तस्वीर लगातार चिंताजनक होती जा रही है।

- **बोरिस जॉनसन**
ब्रिटिश प्रधानमंत्री

स्वदेशी वैक्सीन पर हमारे देशवासियों का यह भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

- **नरेंद्र मोदी**
प्रधानमंत्री

इकलौती संसदीय सीट पर साख बचाने की कोशिश में कांग्रेस

भाषा। रायबरेली

पड़ोसी जिले अमेठी में कांग्रेस को पछाड़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के एकमात्र गढ़ रायबरेली को ध्वस्त करने के लिए पूरे जोर-शोर से जुटी हुई है। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनावों में जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करना है। रायबरेली 2019 में कांग्रेस के हिस्से में आई एकमात्र लोकसभा सीट थी, यहां तक कि पार्टी की महत्वपूर्ण अमेठी सीट भी भाजपा के हिस्से में आ गई थी। यहां से स्मृति ईरानी ने तत्कालीन सांसद राहुल गांधी को हराया था। विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस को महज दो विधानसभा सीटों– रायबरेली (सदर) और हरचंदपुर– पर जीत मिली थी। कांग्रेस के अदिति सिंह और राकेश सिंह को इन सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि, बाद में दोनों भाजपा में शामिल हो गए और इस बार भाजपा ने इन्हें मैदान में उतारा हैं। कभी कांग्रेस के सिपाही रहे, दोनों विधायक अब उसके खिलाफ ही ताल ठोकेंगे। रायबरेली जिले में छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं– बछरावां (आरक्षित), सरैनी, ऊंचाहार, सलोन (आरक्षित), सदर और हरचंदपुर।

पिछले चुनाव में बछरावां, सरैनी और सलोन में क्रमशः भाजपा के राम नरेश रावत, धीरेंद्र बहादुर सिंह और दल बहादुर ने जीत हासिल की थी, वहीं ऊंचाहार सीट से सपा के मनोज कुमार पांडे निर्वाचित हुए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा ने सहयोगी के रूप में लड़ा था। कांग्रेस का दावा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है, वह संप्रग सरकार के दौरान हुआ है, हालांकि भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है। कांग्रेस प्रवक्ता विनय द्विवेदी ने पीटीआई/भाषा को बताया, 2004–2014 के दौरान, तत्कालीन संप्रग सरकार ने उस समय रायबरेली को एक महिला अस्पताल, एम्स, पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल कोच फैक्टरी, रेलवे डबल ट्रैक सहित 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं दी थीं। पिछले सात वर्षों में, भाजपा यहां या अमेठी में भी कोई नई परियोजना नहीं लगा सकी है। हरचंदपुर से इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में वोट मांग रहे राकेश सिंह ने कहा, यहां के मतदाताओं का गांधी परिवार से जो भावनात्मक जुड़ाव था, वह समय बीतने के साथ कम हो गया है और स्थानीय लोगों से उनका जुड़ाव बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया, प्रियंका (गांधी वाद्रा) का रायबरेली में कोई असर नहीं है। उनकी उपस्थिति कहीं और हो सकती है लेकिन लोगों ने उन्हें चुनाव के समय के अलावा यहां नहीं देखा है। गांधी परिवार क्षेत्र को विकास देने या भावनात्मक बंधन को बनाए रखने में विफल रहा है। कांग्रेस के विकास के दावों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा, इंदिरा गांधी के समय में स्थापित अधिकांश उद्योग समय बीतने के साथ बंद हो गए। इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यों से स्थानीय लोगों को लाभ नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से किसी भी स्थानीय युवा को लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, यहां सभी सीटों पर सीधा मुकाबला भाजपा–समाजवादी पार्टी के बीच होगा। कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है और उसे सभी सीटों पर केवल 10,000 से 12,000 वोट ही मिलेंगे, उनमें से कुछ पर उसकी जमानत भी जब्त हो सकती है।

भाजपा की जिला इकाई के अध्यक्ष रामदेव पाल ने कहा, भाजपा रायबरेली में जबरदस्त मेहनत कर रही है, इस बार पार्टी यहां सभी छह सीटें जीतेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम 2022 के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसके बाद यह हमारे लिए मिशन 2024 होगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जीतकर यहां दोबारा कभी नहीं आई हैं, लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि उनके बीच रहे। सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह पर 1.6 लाख वोटों के कम अंतर के साथ अपनी सीट बरकरार रखी, जो अंतर 15 वर्षों में सबसे कम है। 2014 में, उन्होंने 3,5 लाख वोटों के अंतर से, 2009 में 3.7 लाख वोटों से और 2004 में 2.4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। दिनेश प्रताप सिंह के भाई राकेश सिंह ने कहा, सोनिया गांधी का यहां विरोध इसलिए है क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति हैं और लोग एक स्थानीय नेता चाहते हैं जो उनके लिए दिनेश प्रताप सिंह हैं, अगर वह फिर से लड़ते हैं, तो यहां से जीतेंगे। कांग्रेस ने राकेश सिंह के खिलाफ हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए सुरेंद्र विक्रम सिंह को मैदान में उतारा है। सदर सीट पर अदिति सिंह के खिलाफ सबसे पुरानी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार का चायन नहीं किया है। रायबरेली संसदीय क्षेत्र की छह विधानसभा सीटों में से पांच पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा जबकि सलोनी विधानसभा क्षेत्र में 27 फरवरी को पांचवें चरण में मतदान होना है। इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है।

बिजनौर सीट पर तो बिना लड़े ही हार गई कांग्रेस

विवेक श्रीवास्तव। लखनऊ

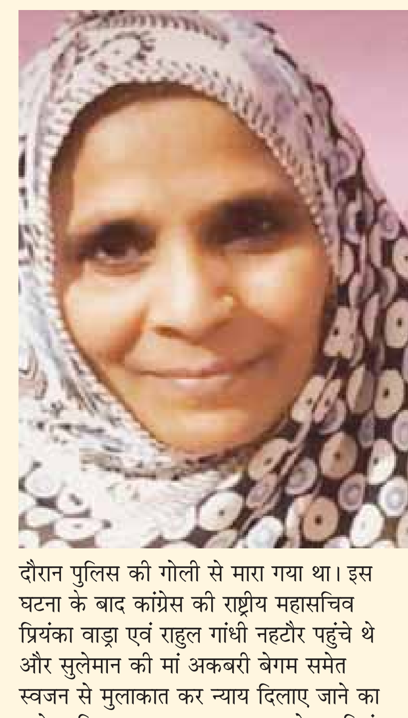

पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की बिजनौर सदर सीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सारे मंसूबे धरे के धरे ही रह गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस चुनाव से पहले ही पराजित हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अकबरी बेगम का पर्चा खारिज हो गया है। अब ऐसे में बिजनौर सदर सीट पर कांग्रेस सिर्फ तमाशबीन की भूमिका में नजर आ रही है। अपना आधार वोट पूरी तरह से गंवा चुकी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आधी आबादी पर दांव खेला है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देने का वायदा करके इस तबके को लुभाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने वायदा तो जरूर कर दिया लेकिन इतनी भारी संख्या में महिला प्रत्याशियों का चयन पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। इसकी काट यह निकाली गई और तय किया गया कि उन महिलाओं को टिकट दिया जाएगा जो पिछले कुछ समय से किसी न किसी वजह के चलते अपने क्षेत्र में चर्चित हैं। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी ने बिजनौर की सदर सीट से सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली लगने से मारे गए सुलेमान की मां अकबरी बेगम को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। अपने इस निर्णय से उन्होंने मुस्लिम बिरादरी को भी साधने का भरपूर प्रयास किया था।

अकबरी बेगम का 21 वर्षीय पुत्र सुलेमान 20 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के विरोध में बिजनौर के नहटौर में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया था। इस घटना के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा एवं राहुल गांधी नहटौर पहुंचे थे और सुलेमान की मां अकबरी बेगम समेत स्वजन से मुलाकात कर न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिलाया था। अब चुनाव आने पर प्रियंका गांधी ने सुलेमान के परिवार से संपर्क कर टिकट की पेशकश की थी। इसके बाद सुलेमान की मां को कांग्रेस ने बिजनौर सदर सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस की घोषणा के बाद से बिजनौर सदर सीट और अकबरी बेगम के नाम को लेकर चर्चा का माहौल गर्म था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन के चलते टिकट बंटवारे में यह सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को चुनाव मैदान में उतारा था। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शुचि चौधरी ने समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा को 27281 वोटों के अंतर से पराजित किया था। मौजूदा चुनाव में भाजपा ने अपनी वर्तमान विधायक शुचि चौधरी को ही प्रत्याशी बनाया है जबकि रुचि वीरा समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बसपा से चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी का इस बार राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन है और इस सीट पर राष्ट्रीय लोक दल ने डॉक्टर नीरज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अकबरी बेगम के सिंबल पर हस्ताक्षर नहीं मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी ने बीते शनिवार को उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस बिना लड़े ही चुनाव से बाहर हो चुकी है।

बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के लिए जीत की राह आसान नहीं

शिव विजय सिंह। लखनऊ

बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के लिए जीत की राह आसान नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के भीतर काफी जबरदस्त तरीके से घमासान व नाराजगी चल रही है। शायद यही कारण रहा कि सपा हाईकमान द्वारा बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में से 17 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद विरोध के चलते करीब पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने पड़े। यही नहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने वाले सपा के युवा नेता चंद्र भूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा बुंदेला ने पार्टी की गतिविधियों से नाराज होकर बसपा का दामन थाम लिया जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका था। गुड्डू राजा बुंदेला ललितपुर विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार के रूप में सीधे-सीधे समाजवादी पार्टी को ही ललकार रहे हैं जिसका असर ललितपुर के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है क्योंकि गुड्डू राजा बुंदेला का बुंदेलखंड में जबरदस्त प्रभाव रहा है।

बुंदेलखंड में दो मंडल हैं– झांसी और चित्रकूट। इन दो मंडलों में छह जिले– जालौन झांसी, ललितपुर, हमीरपुरए, बांदा व चित्रकूट आते हैं जिनमें 19 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें माधोगढ़, कालपी, उरई सदर, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर, गरौठा, ललितपुर, हमीरपुर, राठ,महोबा, चरखारी, तिंदवारी, बबेरू, नरैनी, बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर, महरौनी शामिल है। समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड की चित्रकूट व मानकपुर विधानसभा सीट के अलावा 17 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सपा द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के 24 घंटे के भीतर ही बुंदेलखंड में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में पांच प्रत्याशियों का पत्ता काट दिया। बांदा में सुरक्षित सीट नरैनी से सपा ने पूर्व मंत्री और सामाजिक परिवर्तन मिशन के संयोजक दद्दू प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया था लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के दबाव के चलते उनके स्थान पर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष किरन वर्मा को प्रत्याशी बना दिया। किरन वर्मा पिछले वर्ष ही बसपा से सपा में शामिल हुईं थीं। इसी तरह जालौन में कालपी और उरई के प्रत्याशी बदल दिए। उरई सदर सीट से 2012 में विधायक रहे दयाशंकर वर्मा व कालपी से पूर्व मंत्री और बसपा से तीन बार विधायक रहे श्रीराम पाल को प्रत्याशी बनाया था। इनके स्थान पर कालपी से विनोद चतुर्वेदी और उरई से महेंद्र कठेरिया को अब सपा प्रत्याशी बनाया गया है। हमीरपुर सदर विधानसभा सीट से मनोज प्रजापति का टिकट काटकर रामप्रकाश प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। हमीरपुर जिले की सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने मवईजार गांव निवासी रामप्रकाश प्रजापति को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही सपा की सदस्यता ग्रहण की थी। राम प्रकाश वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत थे और दो साल पूर्व ही वह रिटायर हुए हैं। सपा में शामिल होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति शुरू कर दी। प्रजापति बिरादरी के मतदाता अच्छी संख्या में हैं। सही मायने में देखा जाए तो बुंदेलखंड पर मौजूदा समय में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का बीते सात साल से कब्जा है। भाजपा ने सभी सीटें एक लाख से लेकर 15 हजार तक जीत के अंतर से जीतीं हैं। पर बुंदेलखंड का सियासी मिजाज कुछ ऐसा रहा है कि वह किसी एक दल का होकर नहीं रहा है। यहां बसपा को भी ऊंचाईयों पर बिठाया तो सपा को भी खासी तवज्जो मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा पांच, बसपा सात, कांग्रेस चार व भाजपा ने तीन सीटें जीती थीं। जब सपा ने 224 सीटें लेकर यूपी में सरकार बनाई थी तब उसे इस इलाके में महज पांच सीटें ही मिली थीं। यही नहीं तब बुंदेलखंड के हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में तो उसका खाता तक नहीं खुला था। उससे पहले 2007 के चुनाव में सपा केवल छह सीट जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने की पुरजोर कोशिश की है इसके लिए उन्होंने तीन दिन बुंदेलखड में डेरा भी डाला और रैली भी की। देखना अब यह है कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की मेहनत बुंदेलखंड में क्या रंग दिखाती है।

यूपी में फिर कसौटी पर होगा मुस्लिम फैक्टर

कमल दुबे। लखनऊ

IANS

यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दांव पर होगा मुस्लिम फैक्टर। वैसे तो राज्य में करीब 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है लेकिन 403 विधानसभा क्षेत्रों में से सौ से अधिक सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं। राज्य में करीब तीन दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से अधिक है। इनमें से पश्चिमी यूपी तथा रुहेलखंड की कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां 50 फीसदी से भी ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं।

हालांकि वोटों के बिखराव और ध्रुवीकरण के चलते पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुस्लिम फैक्टर बेअसर ही साबित होता दिखा लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इन सीटों पर मुस्लिम फैक्टर कसौटी पर होगा। वैसे अगर अतीत में जाएं तो राज्य के चुनावी समीकरण में मुस्लिम मतदाताओं की खासी अहमियत रही है। आमतौर पर मुस्लिम मतदाता भाजपा को नापसंद करने वाले माने जाते हैं। भाजपा जहां मुस्लिम उम्मीदवारों से परहेज करती रही है वहीं मुस्लिम समुदाय भी उसी राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है जो भाजपा को हराने की स्थिति में हो।

मुस्लिम समाज की राजनीति करने वाली पार्टियों की भरमार है लेकिन यूपी में पिछले तीन दशक से ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं का सर्वाधिक भरोसा समाजवादी पार्टी पर रहा है। पहले पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव और अब सपा की कमान संभाल रहे उनके पुत्र अखिलेश यादव मुस्लिम समाज की पहली पसंद हैं। पिछले चुनाव में अखिलेश ने भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस को साथ लेकर मुस्लिम समुदाय की दुविधा खत्म कर मजबूत विकल्प देने की कोशिश की थी लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। कुल 311 सीटों पर चुनाव लड़ी पार्टी ने 61 पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे लेकिन कुल जीते 47 में 17 ही मुस्लिम समाज के विधायक बने। नतीजों के बाद कहा गया कि मुसलमानों का एक वर्ग तत्कालीन अखिलेश सरकार के कामकाज से खुश नहीं था। मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर 18 फीसद आरक्षण देने जैसे चुनावी वादों के हकीकत में न बदलने और समाजवादी परिवार में तब मचे घमासान से मुसलमानों का एक वर्ग सपा से दूर रहा था।

वैसे जहां तक बसपा की बात है तो पार्टी प्रमुख मायावती को विश्वास था कि सपा की कलह से भ्रमित मुस्लिम समाज उनका साथ देंगे। सपा सरकार को मुस्लिम समाज का विरोधी बताते हुए मायावती उन्हें समझाती रहीं कि दो खेमों में बंटी सपा को वोट देने का मतलब भाजपा को जिताना होगा। मायावती ने मुस्लिम समाज को अपनी ओर मानते हुए 403 सीटों में से रिकार्ड 100 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे लेकिन कुल जीते 19 विधायकों में मात्र पांच ही मुस्लिम चुने गए। कांग्रेस की स्थिति हर तरह से पतली ही रही। उसके कुल सात विधायकों में दो मुस्लिम जीते थे।

18वीं विधानसभा के चुनाव मैदान में कई तरह के नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर जैसे दंगे के बाद क्षेत्र में जाट बनाम मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव के मद्देनजर पिछले चुनाव में परंपरागत मुस्लिम वोटों के छिटकने के डर से सपा ने रालोद से दूरी बनाए रखी थी लेकिन अब बदले समीकरण में मुस्लिम समाज के सपा की ओर बढ़ते झुकाव को देखते हुए रालोद और सपा मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूंकि रालोद के अलावा कई और छोटी पार्टियों से भी सपा ने गठबंधन किया है इसलिए चर्चा है कि सपा अपने सिंबल पर लगभग सवा तीन–साढ़े तीन सौ सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। दूसरी पार्टियों के मुस्लिम नेता भी सपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश पिछली बार से कहीं अधिक मुस्लिम समाज को टिकट दे सकते हैं। बसपा मौजूदा परिस्थिति और पिछले अनुभव को देखते हुए अबकी मुस्लिम समाज को पहले से कम ही टिकट देने वाली है।

बताते हैं कि बसपा नहीं चाहती कि उसके टिकट बंटवारे से ऐसा कोई संदेश जाए जिससे लगे कि मुस्लिम मतों का बिखराव कर वह भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी नए सिरे से मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने में लगी हैं। कांग्रेस टिकट देने में मुस्लिम समाज की महिलाओं को तव्वजो दे सकती है। वैसे तो भाजपा मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती रही है लेकिन इस बार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का पैगाम लिए कुछ प्रत्याशी मैदान में आ सकते हैं।

ध्रुवीकरण से एम फैक्टर के बेअसर होने की आशंका बेमानी नहीं है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सूबे की 80 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम समाज का सांसद नहीं जीता था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ध्रुवीकरण और मुस्लिम मतों में बिखराव से करीब दो दर्जन विधायक ही मुस्लिम समाज के जीते थे। आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआइएमआइएम भी पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय दिख रही है। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में कई सीटों पर मुस्लिम मतों का बिखराव होने और ध्रुवीकरण से सपा–बसपा को नुकसान और भाजपा का फायदा हो सकता है।

ढहता दुर्ग बचाने को बसपा ताश के पत्तों की तरह फेंट रही प्रत्याशी

सतीश सिंह। लखनऊ

विधानसभा चुनाव के जरिये अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने के लिए इस बार बसपा घोषित प्रत्याशियों को ताश के पत्तों की तरह लगातार फेंट रही है। जिसके चलते पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशियों की सूची में शामिल नाम में से कुछ को जातीय समीकरणों को बैठाने के लिए बदला जा रहा है। यही कारण है कि पहले चरण से लेकर चार चरण के अंतर्गत 231 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों की सूची में कुछ सीटों पर अब तक चार संसोधन सूची जारी हो चुकी है।

सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर वर्ष 2007 में अपने दम पर सरकार बनने वाली बसपा की पकड़ पश्चिमी यूपी में मजबूत मानी जाती है। पर 2007 के बाद से यह पकड़ लगातार ढीली होती जा रही है। बची खुची कसर वर्ष 2017 के चुनावों ने पूरी कर दी। मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना से पलायन का मुद्दा पिछले चुनाव में ऐसा मुद्दा बना कि बसपा का किला भर-भरा कर ढह गया। यानी 2017 के चुनाव परिणाम में 231 सीटों में से बसपा के खाते में महज पांच सीटें ही आई। वर्तमान की स्थिति यह है कि मांट सीट से श्याम सुंदर शर्मा को छोड़कर बाकी बचे चार में कुछ भाजपाई हो गए तो कुछ सपाई। ऐसे में इस चुनाव में बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और करने के लिए बहुत कुछ। शायद यही वजह की पार्टी एक एक सीट की लगातार समीक्षा कर रही है। इस दौरान जरूरत महसूस होने पर प्रत्याशी भी बदले जा रहे हैं।

● अब तक पार्टी जारी कर चुकी है चार संशोधित सूची

● किसी में दो तो किसी में तीन प्रत्याशी बदले

वर्ष 2012 में 52 सीट मिली थी बसपा को: बात अगर वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव की करें तो बसपा के खाते में मथुरा की मांट सीट को मिलाकर उसके खाते में 52 सीटें आई थी। 2012 चुनाव में मांट सीट से श्याम सुंदर शर्मा टीएमसी के टिकट पर लड़े थे। बसपा का समर्थन था। 2012 के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था पर 2017 के दौरान भाजपा की आंधी में बसपा किनारे लग गई। उसे महज पांच सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।

वर्ष 2017 में पार्टी की स्थिति: पहले चरण के अंतर्गत 11 जिलों की 58 सीटों में से बसपा के खाते में सिर्फ दो ही सीटें आई थी। वहीं दूसरे चरण में शामिल नौ जिलों की 55 सीटों में से बसपा के खाते में एक भी नही आई। इसी तरह तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों में बसपा के खाते में महज एक सीट आई। वहीं चौथे चरण में पार्टी के खाते में दो सीट आई थी।

पंजाब में सिर्फ पीएलसी-भाजपा गठबंधन जरूरी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है : अमरिंदर सिंह

भाषा। चंडीगढ़

पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) के प्रमुख अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि केवल पीएलसी-भाजपा गठबंधन ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

अमरिंदर ने कहा कि राज्य और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसे केवल पीएलसी गठबंधन, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन से सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएलसी-भाजपा-शिअद संयुक्त गठबंधन के प्रचार के लिए जल्द पंजाब आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गठबंधन पंजाब और देश के हित में बनाया गया है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पीएलसी और सुखदेव सिंह ढींढसा के

नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन किया है।

अमरिंदर ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को गले लगाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाक सेना प्रमुख रोज अपने सैनिकों को भारतीयों को मारने का आदेश देते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की सत्ता उन लोगों के हाथों में नहीं सौंपी जा सकती है, जो अपनी निजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने को तैयार थे। पटियाला के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमरिंदर ने सवाल किया, आप किससे ज्यादा नफरत करते हैं, गोलियां बरसाने वाले सैनिकों से या फिर इसका हुक्म देने वालों से? उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी सेना उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक बयान के अनुसार, अमरिंदर ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच हालांकि कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत एक गंभीर खतरा पैदा करती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएलसी प्रमुख ने बताया कि मार्च 2017 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सीमा पर पंजाब के 83 सैनिकों को मारा है और उनके नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने हर शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा व नौकरी दी थी। अमरिंदर ने दावा किया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इसे उबारने के लिए केंद्र के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर काम करें। अमरिंदर ने कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही दोनों नेताओं के व्यक्तिगत रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। पीएलसी प्रमुख ने राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं से पर्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से छह महीने पहले सरकार में बेवजह बदलाव कर इन योजनाओं को लटका दिया। अमरिंदर ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 22 लाख नई नौकरियां और एक लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया था, लेकिन राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

पंजाब कांग्रेस के नेता जगमोहन आप में शामिल

चंडीगढ़। खरड़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कांग मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।

कंग अपने दो बेटों यदविंद्र सिंह कांग और अमरिंदर सिंह कांग के साथ आप में शामिल हुए। आप नेता एवं पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने एक ट्वीट में कहा, पंजाब कांग्रेस से निराश- 3 बार कैबिनेट मंत्री और विधायक रहे जगमोहन सिंह कांग साब, अपने बेटों और युवा कांग्रेस नेताओं यादवेंद्र और अमरिंदर के साथ आप में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया।

आप पंजाब हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस ने मोहाली जिले की खरड़ सीट से विजय शर्मा को पार्टी का टिकट दिया है। कांग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर इस सीट से उनकी उम्मीदवारी का कथित रूप से विरोध करने का आरोप लगाते रहे हैं।

मुझे चमकौर साहिब से पचास हजार मतों के अंतर से जीत दिलाएं

●मुख्यमंत्री चन्नी ने मतदाताओं से किया अनुरोध

भाषा। चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब के लोगों से मंगलवार को अनुरोध किया कि वे राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान के दौरान कम से कम 50,000 मतों से अंतर से उन्हें विजई बनाएं। चन्नी के बयान से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि चन्नी चमकौर साहिब सीट से हार रहे हैं। चन्नी ने रूपनगर जिले में चमकौर साहिब सीट (एससी) से नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको मुझे 50,000 मतों के अंतर से विजयी बनाना होगा। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद था। उन्होंने आगामी चुनावों में लोगों से उन्हें पूरे दिल से सहयोग देने का अनुरोध करते हुए कहा, यदि हम (चमकौर साहिब से) 50,000 से कम मतों के अंतर से जीतते हैं, तो यह जीत नहीं होगी।

चन्नी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन पर चमकौर साहिब के लोगों की आवाज दबाने के लिए हाथ मिलाने का आरोप लगाया। अट्ठावन वर्षीय नेता ने कहा, वे जितनी बार चाहें, उतनी बार छापा मार सकते हैं। जितनी चाहे, उतनी फर्जी प्राथमिकियां दर्ज कर सकते हैं। भले ही कुछ भी हो जाए, चमकौर साहिब के लोग मेरे साथ हैं। तीन बार के विधायक चन्नी ने कहा कि मैं आपका बेटा और आपका भाई हूं। मैं 15 साल से आपके साथ हूं और एक भी दिन के लिए आपसे दूर नहीं गया। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे इस चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र से उनका समर्थन करें। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल में पंजाब में अवैध रेत खनन के खिलाफ जारी धनशोधन रोधी जांच के सिलसिले में की गई छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी, जिसमें से आठ करोड़ रुपए चन्नी के एक रिश्तेदार से जुड़े परिसरों से जब्त किए गए थे।

चन्नी ने इस मामले में उनका कोई भी संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर उनके खिलाफ निंदनीय अभियान चलाने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। चन्नी 2007 से चमकौर साहिब विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 2017 के चुनाव में 12,308 मतों के अंतर से विजयी हुए थे।

नई दिल्ली के साऊथ ब्लाक में गार्ड आफ आनर का निरीक्षण करते नए वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ ले. जनरल मनोज पांडेय

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के परिसर से तीन करोड़ की नक्दी बरामद

भाषा। नई दिल्ली

आयकर विभाग ने नोएडा में एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर करीब तीन करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बरामद तीन करोड़ रुपए की नकदी 2000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए के नोट के रूप में परिसर में बनाए गए निजी लॉकर में रखी मिली।

सूत्रों ने कहा कि 30 जनवरी को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी मिलने के बाद तलाशी शुरू की गई थी और कार्वाई जारी है।

उन्होंने कहा कि अब तक करीब तीन करोड़ रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं और विभाग इसके स्वामित्व तथा स्रोत की जांच कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर से हैं।

मजीठिया अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव

पंजाब चुनाव

भाषा। चंडीगढ़

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मंगलवार को कहा कि वह मजीठा विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे और केवल अमृतसर पूर्व से लड़ेंगे। अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी पत्नी गनीव कौर उनके स्थान पर मजीठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कौर ने सोमवार को मजीठा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। कुछ दिन पहले शिअद प्रमुख ने सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व से मजीठिया को मैदान में उतारा था।

अमृतसर में मीडिया को संबोधित करते हुए मजीठिया ने कहा कि शिअद द्वारा उन्हें अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उनसे पूछा कि अगर वह दोनों सीटों से जीते तो वह किस सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सवाल ने उन्हें केवल एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मजीठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

मजीठिया ने कहा कि मजीठा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद, मैं घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी गनीव कौर मजीठा सीट से चुनाव लड़ेंगी। मैं अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ूंगा। मजीठिया 2007 से मजीठा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मजीठिया ने अमृतसर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करने पर नवजोत सिद्धू पर निशाना साधा। सिद्धू ने पिछले हफ्ते मजीठिया को मजीठा विधानसभा सीट छोड़ने और अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही लड़ने की चुनौती दी थी।

चुनावी समर में उतरे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लाधर, दूसरे नौकरशाह से होगा मुकाबला

चंडीगढ़। लुधियाना की गिल विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दो पूर्व नौकरशाहों के बीच होना है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने सुच्चा राम लाधर को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक कुलदीप सिंह वैद्य पर दांव लगाया है। पंजाब कैडर के 1991 बैच के 63 वर्षीय अधिकारी लाधर ने कहा कि उन्होंने लोगों की सेवा करते रहने का प्रण लिया है। इस सीट पर लाधर का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक वैद्य से होना है। दिलचस्प बात यह है कि वैद्य के भाई सरबजीत शनिवार को ही भाजपा में शामिल हुए हैं। एम.टेक तक शिक्षा हासिल करने के बाद लाधर ने 1982 में पंजाब के सिंचाई विभाग में काम करना शुरू किया।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष लालपुरा का इस्तीफा, पंजाब से भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वह पंजाब के रूपनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लालपुरा ने बताया कि गत 28 जनवरी को उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। संवैधानिक बाध्यता के चलते मैंने इस्तीफा दिया है। गत 27 जनवरी को भाजपा ने लालपुरा को रूपनगर से अपना उम्मीदवार घोषित किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा पिछले साल सितंबर में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे थे।

टिकट मिलने के बाद सांपला ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

फगवाड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब की फगवाड़ा (आरक्षित) विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय सांपला ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

सांपला ने कहा कि फगवाड़ा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने 28 जनवरी को अपना इस्तीफा संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया था।

उन्होंने कहा कि मुझे 27 जनवरी को पार्टी का टिकट आवंटित किया गया था और 28 जनवरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

सांपला ने सोमवार को फगवाड़ा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी।

कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति मिली

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम को इस माह के अंत में विदेश जाने की मंगलवार को अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को उन्हीं शर्तों पर विदेश जाने देने की अनुमति दी जाती है, जैसी शर्तें पहले लगाई जा चुकी हैं और उन्हें (कार्ति को) उस आदेश में उल्लेखित सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को अर्जी के बारे में अवगत कराया, जिसमें विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और कहा कि याचिकाकर्ता को पूर्व की शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है।

सिब्बल ने गत वर्ष 25 अक्टूबर के आदेश का उल्लेख किया जिसके तहत कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी गई थी और पीठ को आश्वस्त किया कि कार्ति फरवरी में एक करोड़ रुपए जमा करा देंगे।

कांग्रेस सांसद एयरसेल मैक्सिस करार और आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिए कथित तौर पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने संबंधी आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

उन पर आरोप है कि उन्होंने एफआईपीबी की मंजूरी के लिए 305 करोड़ रुपए लिए थे, उस वक्त कार्ति के पिता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदम्बरम केंद्र में वित्त मंत्री थे।

बीएसएफ ने लोगों को पाक सीमा से ड्रोन घुसपैठ पर नजर रखने का प्रशिक्षण दिया

भाषा। जम्मू

पाकिस्तान से सटी 198 किलोमीटर लंबी सीमा पर रह रहे लोग पड़ोसी देश से होने वाली ड्रोन घुसपैठ पर नजर रखने में बीएसएफ की मदद कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 140 से अधिक ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को भारत-पाक सीमा पर ड्रोन गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित आरएस पुरा, अखनूर और अरनिया सेक्टर में सीमावर्ती बस्तियों में ड्रोन गतिविधियों को लेकर जागरुकता फैलाने वाले कई फ्लेक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं। सुचेतगढ़ निवासी दयान सिंह कहते हैं, हम सीमा पर ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हमें बताया गया है कि आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ गिराने की खातिर कैसे सीमापार से ड्रोन का संचालन किया जाता है।

एक अन्य ग्रामीण एवं पूर्व सैनिक सुरम चंद ने कहा कि बीएसएफ के गश्त अभियान और तकनीकी निगरानी के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमा पर तीसरी आंख बन गए हैं। बीएसएफ के डीआईजी एसपीएस संधू ने बताया कि बीएसएफ ने अतीत में जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों में 170 से अधिक बस्तियों व स्कूलों में 144 ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संधू के मुताबिक, बीएसएफ ने सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों में इजाफे के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों में पिछले साल ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से संचालित ड्रोन गतिविधियां सीमावर्ती इलाकों में गंभीर चिंता का सबब बन गई हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए मदद सामग्री गिराए जाने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं।

डीआईजी बीएसएफ ने कहा, सीमावर्ती इलाकों में रह रह लोगों को ड्रोन के जरिए खेप गिराए जाने का लाइव दृश्य दिखाया गया। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, गांवों और स्कूलों में विभिन्न फ्लेक्स बोर्ड भी प्रदर्शित किए गए, ताकि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की जानकारी देने और उसे नाकाम करने के लिए आबादी के बीच समझ व समन्वय को बढ़ाया जा सके। बीते साल जीपीएस से लैस और दस किलो वजन ढोने में सक्षम कई ड्रोन ने पाकिस्तान से दर्जनों बार हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों के जखीरे गिराए थे।

प्रयागराज में मौनी अमावस्या उत्सव के अवसर पर गंगाए यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर पवित्र स्नान करने से पहले प्रवास पर हिंदू श्रद्धालु

अरुणाचल प्रदेश से अपहृत किशोर के पिता का आरोप

चीनी सेना ने पिटाई की, बिजली के झटके दिए

भाषा। ईटानगर

अरुणाचल प्रदेश से कथित तौर पर चीन की सेना द्वारा अगवा किए गए भारतीय किशोर को उसके परिवार से फिर से मिला दिया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने बताया कि भारतीय सेना ने सोमवार शाम को अपर सियांग जिले में तूतिंग में एक कार्यक्रम में मीराम तारोन को उसके माता-पिता से मिलाया। घर वापसी पर स्थानीय प्रशासन और पंचायत नेताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया।

वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप लुंगता जोर इलाके से 18 जनवरी को कथित तौर पर चीनी सेना ने मीराम (17) का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह अपने दोस्त जॉनी यायिंग के साथ शिकार पर गया था। यायिंग किसी तरह घटनास्थल से भाग निकला और उसने प्राधिकारियों को इसकी जानकारी दी। चीनी सेना ने अन्जॉ जिले के किबितू में वाचा-दमाई केंद्र में 27 जनवरी को मीराम को भारतीय सेना को सौंपा, जहां वह पृथक वास में रहा। मीराम के पिता ओपांग तारोन ने कहा कि इस पूरी घटना ने उनके बेटे को डरा दिया है और वह मानसिक रूप से परेशान हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) के कब्जे में एक सप्ताह से अधिक समय तक रहने के दौरान उसे बांधा गया और उसकी आंखों पर भी पट्टियां बांधी गईं।

ओपांग तारोन ने कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा कि वह अब भी सकते में है। उसे पीठ पर मारा गया और शुरुआत में बिजली के हल्के झटके दिए गए। ज्यादातर समय उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसके हाथ बांधकर रखे गए। वे उसे तभी खोलते थे जब उसे भोजन करना होता था या शौच के लिए जाना होता था लेकिन उन्होंने उसे पर्याप्त भोजन दिया। अरुणाचल पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तापिर गाओ ने 19 जनवरी ट्वीटर पर किशोर के अपहरण की सूचना साझा की थी।

नक्सलियों ने गैस सिलेंडर से भरे वाहन को लूटा, सुरक्षा बल को देखकर भागे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों ने रसोई गैस सिलेंडर से भरे वाहन को लूटा। सुरक्षाबलों ने वाहन को छुड़ा लिया है। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के भेजी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सोमवार को रसोई गैस सिलेंडर से भरे वाहन को लूट लिया था। सुरक्षा बलों ने कार्वाई कर मंगलवार सुबह वाहन को छुड़ा लिया है।

केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

भाषा। कोच्चि

केरल उच्च न्यायालय ने अलप्पुझा जिले में स्थित एकमात्र केंद्रीय विद्यालय को बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला की याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की पीठ ने उक्त स्कूल को प्रायोजित करने वाले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपी) की कायमकुलम इकाई और केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी याचिका पर जवाब मांगा है।

चेन्नीथला ने अधिवक्ता निशा जॉर्ज के माध्यम से दाखिल याचिका में दावा किया है कि स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया और ऐसा अवैध रूप से किया गया। याचिका में दावा किया गया है, केंद्रीय विद्यालय (केवी) एनटीपीसी, कायमकुलम (संबंधित स्कूल) वर्ष 1999-2000 में एनटीपीसी, कायमकुलम के प्रायोजन के तहत परियोजना क्षेत्र में खोला गया था। यह अलाप्पुझा जिले में एकमात्र केवी है।

विधायक ने याचिका में तर्क दिया है कि एनटीपीसी अधिकारियों ने अपने हलफनामे का घोर उल्लंघन करते हुए अब स्कूल को प्रायोजित नहीं करने का फैसला किया है, जिसके बाद इसे अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा।

केवीएस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के आई मयंक ट्टी माथर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनसे और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों से इस मामले में निर्देश लेने को कहा और इसे 10 दिन के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इंदौर में एक व्यक्ति ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता के चेहरे पर कालिख मली

भाषा। इंदौर (मध्यप्रदेश)

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के चेहरे पर इंदौर में एक व्यक्ति ने मंगलवार को कालिख मल दी। चश्मदीदों ने बताया कि यह घटना मुस्लिम बहुल खजराना क्षेत्र में तब हुई जब पठान नाहर शाह वली दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद दरगाह से बाहर निकले थे। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संपत उपाध्याय ने बताया कि पठान के चेहरे पर कालिख मलने के मामले में स्थानीय नागरिक सद्दाम (32) की भूमिका सामने आई है और उसे थाने में बुलाकर पूछताछ की गई है। उपाध्याय ने बताया कि सद्दाम को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता के चेहरे पर कालिख मलने के पीछे उसके मकसद का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सद्दाम चाय बनाने के पतीले की कालिख अपने हाथों में लगाकर आया था और पठान दरगाह से जैसे ही बाहर निकले, उसने उन्हें फूल माला पहनाने के बाद उनके चेहरे पर कालिख मल दी। उधर एआईएमआईएम की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. नईम अंसारी ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बताया कि उनकी पार्टी ने इस मामले में खजराना पुलिस को आवेदन देकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा,पुलिस को बारीकी से पड़ताल कर पता लगाना चाहिए कि पठान के चेहरे पर कालिख मलने की घटना के पीछे आखिर किन लोगों का हाथ है? अंसारी ने बताया कि मुंबई के भायखला क्षेत्र के पूर्व विधायक पठान एआईएमआईएम की संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मंगलवार को ही मध्यप्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे।

विधायक नितेश राणे की जमानत याचिका खारिज

मुंबई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर बी रोटे ने राणे की जमानत याचिका खरिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में दस दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे।

हिजाब विवाद में छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

मंगलुरु। उडुपी जिले स्थित एक सरकारी महिला कॉलेज की एक छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके कक्षा के भीतर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध किया है। छात्रा रेशम फारूक ने यह याचिका दायर की। रेशम का प्रतिनिधित्व उसके भाई मुबारक फारूक ने किया।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है और इस्लाम के तहत यह एक आवश्यक प्रथा है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि उसे और उसकी अन्य सहपाठियों को कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

याचिका में कहा गया है कि कॉलेज ने इस्लाम धर्म का पालन करने वाली आठ छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया। इसमें कहा गया है कि ए छात्राएं हिजाब पहने थीं, इसलिए उन्हें शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से शतहाबिश शिवन्ना, अर्णव ए बगलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन अदालत में पेश हुए।

2021-22 के विनिवेश लक्ष्य में भारी कटौती

2022-23 में 65,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से होने वाली आय के अनुमान में भारी कटौती करते हुए इसे 1.75 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ ही उसने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य में बड़ी कटौती की घोषणा की है। पिछले साल उन्होंने 2021-22 के बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था। लेकिन वित्त वर्ष खत्म होने में सिर्फ दो महीने का ही वक्त रह जाने के बीच सरकार अबतक सिर्फ 12,030 करोड़ रुपए का ही विनिवेश राजस्व जुटा पाई है। इसमें 2,700 करोड़ रुपए एयर इंडिया की बिक्री से मिले हैं जबकि 9,330 करोड़ रुपए विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की अल्पांश हिस्सेदारी बेचने से मिले हैं। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी बेचकर वह वर्ष 2021-22 के संशोधित विनिवेश लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। एलआईसी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारियां चल रही हैं और मार्च में इसके आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, आरआईएनएल और पवनहंस लिमिटेड की भी रणनीतिक बिक्री की कोशिश में लगी हुई है। सरकार इसके पहले भी कई बार अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने से चूकी है। वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सरकार सिर्फ 37,897 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी। वर्ष 2019-20 में विनिवेश प्राप्ति 50,298 करोड़ रुपए रही थी जबकि बजट अनुमान 1.05 लाख करोड़ रुपए का था जिसे बाद में संशोधित कर 65,000 करोड़ रुपए किया गया था।

हालांकि, वर्ष 2017-18 और 2018-19 में लगातार दो साल सरकार विनिवेश लक्ष्य से आगे निकल गई थी। वर्ष 2018-19 में विनिवेश का बजट लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए का था लेकिन सरकार 84,972 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही थी। इसके पहले 2017-18 में भी उसने एक लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से अधिक 1,00,056 करोड़ रुपए का विनिवेश राजस्व जुटाया था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाया जाएगा : निर्मला सीतारमण

भाषा। नई दिल्ली

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाया जाएगा, जो उद्यमों तथा सेवा केन्द्रों के विकास में राज्यों को सहयोगी बनाने में सक्षम बनाएगा। संसद में 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसमें सभी बड़े वर्तमान तथा नए औद्योगिक एनक्लेव कवर किए जाएंगे, ताकि वे उपलब्ध अवसंरचना का अधिकतम उपयोग कर सकें और निर्यात स्पर्धा बढ़ा सके।गौरतलब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अलग तरह के आर्थिक नियमन होते हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से विदेश निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही ए निर्यात केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। इन क्षेत्रों में परिचालन करने वाली कंपनियों को कर राहत मिलती है और माल के निर्यात करने पर कम शुल्क देना पड़ता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2006 में लागू किया गया था। हालांकि, न्यूनतम वैकल्पिक कर व्यवस्था लागू होने एवं कर छूट हटाने संबंधी उपबंध पेश किए जाने के बाद इसका महत्व कम हो गया। उद्योगों की ओर से बार-बार मांग की गई कि इन कानूनों के तहत कर लाभ जारी रखा जाए। विशेष आर्थिक क्षेत्र को पहले पांच वर्ष के लिए निर्यात से आय पर 100 प्रतिशत आय कर छूट मिलती रही थी। इसके आगे पांच वर्षों तक यह छूट 50 प्रतिशत मिलती थी। मंत्री ने कहा, हम विशेष आर्थिक क्षेत्र में सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार करेंगे। यह पूरी तरह से आईटी संचालित होगा तथा बेहतर सुविधा दिए जाने के साथ जोखिम आधारित जांच के साथ सीमा-शुल्क के राष्ट्रीय पोर्टल पर काम करेगा। यह सुधार 30 सिंतबर से लागू होगा।

क्विक न्यूज

एलआईसी के जीवन अक्षय और न्यू जीवन शांति प्लान में संशोधन

मुबंई। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 फरवरी 2022 से अपनी वार्षिकी योजनाओं के संबंध में एलआईसी की जीवन अक्षय (प्लान VII 857) और एलआईसी की जीवन शांति (प्लान 858) की वार्षिकी दरों में संशोधित किया है। संशोधित वार्षिकी दरों के साथ इन योजनाओं को संशोधित संस्करण विक्रय हेतु 1 फरवरी 2022 से उपलब्ध होगा। एलआईसी की न्यू जीवन शांति के दोनों वार्षिकी विकल्पों के तहत वार्षिकी राशि की गणना कैल्क्यूलेटर के माध्यम से, जो एलआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध और साथ-साथ विभिन्न एलआईसी ऐप्स के माध्यम से भी की जा सकती है।

संसाधन जुटाने के लिए हरित बॉन्ड लाएगी सरकार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि कर्ज कार्यक्रम के तौर पर संसाधन जुटाने के लिए सरकार हरित बॉन्ड (ग्रीन बॉन्ड) लेकर आएगी। सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.1 प्रतिशत रहेगा।उन्होंने कहा कि प्रमुख निजी निवेश को बढ़ाने और मांग को समर्थन देने के लिए सार्वजनिक निवेश को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। सीतारमण ने कहा कि गुजरात में गांधीनगर से सटे गिफ्ट सिटी के आईएफएससी में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो घरेलू नियमों के नियंत्रण से मुक्त होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कारोबारी विवादों के त्वरित समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का गठन किए जाने की भी घोषणा की।

देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों को बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेनदेन कर सकेंगे। सीतारमण ने कहा, 2022 में, देश के पूरे 100 फीसदी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे और इससे वित्तीय समावेश तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के जरिए खातों का संचालन संभव हो जाएगा तथा पोस्ट ऑफिस खातों और बैंक खातों के बीच कोष का आदान-प्रदान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों में विशेषकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लाभदायक होगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए बचत खाता सेवाएं और भुगतान संबंधी बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं।

बजट से आर्थिक वृद्धि को मिलेगी रफ्तार: बैंकर

कोलकाता। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को संसद में पेश किए गए बजट को बैंकरों ने आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने वाला बताते हुए कहा कि इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी।बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में की गई घोषणाएं हाल में मिली आर्थिक तेजी को समर्थन देने वाली हैं और इससे दीर्घावधि में वृद्धि बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ढांचागत विकास के लिए नियोजित पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी होने, किफायती आवास पर जोर और एमएसएमई एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास से भारत प्रगति के अगले दौर के लिए तैयार हो सकेगा।घोष ने कहा कि आपात ऋण गारंटी योजना के मद में आवंटन बढ़ने और सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के ऋण गारंटी ट्रस्ट में अतिरिक्त फंड डालने से इस क्षेत्र को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाने से किफायती आवासों की मांग को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा आवासीय वित्त की मांग भी बढ़ेगी।

जीएसटी संग्रह जनवरी में रिकॉर्ड 1.40 लाख करोड़ पर

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जनवरी, 2022 में रिकॉर्ड 1.40 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि जीएसटी व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। उन्होंने कहा, जीएसटी का सकल संग्रह जनवरी में रिकॉर्ड1,40,986 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ऐसा अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के कारण संभव हो सका है। गौरतलब है कि लगातार सातवें महीने में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इससे पहले अप्रैल, 2021 में जीएसटी संग्रह1,39,708 करोड़ रुपए था। वहीं दिसंबर, 2021 में यह 1.29 लाख करोड़ रुपए था।

वित्तमंत्री ने कुछ रसायनों पर सीमा-शुल्क में कटौती का प्रस्ताव दिया

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेथनॉल समेत कुछ रसायनों पर सीमा-शुल्क घटाने का मंगलवार को प्रस्ताव दिया। उन्होंने तराशे गए और पॉलिश हीरों और रत्नों पर सीमा-शुल्क को घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए सुधार लाएगी और पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती दरें तथा परियोजनाओं संबंधी आयात चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च कीमतों के कारण कुछ इस्पात उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क और प्रतिपूर्ति शुल्क रद्द किए जा रहे हैं। सीतारमण ने कहा, पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रण वाले ईंधन पर एक अक्टूबर से दो रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।

घोषणाओं से बहुत खुश हैं: मुकुंद हलवासिया

लखनऊ। केंद्रीय बजट 2022-23 पर मुकुंद हलवासिया सह अध्यक्ष यूपी चैप्टर ने कहा है कि हम घोषणाओं से बहुत खुश हैं क्योंकि ये उस भारत पर प्रकाश डालते हैं जिसमें हम 2035 तक रहेंगे। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और ई.पंजीकरण के साथ विदेशी ईंधन पर कम निर्भरता के साथ हरित ऊर्जा, बच्चों के लिए समावेशी ई.लर्निंग, जुड़ा हुआ माल ढुलाई और यात्री आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पोर्टल, डिजिटल पासपोर्ट और मुद्रा, कर व्यवस्था में स्थिरता और उम्मीद है कि जीएसटी के तहत लगातार बढ़ते संग्रह के साथ प्रत्यक्ष कर दरों में 20 प्रतिशत से कम की कमी आएगी। बढ़ती जीडीपी और जीएसटी संग्रह पहले से ही 1.4 ट्रिलियन मासिक से ऊपर सरकार को वित्तीय वर्ष 22.23 के लिए अनुमानित 10 ट्रिलियन रुपये से अधिक पूंजीगत खर्च के तरीके को लगातार बढ़ाने में सक्षम बनाएगीए जबकि 2030 तक राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे लाएगीए जबकि प्रत्यक्ष कर पर निर्भरता को कम करेगी।

तराशे, पालिश हीरे और रत्नों पर आयात शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव

भाषा। नई दिल्ली

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर आयात शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा, जबकि बगैर तराशे गए हीरे पर आयात शुल्क शून्य कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में तराशे और पॉलिश हीरे के साथ-साथ रत्नों पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सरकार ई-कॉमर्स के माध्यम से आभूषणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए वह इस साल जून तक सरलीकृत नियामकीय ढांचा लागू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा, रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तराशे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत किया जा रहा है। बगैर तराशे गए हीरे पर शून्य सीमा शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि कम कीमत वाले नकली आभूषणों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह से सीमा शुल्क निर्धारित किया जा रहा है कि इसके आयात पर कम से कम 400 रुपए प्रति किलोग्राम शुल्क का भुगतान किया जाए।

कोयला से गैस बनाने की चार परियोजनाएं शुरू होंगी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला से गैस बनाने की चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाई ऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला से गैस बनाने और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले को बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी।

आपात ऋण गारंटी योजना को मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च, 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गारंटी कवर को 50,000 रुपए से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही केन-बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने बजट भाषण में कहा कि फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद है।

नए ऑर्डर, उत्पादन की रफ्तार कम रहने से भारत में विनिर्माण गतिविधियों में नरमी

नई दिल्ली। कोविड-19 की नई लहर के कारण वृद्धि के सीमित रहने, कारोबारी विश्वास के प्रभावित होकर 19 महीने के निचले स्तर पर आने से नए ऑर्डर और उत्पादन में विस्तार की गति धीमी रही और जनवरी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में नरमी आई। एक मासिक सर्वेक्षण में मंगलवार को यह कहा गया। आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जनवरी में घटकर 54.0 पर आ गया जो दिसंबर में 55.5 था। यह पिछले साल सितंबर के बाद से इस क्षेत्र की सेहत में सबसे कमजोर सुधार है। आईएसएस मार्किट में सहायक निदेशक अर्थशास्त्र पॉलियाना डि लीमा ने कहा, पीएमआई के हालिया नतीजे बताते हैं कि कोविड-19 की नई लहर का भारत के विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन पर मामूली प्रभाव पड़ा है। कीमतों के लिहाज से देखें तो उत्पाद विनिर्माताओं को लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुद्रास्फीति की कुल दर बीते चार महीने में सबसे कम है लेकिन यह अभी भी दीर्घकालिक औसत से अधिक बनी हुई है।

पूर्वोत्तर के लिए नई योजना शुरू की जाएगी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।

बजट के बाद शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 848 अंक चढ़ा

भाषा। मुंबई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती पर जोर देने और नए करों से परहेज के बीच मंगलवार को शेयर बाजारों में तेजी आई। धातु और पूंजीगत सामान कंपनियों के शेयरों में भारी लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 848 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा मजबूत वैश्विक संकेतों ने भी घरेलू शेयर बाजारों को मजबूती दी। दिन के कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 59,032.20 की ऊंचाई को छूने के बाद 848.40 अंक या 1.46 प्रतिशत बढ़कर 58,862.57 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 237 अंक या 1.37 प्रतिशत बढ़कर 17,576.85 अंक पर बंद हुआ।

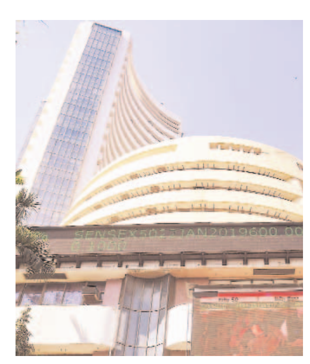

सेंसेक्स में सबसे अधिक 7.57 प्रतिशत की बढ़त टाटा स्टील में हुई। इसके अलावा सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और एचसीएल टेक भी बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावरग्रिड, एसबीआई, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, मारुति और रिलायंस के शेयर गिरकर बंद हुए।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए खजाना खोलते हुए 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से राजमार्गों से लेकर सस्ते मकानों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है।

लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने पूंजी व्यय 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। साथ ही सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती दर की समयसीमा बढ़ाने के साथ डिजिटल मुद्रा शुरू करने तथा क्रिप्टो संपत्तियों पर कर लगाने के भी प्रस्ताव किए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी बजट में बुनियादी ढांचा खर्च पर अच्छा-खासा जोर है। इसमें 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, नदियों को जोड़ने की योजना तथा नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण शामिल है।वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तेज वृद्धि के लिए आधार रखने का संकल्प जताते हुए कहा, अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना और पुनरुद्धार हमारे देश की मजबूती को बताता है।

उन्होंने कहा, बजट में राजकोषीय मजबूती की जगह आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। बजट वृद्धि के लिए निरंतर गति प्रदान करता रहेगा। बजट में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है जबकि पूर्व में इसके 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अगले वित्त वर्ष 2022-23 में इसके कम होकर 6.4 प्रतिशत तथा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत पर आने का अनुमान रखा गया है।

पेज एक का शेष

राजनीति से...

एवं जल निकासी क्षेत्र तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ सातों इंजन अर्थव्यवस्था को समान गति से बढ़ाएंगे। बजट प्रस्तावों में परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्रों (गति शक्ति), बैंकिंग और वित्तीय प्रौद्योगिकी (75 डिजिटल इकाइयां स्थापित की जाएंगी), कृषि, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र (बेटरी अदला-बदली नीति) समेत अन्य क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए आधार रखा गया है। लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने पूंजी व्यय 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। साथ ही सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती दर की समयसीमा बढ़ाने के साथ डिजिटल मुद्रा शुरू करने तथा क्रिप्टो संपत्तियों पर कर लगाने के भी प्रस्ताव किए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी बजट में बुनियादी ढांचा खर्च पर अच्छा-खासा जोर है। इसमें 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, नदियों को जोड़ने की योजना तथा नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण शामिल है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तेज वृद्धि के लिए आधार रखने का संकल्प जताते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना और पुनरुद्धार हमारे देश की मजबूती को बताता है। उन्होंने कहा कि बजट में राजकोषीय मजबूती की जगह आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। बजट वृद्धि के लिए निरंतर गति प्रदान करता रहेगा। बजट में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है जबकि पूर्व में इसके 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अगले वित्त वर्ष 2022-23 में इसके कम होकर 6.4 प्रतिशत तथा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत पर आने का अनुमान रखा गया है। आर्थिक वृद्धि दर के बारे में इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5 प्रतिशत रहेगी। वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर करदाताओं के लिए चीजें सुगम बनाई गई हैं। एक नई आयकर रिटर्न प्रणाली लाई जाएगी और राजस्व प्राधिकरणों के अपीलीय अधिकारों को सीमित कर कानूनी विवाद कम किए जाएंगे। बजट में नई कंपनियों के लिए कर को लेकर राहत की अवधि बढ़ाई गई है। इसके तहत 15 प्रतिशत कॉरपोरेट कर का विकल्प चुनने वाली इकाइयां अपना उत्पादन 31 मार्च, 2024 तक शुरू कर इसका लाभ ले सकती हैं। सीतारमण ने न केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव किया, बल्कि डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल संपत्तियों पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। इसमें संपत्ति की खरीद लागत को छोड़कर किसी व्यय को कटौती में शामिल नहीं किया जाएगा। रोजगार का बड़ा स्रोत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के इरादे से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 15 प्रतिशत अधिभार की सीमा तय करने का प्रस्ताव किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कानून के स्थान पर नया कानून लाया जाएगा। बुनियादी ढांचा विकास को लेकर राज्य भागीदार बनेंगे। अप्रत्यक्ष कर मामले में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए परियोजना आयात योजना के तहत पूंजीगत सामान पर रियायती कर दर के प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा और आयात पर 7.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। यही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर लगातार मिल रही चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट को मजबूत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा बजट को पिछले साल के 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सैन्य साजोसामान के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट ने समग्र और भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ अगले 25 साल के लिए आर्थिक वृद्धि को आगे ले जाने का आधार रखा है। इस बजट में भारत की आजादी के 75 से 100 साल तक के अमृत काल में अगले 25 साल में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है।

गंगा किनारे...

आदि शामिल होगा। खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए युक्तिसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाएं देने के लिए सरकार निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि मूल्य श्रृंखला के अंशधारकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों की भागीदारी में पीपीपी आधार पर एक योजना शुरू करेगी। प्राकृतिक शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लगातार 8वें...

को मामूली राहत दी है। नए प्रावधान के अनुसार माता-पिता या अभिभावक के 60 साल के होने तक दिव्यांग को कर में राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14 प्रतिशत टैक्स छूट देने का फैसला किया है।

सड़क परियोजनाओं...

मल्टीमॉडल लाजिस्टिक पार्क आरंभ करने के लिए संविदाएं जारी की जाएंगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर के लोग लाभांवित होंगे।

गांवों-शहरों...

सके। वित्त मंत्री ने कहा कि हम मध्यस्थता की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ भी काम करेंगे। इससे पहले सोमवार को जारी आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम आवास योजना के तहत 25 नवंबर तक 33.99 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा, पीएमएवाई के तहत 80 लाख घरों का निर्माण करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना स्वागतयोग्य कदम है। क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष बोम्मन ईरानी ने कहा कि एक भूमि एक पंजीयन प्रणाली का क्रांतिकारी सुधार लाया गया है जो रियल एस्टेट परिवेश के लिए लाभदायक है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) के अध्यक्ष राजन बांदेलकर ने कहा कि बिक्री को बढ़ावा देने और 2022 तक सबके लिए आवास के सपने को पूरा करने के लिए क्षेत्र बजट में प्रोत्साहन के रूप में और उम्मीदें कर रहा था।

देशभर में...

और क्षमता वर्धन के लिए स्वदेशी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है। उन्होंने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नए उत्पाद तथा सक्षम लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा और पार्सल की सुगम आवाजाही के लिहाज से डाक तथा रेलवे के नेटवर्कों के एकीकरण की दिशा में भी अगुवाई करेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि डाक और रेलवे के एकीकरण से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक समाधान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए नए उत्पाद और सेवाएं शुरू करेगा। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और विशेष उद्देश्य वाले वाहनों में निवेश के लिए 38686.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रॉलिंग स्टॉक विकसित करने के लिए 7,977 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे रेलवे में नए अत्याधुनिक कोच और प्रौद्योगिकी लाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने समर्पित माल ढुलाई कॉरीडोर (डीएफसी) के लिए 15710.14 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। परिचालन और रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा इन परिसम्पत्तियों को मुद्रीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने पटरियों के नवीनीकरण के लिए 13335.47 करोड़, गेज परिवर्तन के लिए 2850 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 12108 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई लाइन के लिए भी 25243 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे।

अगले वित्त...

बड़ी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल एसेट ट्रांसफर के जरिए होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा शुरू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे नकदी प्रबंधन प्रणाली में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। प्राइमस पार्टनर्स-डिजिटल करंसी के प्रबंध निदेशक श्रवण शेट्टी ने कहा कि ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल मुद्रा से क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में सट्टेबाजी की गुंजाइश कम होगी। इससे अर्थव्यवस्था को डिजिटल मुद्रा का लाभ एक संरचनात्मक ढांचे में मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर लेन-देन को लेकर 30 फीसदी कर लगाने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्ताव का इस उद्योग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के मुख्य कार्यकारी एवं संस्थापक निश्चल शेट्टी ने कहा, अंततः भारत देश में क्रिप्टो क्षेत्र को कानूनी रूप देने की राह पर है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी में भागीदार अमित सिंघानिया ने कहा कि क्रिप्टो लेनदेन पर टीडीएस लागू करने से सरकार इस तरह के लेनदेन पर बेहतर तरीके से नजर रख सकेगी।

केंद्र ने...

तैयार हों। पहले चरण में यह योजना दो फरवरी 2006 से 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की गई थी, बाद में इसे एक अप्रैल, 2007 से 113 और 15 मई 2007 से 17 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया गया था। शेष जिलों को एक अप्रैल, 2008 से अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अधिनियम में अब देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों...

लिए टिकाऊ कारोबारी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारिस्थितिकी में सक्षमता को बेहतर किया जा सकेगा। सीतारमण ने कहा, हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं शासन समाधानों के जरिए इसे समर्थन दिया जाएगा। शून्य जीवाश्म ईंधन नीति और इलेक्ट्रिक वाहनों वाले विशेष आवागमन क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। इस नीति में बैटरी अदला-बदली के केंद्रों की स्थापना को गति दी जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को बदलकर चार्ज बैटरी लगवा सकेंगे।

रूस का यूक्रेन संकट पर अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब देने से इंकार

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को इन खबरों का खंडन किया कि मॉस्को ने यूक्रेन संकट को कम करने से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव पर वाशिंगटन को एक लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। इससे एक दिन पहले सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच तीखे-आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे। वहीं, इस सिलसिले में रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठकों का दौर जारी है। रूस अमेरिका और नाटो से कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा रूस की मांग है कि उसकी सीमाओं के पास नाटो हथियारों की तैनाती रोकी जाए और नाटो के बल पूर्वी यूरोप से वापस लौट जाएं। वहीं, अमेरिका और नाटो को लगता है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वाशिंगटन ने मॉस्को को मांगों पर लिखित प्रतिक्रिया प्रदान की है, और सोमवार को बाइडन प्रशासन के तीन अधिकारियों ने कहा कि रूसी सरकार ने अमेरिकी प्रस्तावों पर एक लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। हालांकि दूसरी ओर रूस के उप विदेश मंत्री एलेक्जेंडर ग्रूश्को ने मंगलवार को आरआईए नोवोस्ती समाचार एजेंसी से मंगलवार को बताया कि यह सच नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि इस संबंध में भ्रम पैदा हुआ है और अमेरिकी प्रस्तावों पर रूस की क्या प्रतिक्रिया हो, इस पर अभी विचार चल रहा है। पेसकोव ने कहा, पश्चिमी अधिकारियों ने कुछ अलग मुद्दे पर विचार व्यक्त किए होंगे। इससे पहले, अमेरिकी अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया था कि मॉस्को ने यूक्रेन संकट को कम करने से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव पर वाशिंगटन को एक लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने रूस की प्रतिक्रिया की विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा, बातचीत को सार्वजनिक रूप से उजागर करना उचित नहीं होगा और वे इसका फैसला रूस पर छोड़ते हैं कि वह अपनी प्रतिक्रिया को लोगों से साझा करें या नहीं। इस बीच, रूस ने पश्चिम देशों पर यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ाने का मंगलवार को आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका कीव में नाजियों को सत्ता में लेकर आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में मॉस्को ने यह टिप्पणी की, जहां रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई। अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन सीमा पर 1,00,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर रहा है जो दशकों में यूरोप में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। रूस द्वारा साइबर हमलों और झूठी सूचनाएं फैलाने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

रूस ने भारत और चीन को धन्यवाद दिया

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले चीन के प्रक्रियागत मतदान के खिलाफ मत देने और इसमें भारत, केन्या एवं गैबॉन के अनुपस्थित रहने पर संयुक्त राष्ट्र में एक रूसी राजनयिक ने मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहने पर चारों देशों को शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन सीमा पर तनावपूर्ण हालात को लेकर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में प्रक्रियागत मतदान में भाग नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रथम उप स्थाई प्रतिनिधि दमित्रि पोलिंस्की ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड के एक ट्वीट के जवाब में ट्विटर पर लिखा, जैसा हमने उम्मीद की थी, यह एक जनसंपर्क हथकंडे के अलावा और कुछ नहीं था। यह मेगाफोन डिप्लोमेसी (सीधे बातचीत करने के बजाय विवादित मामले में सार्वजनिक बयान देने की कूटनीति) का उदाहरण है। कोई सच्चाई नहीं, केवल आरोप और निराधार दावे। पोलिंस्की ने कहा, यह अमेरिकी कूटनीति का सबसे खराब स्तर है। अपने चार सहयोगियों चीन, भारत, गैबॉन और केन्या का धन्यवाद, जो मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहे। ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस की आक्रामकता केवल यूक्रेन और यूरोप के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इसे जिम्मेदार बनाने का दायित्व है। यदि पूर्व साम्राज्यों को बल से अपने क्षेत्र फिर से हासिल करना शुरू करने का लाइसेंस मिल जाए, तो दुनिया के लिए इसका क्या अर्थ होगा? यह हमें एक खतरनाक मार्ग पर ले जाएगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं पर संकट आने से रोकने के लिए यूएनएससी में इस मामले को लेकर आए। यह रूस की सद्भावना की परीक्षा होगी कि क्या वह वार्ता की मेज पर बैठेगा और तब तक बना रहेगा, जब तक हम किसी सहमति पर नहीं पहुंच जाते? अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन और क्यों जिम्मेदार है। बैठक से पहले परिषद के स्थाई और वीटो- अधिकार प्राप्त सदस्य रूस ने यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियागत वोट का आह्वान किया था कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अनुरोध पर हुई बैठक के लिए परिषद को नौ मतों की आवश्यकता थी।

● यूक्रेन पर मतदान से पहले अमेरिकी दबाव पर नही झुकने पर दी प्रतिक्रिया

श्रीलंकाई नौसेना ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

कोलंबो। नौसेना ने मंगलवार को यहां कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने स्थानीय मछुआरों द्वारा सतर्क किए जाने के बाद देश के क्षेत्रीय जल में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और मछली पकड़ने के दो ट्रॉलर भी जब्त कर लिए। यह घटना तब हुई जब स्थानीय मछुआरे उत्तर में भारतीयों को मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई जल में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक सप्ताह से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं। दो भारतीय नौकाओं को स्थानीय मछुआरों ने सोमवार की मध्यरात्रि के आसपास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के श्रीलंकाई हिस्से में प्वाइंट पेड्रो के तट पर देखा। भारतीय मछुआरों और दो नौकाओं को मछली पकड़ने के निरीक्षणालय ने आगे की कार्वाई के लिए कांकेसंतुरई में पुलिस की हिरासत में सौंप दिया।

यूक्रेनी रक्षा प्रेस सेवा द्वारा प्रदान की गई इस तस्वीर में यूक्रेनी लड़ाकू मेडिक्स सैन्य प्रशिक्षण मैदान पी लुहान्स्क क्षेत्रए पूर्वी यूक्रेन में घायलों की सामरिक चिकित्सा और हवाई निकासी पर एक प्रशिक्षण में भाग लेते हुए

अमेरिका में दो लोगों पर राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकियां देने का आरोप

कॉलेज पार्क (अमेरिका)। अमेरिका में मैरीलैंड और कंसास के एक-एक व्यक्ति पर राष्ट्रपति जो बाइडन को जान से मारने की अलग-अलग धमकियां देने का आरोप लगाया गया है। प्राधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मैरीलैंड के रयान मैथ्यू कॉनलन (37) और कंसास के स्कॉट रयान मैरीमैन (37) को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। कॉनलन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है। संघीय प्राधिकारियों ने बताया कि मैरीमैन ने पिछले मंगलवार को अपने गृहनगर में पुलिस को फोन किया और कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी जा रहा है। जब खुफिया सेवा के एक एजेंट ने उसे गत बुधवार को बुलाया तो मैरीमैन ने कहा कि ईश्वर में उसे वाशिंगटन जाकर एक नाग का सिर काटने के लिए कहा है। एजेंट ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा, मैरीमैन ने इससे इनकार किया कि यह नाग अमेरिका का राष्ट्रपति है । एजेंटों ने जब गत बुधवार को मैरीमैन को मैरीलैंड के एक रेस्त्रां की पार्किंग में पकड़ा था तो उसके बैग में हथियार नहीं मिला लेकिन उसमें कारतूस रखे हुए थे।

चीन से पहले के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट खतराः एफबीआई प्रमुख

भाषा। वाशिंगटन

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने चीन पर अमेरिकी अवधारणाएं और नवोन्मेष चुराने तथा हैकिंग के अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम को चीन की सरकार से पहले के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट खतरा है। एफबीआई निदेशक ने रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने चीन पर ए आरोप ऐसे वक्त लगाए हैं जब वह शीत ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है। रे ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि एक ओर जहां अमेरिकी विदेश नीति रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से निपटने के रास्ते तलाश कर रही है वहीं वह दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मान रही है। एफबीआई की ओर से उपलब्ध कराए गए भाषण की प्रति के अनुसार रे ने कहा, जब हम अपनी जांचों का मिलान करते हैं,तो पाते हैं कि इनमें से दो हजार से अधिक मामले चीनी सरकार द्वारा हमारी सूचनाओं अथवा प्रौद्योगिकियों को चुराने से जुड़े हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारी अवधारणाओं, नवोन्मेष, और आर्थिक सुरक्षा के समक्ष चीन जैसा व्यापक खतरा पैदा करता है। रे ने कहा, चीन सरकार की आर्थिक जासूसी से नुकसान सिर्फ इतना नहीं है कि उसकी कंपनियां अवैध रूप से प्राप्त तकनीक के आधार पर आगे बढ़ती हैं, बल्कि जब वे आगे बढ़ती हैं, तो वे हमारी कंपनियों और कर्मचारियों को पीछे धकेल देती हैं।

ब्राजील में भूस्खलन, बाढ़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 24 हुई

फ्रांको द रोचा (ब्राजील)। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 24 हो गई। दमकलकर्मी मलबे में से शव निकालने में लगे हुए हैं। नागरिक रक्षा प्राधिकरण के एक बयान के अनुसार, ब्राजील के सबसे घनी आबादी वाले राज्य में सप्ताहांत जोरदार बारिश हुई और हजारों लोगों को अपने घरो को छोड़ना पड़ा। रविवार को मृतकों की संख्या 19 थी। सिसेरो पेरेरा (54) ने फ्रांको द रोचा शहर में आपदा स्थल पर कहा, मै अपने भतीजे, उसकी पत्नी और दो साल के बच्चे की तलाश कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि शव अब भी कीचड़ मे फंसे है लेकिन अभी तक वे शव बाहर नही निकाल सके है। बारिश से करीब 27 शहर प्रभावित हुए हैं जिनमें से फ्रांको द रोचा शहर मे सबसे अधिक संख्या में लोगो ने जान गंवाई है। गवर्नर जोआओ डोरिया ने रविवार को प्रभावित इलाको का हवाई सर्वेक्षण किया और इन शहरो को 28 लाख डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

मिस्र में गैस लीक होने से एक परिवार के सात सदस्यों की मौत

काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक घर मे गैस लीक होने के कारण उसमे रह रहे परिवार के सात सदस्यो की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, हादसा सोमवार को काहिरा के शराबिया इलाके मे हुआ, जिसमे एक दंपति और उसके पांच बच्चो की दम घुटने के कारण मौत हो गई। बच्चो की उम्र 13 से 26 साल के बीच थी। लगभग दस करोड़ आबादी वाले मिस्र मे गैस लीक होने और आग लगने की घटनाएं बेहद आम है, खासकर घनी बस्तियो और गरीब इलाको मे, जहां सुरक्षा उपायो का पालन नही किया जाता। पिछले महीने, काहिरा के फैसल इलाके मे एक अपार्टमेंट मे आग लगने के कारण चार बच्चो की मौत हो गई थी।

मैक्सिको में साक्षात्कार के समय पत्रकार की हत्या

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको मे एक ऑनलाइन समाचार संस्थान के पत्रकार की सोमवार को तब गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह वीडियो साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रहा था। संस्थान के निदेशक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक महीने के अंदर मैक्सिको मे यह चौथे पत्रकार की हत्या है। मॉनिटर मिशोएकन नामक संस्थान के उपनिदेशक के कानूनी कार्यालयो मे पत्रकार राबर्टो टोलेडो जैसे ही पहुंचे, तीन हथियारबंद लोगों ने उन्हें गोली मार दी। मॉनिटर के निदेशक अर्मांडो लिनारेस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनकी भी योजना वहां पहुंचने की थी। पश्चिमी राज्य मिशोएकन में अभियोजकों ने कहा कि वह जिटाकुआरो शहर के एक मामले की छानबीन कर रहे थे। मिशोएकन स्टेट अटॉर्नी कार्यालय ने एक बयान में कहा कि टोलेडो की अस्पताल में मौत हो गई। लिनारेस ने कहा कि टोलेडो ने वीडियो कहानियां रिकॉर्ड की और मॉनिटर के लिए दो साल से काम कर रहे थे।

ऊर्जा संकट गहराने के बीच बाइडन ने कतर को बड़ा गैर-नाटो सहयोगी नामित किया

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को कतर को एक बड़ा गैर-नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) सहयोगी नामित किया। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है, जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल-हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। बाइडन ने व्हाइट हाउस में कतर के सत्तारूढ़ नेता के साथ एक बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने के खतरे के बीच यूरोप में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में बाइडन पश्चिमी देशों की मदद करने लिए गैस समृद्ध देश कतर की ओर देख रहे हैं। बाइडन ने कतर को बड़ा गैर-नाटो सहयोगी नामित करने की संसद को सूचना देने से कुछ घंटों पहले कहा था, कतर एक अच्छा मित्र और एक विश्वसनीय साझेदार है। यह कदम एमक्यू-9 रीपर ड्रोन की 50 करोड़ डॉलर से अधिक की बिक्री के लिए अमेरिकी अनुमोदन प्राप्त करने की कतर की कोशिश को सफल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इस संबंधी अनुरोध 2020 से लंबित है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अपना नाम गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि ऊर्जा संकट की स्थिति में कतर द्वारा यूरोपीय सहयोगियों की मदद किए जाने की उम्मीद से इस कदम का कोई लेना-देना नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में कतर से मिली मदद के लिए उसे गैर-नाटो सहयोगी नामित किया गया है। कतर यह दर्जा पाने वाला 18वां देश है। इससे पहले 2019 में ब्राजील को यह दर्जा मिला था।

यूएई पर यमन के हूती हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागीं

भाषा। दुबई

इजराइल के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निशाना बनाने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्टर मिसाइल दागीं। अधिकारियों ने कहा कि यह दूसरी बार है, जब अमेरिकी सैनिकों ने इस तरह का कदम उठाया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन द्वारा सोमवार देर रात इस बारे में की गई पुष्टि यमन के वर्षों लंबे युद्ध में व्यापक अमेरिकी भागीदारी को दिखाती है। अमेरिका ने यमन की निर्वासित सरकार की ओर से लड़ रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन को आक्रामक समर्थन प्रदान किया है। यूएई की रक्षा में उसकी भागीदारी ऐसे समय हुई है जब हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी स्थित अल-धफरा एयर बेस को एक लक्ष्य घोषित किया है। अल-धफरा में लगभग 2,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह प्रतिष्ठान सशस्त्र ड्रोन से लेकर एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों तक हर चीज के लिए परिचालन के एक प्रमुख आधार के रूप में काम करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी सेना ने यूएई पर आते एक मिसाइल खतरे का जवाब दिया। साकी ने कहा,इसमें संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के प्रयासों के लिए पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल शामिल है। मैं कहूंगी कि हम उनके (यूएई) साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं, पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर हम अपने अमीराती भागीदारों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं, तो हम ऐसा करने जा रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या अमेरिका अल-धफरा के बाहर भी लक्ष्यों को निशाना बनाएगा।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति की कार्रवाई तेज होने से कारोबारियों को सता रहा डर

बीजिंग। चीन में मंगलवार को नए चंद्र वर्ष की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के विस्तार से देशभर में हलचल है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे उच्च तकनीकी उद्योग और इसके अरबपति मालिकों के खिलाफ कार्वाई तेज होने संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। आधिकारिक मीडिया के अनुसार, कार्वाई की शुरुआत के बाद से चीनी सेना के 50 से अधिक उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित दस लाख से अधिक अधिकारियों को दंडित किया गया है।

Public Notice

This is to inform general public that Mr. Karan Bajaj and Mrs. Rajni Bajaj are owners of Property bearing No. 7690 (Plot No. 44) area measuring 200 sq. yds. situated at Ram Nagar, Paharganj, New Delhi vide Relinquishment Deed dated 05/02/2019, executed by Mrs. Kanta Bajaj, Mrs. Neelma Wadhwa, Mrs. Anjali Bajaj and Mrs. Shalini Bajajand further Mr. Karan Bajaj and Mrs. Rajni Bajaj are mortgaging the above said property with Fullerton India Credit Company Limited& in case anyone has any objection, the same may be raised within 07 days of this publication to Mr. Muneesh Dhawan/ Mr. Sudhir Jain (Advocates), Law Veritas, Unit no 907, 9th Floor, GD-ITL Tower, (B-08), Netaji Subhash Place, Delhi-110034 or contact at 9066707172/9818228636 (M).

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that Bank of Baroda. Netaji Subhash Place Branch intends to accept the under mentioned property standing in the name of Mr. Vinod Kumar Mittal S/o Shri Chandgi Ram Mittal as a security for a loan/ credit facility requested by one of its customers. In case anyone has got any right/title/interest/claims over the under mentioned property, they are advised to approach the bank within 10 days alongwith necessary proof to substantiate their claim. If no response is received within 10 days it is presumed that the property is free of any charge/ claim/ encumbrance and Bank shall proceed with the mortgage. Details of the property: Built up industrial unit, raised /erected over land bearing plot no. 67, having its land area measuring 530.00 Sq Mtrs./ 633 Sq. Yds., Rajasthani Udyog Vihar, Delhi 110033. Branch Details: Netaji Subhash Place Branch, Bank of Baroda, 1" Floor, Aggarwal Heights, Plot No. 5, Netaji Subhash Place, Delhi 110034. Phone No. 011-27357790/91. Details of Advocate: **Anshu Priyanka, Advocate. Chamber No. Y-8, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi 110054.**

जॉनसन के माफी मांगने के बावजूद मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं

भाषा। लंदन

ब्रिटेन में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पार्टियों के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बेशक माफी मांग ली है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जॉनसन और डाउनिंग स्ट्रीट के कर्मचारियों द्वारा आयोजित की गईं पार्टियों से संबंधित एक जांच में कहा गया है कि ए नियमों का घोर उल्लंघन थीं। वरिष्ठ लोकसेवक सू ग्रे ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि सरकार में नेतृत्व और निर्णय की विफलताएं थीं तथा कुछ चीजों को होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। जॉनसन ने सोमवार रात को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों को संबोधित किया। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने आलोचनाओं को गंभीरता से लिया है और वह इस मामले के मद्देनजर सरकार चलाने के तरीके में बदलाव लाएंगे। उन्होंने संसद में सांसदों से कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। उप प्रधानमंत्री डॉमिनिक राब ने मंगलवार को जॉनसन का बचाव करते हुए कहा, "उनका मानना है कि उन्होंने हर समय उनकी सलाह पर बेहतर ढंग से काम किया। पुलिस द्वारा जिन कार्यक्रमों के बारे में जांच की जा रही है।

● लॉकडाउन में पार्टियों के आयोजन का मामला

अमेरिकी सासंद ने बाइडन से पाक के मनोनीत राजदूत को मंजूरी न देने का आग्रह किया

इस्लामाबादा-वाशिंगटन। एक अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडन से पाकिस्तान के मनोनीत राजदूत मसूद खान की राजनयिक परिचयपत्र अस्वीकार करने का आग्रह किया है और उन्हें क्षेत्र में अमेरिका के हितों को कमजोर करने के लिए काम करने वाला और आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाला शख्स करार दिया है। उन्होंने कहा कि खान ने युवाओं को जिहादवादियों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है और विदेशी आतंकवादी संगठनों की प्रशंसा की है। पिछले साल अगस्त तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर चुके खान को नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नामित किया गया था। रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बाइडन को लिखे एक पत्र में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में खान के मनोनयन के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, (पाकिस्तान के प्रधानमंत्री) इमरान खान द्वारा क्षेत्र में अमेरिका के हितों, और हमारे भारतीय सहयोगियों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाले आतंकवाद के एक हमदर्द को नामित करने को सिर्फ निर्णय लेने की कमी और अमेरिका के लिए इस्लामाबाद की निरंतर अवमानना के तौर पर ही वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मसूद खान द्वारा प्रस्तुत किसी भी राजनयिक परिचय पत्र अस्वीकार करें।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General public on behalf of ICICI Bank Ltd. That Mr. Rohit Kapur is the Claiming owner of Flat / Unit No. 167, having area 1755 sq. fts. Type-V, Situated at Arun Vihar, Sector-37, Noida, Distt. Gautambudh Nagar - U.P. "the said property", by virtue of Mutation Letter dated 23.07.2021 issued by Noida Authority, after demise of his parents Mr. Tilak Raj Kapur & Mrs. Padma Kapur, All persons are hereby informed that above mentioned owner want to sell the said property, to Mr. Rohit Luthra & Mrs. Urvashi Dogra Luthra who is taking Loan from ICICI Bank Ltd., for purchase of the said property, if anybody has any objection/s upon the ownership of above owner its Sale /Mortgage/litigation, and any kind of objections, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 10 days of the present.

Kumar & Associates (Advocates & Consultants)
200, IInd Floor, 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N. Delhi-15
Ph : 011-41112527-28 kumarassociates.advocate@gmail.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public on behalf of ICICI Bank Ltd. that Mrs. Alka Kapoor is the owner of Entire Third Floor with roof rights (said floor) Built of Property bearing No.677-678, area measuring 123.66 sq. yds, Situated at Double Storey, New Rajinder Nagar, New Delhi "the said property", by virtue of sale deed dated 02.11.2004, registration No. 7848, executed by Mr. J C Kapoor and Mr. Rajnish Kapoor through attorney Mr. Naresh Kumar, All persons are hereby informed that above mentioned owner want to sell the said floor, to Mrs. Pammi Singh who is taking Loan from ICICI Bank Ltd., for purchase of the said floor, if anybody has any objection/s upon the ownership of above owner its sale /Mortgage/ litigation, and any kind of objections, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 10 days of the present.

Kumar & Associates (Advocates & Consultants)
200, IInd Floor, 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N. Delhi-15
Ph : 011-41112527-28 kumarassociates.advocate@gmail.com

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
(सीआईएन : एल70109डीएल1980पीएलसी169318)
पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
ई-मेल : camaccommercial@gmail.com
फोन : 7303495374
वेबसाइट : www.camaccommercial.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 08 फरवरी, 2022 को, इसके पंजीकृत कार्यालय में, आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित, अनुमोदित एवं अभिलेखबद्ध किए जाएंगे। उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.camaccommercial.com पर भी उपलब्ध है तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भेजी जा चुकी है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
हस्ता./-
स्वाति श्रीवास्तव
निदेशक
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 01-02-2021
डीआईएन - 08529225

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्लॉट-11, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में स्थित जेडीएम अपार्टमेंट सीजीएचसी लिमिटेड द्वारा श्री केशव चंद्र खंडूरी के नाम जारी किए गए फ्लैट नंबर 78 के संबंध में शेयर प्रमाण पत्र खो जाने/गुम होने की सूचना मिली है और उसके द्वारा सोसायटी को डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन दिया गया है।
सोसाइटी इस नोटिस के प्रकाशन से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र पत्र जारी करने के लिए दावा या आपत्तियां (लिखित रूप में) आमंत्रित करती है। यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो सोसायटी डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी।

सचिव
दिनांक रू 26/01/22 — जय दीबा मां
स्थान : नई दिल्ली — सीजीएचएस लिमिटेड

म्यांमा में सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा बढ़ गई हैः संरा दूत

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

म्यांमा के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई विशेष दूत नोलीन हेजर ने सोमवार को दावा किया कि सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा और क्रूरता बढ़ गई है, जिसके विरोध में देश में एक आंदोलन छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों ने हिंसा को समाधान के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर रुख सख्त कर लिया है। हेजर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि म्यांमा की स्थिति तेजी से अस्थिर हो गई है और हवाई हमलों सहित सैन्य अभियानों से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में लगभग 1,500 नागरिक मारे गए हैं और विस्थापित लोगों की संख्या 2021 के अंत के 3,20,000 के आंकड़े से बढ़कर अब 4,00,000 से अधिक हो गई है। यह एक फरवरी, 2021 से पहले ही विस्थापित हुए 3,40,000 लोगों के अतिरिक्त है, जब सेना ने आन सांग सू ची को सत्ता से बेदखल कर दिया था। छह सप्ताह पहले पद संभालने वाली हेजर ने कहा कि म्यांमा की लगभग आधी आबादी अब गरीबी के दलदल मे है और 1.44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। आसियान के विदेश मंत्री और कुछ नेता पिछले अप्रैल में हुई बैठक में पांच सूत्रीय सहमति को लागू करने के लिए म्यांमा पर दबाव डाल रहे हैं।

म्यांमा की नेता सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में सुनवाई 14 फरवरी को

बैंकाक। म्यांमा में अपदस्थ असैन्य नेता आंग सान सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में सुनवाई 14 फरवरी को शुरू होगी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। म्यांमा में फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने देश में हुए चुनाव में भारी गड़बड़ी के आरोपों में सू ची को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन आरोपों के संबंध में उन्हें कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। अन्य मामलों में सू ची को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मामले की जानकारी रखने वाले कानूनी अधिकारी ने बताया कि पूर्व नेता पर नवंबर 2020 में हुए चुनाव में केन्द्रीय चुनाव आयोग को प्रभावित करने के आरोप हैं। इस चुनाव में सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से जीत दर्ज की थी।राज्य चुनाव आयोग ने पिछले साल नवंबर में सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आयोग के सदस्यों को सैन्य सरकार ने नियुक्त किया था। मामले में सुनवाई राजधानी ने प्ई तॉ में होगी और जुर्म साबित होने पर तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

ईरान में दो समलैंगिक युवकों को फांसी

दुबई। ईरान में उन दो समलैंगिक युवकों को फांसी दे दी गई, जो यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी करार दिए जाने और मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बीते छह साल से जेल में बंद थे। समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दुनिया के सर्वाधिक दमनकारी देशों में से एक माने जाने वाले ईरान में समलैंगिकता अपराध है। जिन दो युवकों को फांसी दी गई है, उनकी पहचान मेहरदाद करीमपुर और फरीद मोहम्मदी के रूप में हुई है। दोनों युवकों को दो पुरुषों को यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य करने के अपराध में मौत की सजा सुनाई गई थी और राजधानी तेहरान से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मराघे शहर की एक जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।

Public Notice

This is to inform general public that Smt. Rekha has acquired the Property Bearing No. 14-A, area measuring 66 Sq. Yds., and Plot No. 15-A, area measuring 30 Sq. Yds., total area 66+30=96 Sq. Yds., i.e., 80.27 Sq. Mtrs., Out of Khasra No. 284/285, Situated in the Revenue Estate of Village Nasir Pur, area abadi known as Colony West Sagar Pur, New Delhi vide Gift Deed dated 30.11.2021, executed by Sh. Parladh Singh Gautam, and Now, Smt. Rekha is intending to sell the above said property to Mr. Deepak vide Sale Deed. Further Mr. Deepak is mortgaging the above said property with Fullerton India Home Finance Co. Ltd.& in case anyone has any objection, the same may be raised within 07 days of this publication to Mr. Muneesh Dhawan/ Mr. Sudhir Jain (Advocates), Law Veritas, Unit no 907, 9th Floor, GD-ITL Tower, (B-08), Netaji Subhash Place, Delhi-110034 or contact at 9066707172/9818228636 (M).

पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन : एल65929डीएल1947पीएलसी001240
ई-मेल : pnbfinanceindustries@gmail.com
पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com
फोन : 91-7303495375

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 08 फरवरी, 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के पृथक्कृत और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।
उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.pnbfinanceandindustries.com पर भी उपलब्ध है तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भेजी जा चुकी है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
श्वेता सक्सेना
(निदेशक एवं कम्पनी सचिव)
स्थान : नई दिल्ली — (डीआईएन-03120958 एवं
तिथि : 01-02-2022 — सदस्यता सं. : ए18585

सबको सुलभ नहीं ऑनलाइन कक्षाएं

डॉ. नीलम गुप्ता का कहना है कि जब तक वंचितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तब तक कक्षाओं की पहुंच एक मुद्दा बनी रहेगी।

शिक्षा उद्योग जो कभी सैद्धांतिक शिक्षा पर प्रमुख रूप से केंद्रित था, अब एक व्यावहारिक मोड़ ले चुका है और सॉफ्ट स्किल्स की ओर दृढ़ता से झुक रहा है। इसे जोड़ने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की आवश्यकता भी बढ़ी है।

ऑनलाइन शिक्षा पहले से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, लेकिन दुनिया में महामारी की मार के साथ, यह छात्रों के लिए एक विकल्प से एक आवश्यकता में बदल गया। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में ऑनलाइन शिक्षा बाजार 2025 के अंत तक लगभग 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर हासिल करने के लिए तैयार है। अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। ऑनलाइन या हाइब्रिड लर्निंग का परिचय।

● क्या जनरल जीज़ छात्रों के लिए ऑनलाइन सीखना एक फायदा है?

जेनरेशन जी अधिक जिज्ञासु, रचनात्मक और सहज होते हैं। वे सीखने के पैटर्न में बड़े बदलावों के माध्यम से एक लंबी और नवीन शैक्षणिक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कोविड प्रतिबंधों का पालन करने के अलावा इससे जुड़े कई अतिरिक्त लाभों के साथ आती है। छात्र कई उन्नत एड-टेक स्टार्टअप और ऑनलाइन शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं और पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्लिनिकल रिसर्च, ब्लॉकचैन, डेटा मैनेजमेंट, यूएक्स/यूआई जैसे अपरंपरागत पाठ्यक्रम अभी भी कैंपस के छात्रों के लिए विशिष्ट हैं और कई पेशेवर सहायता प्रदान करते हैं, जो नियमित स्कूलों और कॉलेजों से एक कदम आगे है। पैटर्न में ये बदलाव छात्रों को नौकरी के क्षेत्र के लिए तैयार कर रहे हैं और प्रत्येक छात्र को वैश्विक शिक्षकों के नेटवर्क से अपने जुनून और रचनात्मकता का पता लगाने की अनुमति दे रहे हैं और पूरे भारत में छात्रों को अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजार से जोड़ रहे हैं।

ई-लर्निंग छात्रों को एक आरामदायक जगह और किसी भी जगह से सीखने की क्षमता देता है और अधिक लचीले शेड्यूल की अनुमति देता है, खासकर जब वे स्कूल के अलावा कक्षाएं लेना चाहते हैं। ऑफ़लाइन शिक्षण से तत्काल परिवर्तन को शिक्षकों और कई छात्रों द्वारा आसानी से अनुकूलित किया गया था। हालांकि, कुछ वंचित छात्रों के लिए इस नए बदलाव का सामना करना मुश्किल था क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन उपलब्ध थे।

● ऑनलाइन सीखने का स्याह पक्ष

ऑनलाइन सीखने से छोटे बच्चे दिन में 12 घंटे से अधिक समय तक स्क्रीन पर चिपके रहते हैं जो माता-पिता के लिए खतरनाक हो सकता है। यह सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है जो मानसिक स्वास्थ्य विकार, तनाव और चिंता सहित अन्य गंभीर मुद्दों को जन्म दे सकता है। साथियों के बीच आमने-सामने संचार की कमी के कारण, ऑनलाइन सीखने से भी छात्रों में संचार कौशल विकास की कमी हो सकती है।

● यूनिसेफ की रिपोर्ट : 250 मिलियन छात्रों में से 8.5 प्रतिशत के पास इंटरनेट है

सभी नामांकित बच्चे जो ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम नहीं थे, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। (प्रथम नेटवर्क के भीतर एक स्वायत्त मूल्यांकन, सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान इकाई) द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण मोबाइल फोन, कनेक्टिविटी और यहां तक कि बिजली तक पहुंच में बाधाओं का सामना कर रहे छात्रों के वास्तविक खातों की पुष्टि करता है। उन छात्रों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीडब्ल्यूएल) के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करना मुश्किल लगता है।

● क्या भारत ऑनलाइन शिक्षा की ओर पूरी तरह से स्विच कर सकता है?

दुनिया में महामारी आने से पहले, देश यह सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि 2030 तक बच्चे कम से कम प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों और गरीबी को एक गंभीर मुद्दे के रूप में ध्यान में रखते हुए, यह तर्क देना आसान होगा कि अधिकांश लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं है।

एनसीईआरटी के सर्वेक्षण के अनुसार, कम से कम 27 प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप तक पहुंच नहीं है, जबकि 28 प्रतिशत छात्रों और अभिभावकों का मानना है कि बिजली की कमी प्रमुख चिंताओं में से एक है। ऐसे में छात्रों के लिए रोजमर्रा के असाइनमेंट और लाइव सेशन का सामना करना मुश्किल हो जाता है।

स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग (स्कूल) सर्वेक्षण के अनुसार, लॉक्ड आउट- स्कूली शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट, जिसमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वंचित घरों के 1,362 स्कूली बच्चे शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 37 प्रतिशत बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और 48 प्रतिशत कुछ शब्दों से अधिक नहीं पढ़ सकता है।

सारांश

दुनिया भर में ऑनलाइन सीखने में कोविड मानदंडों के कारण एक महान स्पाइक देखा गया, जिसमें कई एड-टेक स्टार्टअप नए युग के पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं, ऑनलाइन सीखने ने सिस्टम के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया और आज एक मजबूत स्थिति रखता है। सीखने के पैटर्न में इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र वंचित हैं, क्योंकि उनके पास बुनियादी बैकअप संसाधन नहीं हैं। भारत, ऑनलाइन सीखने की दुनिया में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद, अभी भी जनसंख्या में प्रौद्योगिकी साक्षरता और सामर्थ्य में एक बड़ा अंतर है। जब तक समाज में इस तरह के अंतराल मौजूद नहीं होंगे, तब तक ऑनलाइन शिक्षा सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा के पारंपरिक तरीके के प्रतिस्थापन के बजाय एक अतिरिक्त के रूप में देखें।

(लेखक एआरओएच फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ हैं।)

हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़

उनकी आत्मकथा **विंचवचा तेल** के सह-लेखक **प्रशांत रूपावटे** कह रहे हैं कि एक्टिविस्ट **सुनीता भोसले** ने एक असाधारण जीवन जिया है।

सुनीता भोसले, जो पारधी समुदाय के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई में सबसे आगे हैं, को हाल ही में महाराष्ट्र फाउंडेशन द्वारा कार्यकर्ता पुरस्कार (कार्यकर्ता पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है - संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत स्थापित एक धर्मार्थ संगठन और इसके लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के बुनियादी मानवीय सिद्धांत। उनकी आत्मकथा, विंचवचा तेल (बिच्छू का तेल), उनके संघर्ष की कहानी है। इस लेख में, मैं, पुस्तक के सह-लेखक के रूप में, पुस्तक की रचनात्मक प्रक्रिया से कुछ यादें ताजा करता हूं।

हम सभी अपने बारे में कहानियां बताना पसंद करते हैं। हालांकि, भोंसले का जीवन संघर्ष किसी फिल्म या नाटक से कम नाटकीय नहीं है और निश्चित रूप से याद करने लायक है। वह बिना रुके, बिना रुके, फूटते झरने की तरह बेदम बोलती है। वह इतनी सांस भी नहीं लेने देती कि मराठी में बोलने के बावजूद मुझे समझने में दिक्कत होती थी। मेरे लिए जाति, शोषण, अन्याय और अत्याचार के मुद्दे नए नहीं थे। मेरे पिता, प्रोफेसर जी वी रूपवते, कॉलेज में पढ़ते समय, दलित छात्रों के लिए एक छात्रावास में रहते थे। यह दादासाहेब रूपावते, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अम्बेडकरवादी, सामाजिक कार्यकर्ता और महाराष्ट्र के समाचार पत्र संपादक द्वारा स्थापित किया गया था। वह छात्रों का दूसरा बैच था। पहले बैच में लेखक दया पवार (उनके संस्मरण बालूता को दलित साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है), विद्वान रावसाहेब कस्बे और मधुकर पिचड़, जो महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री थे, जैसे प्रकाशक थे।

मेरे पिता सामाजिक आंदोलनों में शामिल थे और लक्ष्मण माने, पार्थ पोल्के जैसे कार्यकर्ता लेखकों ने हमारे घर में बैठकें कीं। इसलिए, भले ही मैं कई आंदोलनों और विचारों से अवगत था, जब मैंने भोसले की बात सुनी, तो मैं भीतर से हिल गया। मैंने फैसला किया कि उसके खाते को सार्वजनिक करने की जरूरत है। तथाकथित महान, सहिष्णु और जीवंत संस्कृति के अंधेरे और जघन्य पक्ष को उजागर करने की आवश्यकता थी, जो किनारों पर रहने वाले समूहों को किसी भी सभ्यता से वंचित करता है और उसी से विंचवचा

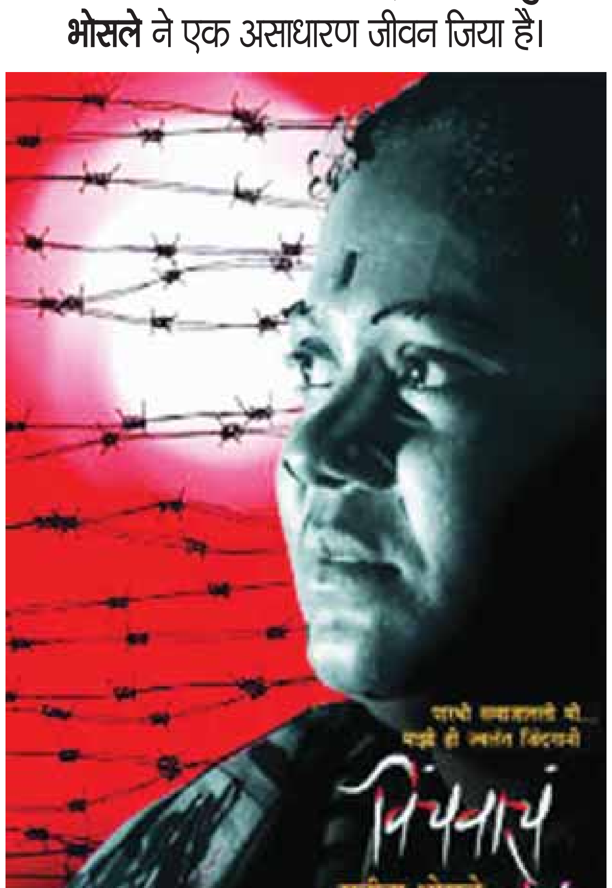

तेल ने आकार लिया।

मैं उससे मिलने शिरूर गया था। हम राज्य परिवहन निगम के शिरूर डिपो में अव्यवस्थित और तैलीय कैंटीन में फंस गए। वह मूसलाधार प्रवाह की तरह बोलने लगी और बूंदी की घटना सुनाने लगी (बूंदी चने के आटे की चीनी और तली हुई गेंद है)।

मई का दिन था और सुबह आठ बजे भी बहुत गर्मी थी। 10 बजे तक तापमान 35 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। यह शादियों का मौसम भी था और मुझे एक के बारे में पता चला, जो हमारे स्थान से लगभग 2 किमी दूर कलवंतवाड़ी में होने वाला था। मैं अपने छोटे भाई अविनाश के साथ वहां गया था। हम कूड़ेदान के पास वेडिंग हॉल के सामने घंटों इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम चार बजे तक शादी की दावत चल रही थी। एक बार जब प्लेट वहां फेंक दी जाती थी, तो हम कूड़ेदान में भाग जाते थे, आवारा कुत्तों को भगाते थे और प्लास्टिक की थैली में बंडियां इकट्ठा करते थे। यह सब करते हुए हम पुलिस द्वारा भगाए जाने के बारे में चिंतित थे। इसलिए हमने बूंदी के पैकेट को एक पेड़ के नीचे छिपा कर रखा। कुछ देर बाद जब हम वहां गए तो पैकेट गायब थे। आवारा कुत्ते उन्हें उठाकर ले गए। हमने जो मेहनत की थी वह बेकार गई। हम रोना बंद नहीं कर सके और उनकी बात सुनकर वेडिंग हॉल से लोग बाहर आ गए। हमारी बात सुनने के बाद, उन्होंने वास्तविक स्थिति को समझा और उन्होंने उदारता से हमें ताजा बूंदी दी, भोसले ने कहा।

मैं भोंसले के रिवेटिंग अकाउंट में तब तल्लीन था जब कैंटीन में टीवी सेट ने मंगलयान मिशन के सफल लॉन्च के बारे में खबर प्रसारित करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने श्रीहरि कोटा अंतरिक्ष यान पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्राचीन भारत की महान और गौरवशाली संस्कृति पर गर्व किया। यही वह क्षण था जब मुझे भारत की प्राचीन और शानदार विरासत को लाना अनिवार्य लगा, जिसमें भोंसले दुनिया के सामने रहते थे।

हमने विंचवचा तेल पुस्तक का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह भोंसले के समुदाय के शोषण को दर्शाती है। निम्न जाति के किसी भी आरोपी के खिलाफ बिच्छू के तेल का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है। वे इस तेल को आरोपी पुरुष के जननांगों पर लगाते हैं जिससे उनके जननांगों में सूजन और जलन होती है। आरोपी दर्द को सहन करने में सक्षम नहीं है और अपराध स्वीकार करता है। यह रचनात्मकता पर हमले के समान है। समाज ने इस तेल को दलितों, वंचितों और खानाबदोशों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसका उपयोग विभिन्न रूपक रूपों में जाति विभाजन को भड़काने के लिए या कभी-कभी फूट डालो और राज करो के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

सुनीता किनारे पर रहने वाली जाति की थी। वह अपराधी के रूप में ब्रांडेड जनजाति में पैदा हुई थी। उन्हें बचपन से ही हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन वह बहादुर है और 11 साल की उम्र से ही पारधी चरण के अपराधीकरण और शोषण के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। विंचवचा तेल इस उग्र और स्व-निर्मित कार्यकर्ता की जीवन कहानी है।

(अलका गाडगिल द्वारा अनुवादित)

हितों का टकराव

राजयोगी **ब्रह्मकुमार निकुंज** जी कहते हैं, मानसिक प्रदूषण ने समाज में नैतिक गिरावट को जन्म दिया है।

भारत और उसके पड़ोसी देशों में हाल के राजनीतिक मामलों पर थोड़ा प्रतिबिंब किसी को भी इन देशों के राष्ट्रीय वातावरण में उच्च प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को पहचानने और समझने में सक्षम करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इन देशों के बीच संघर्ष और टकराव विस्तारवादी सोच और दूसरी तरफ से अधिक जमीन हड़पने की प्रवृत्ति के कारण थे। यदि इन देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कोई पूर्वाग्रह और गलतफहमी नहीं होती, तो शायद अन्य देश प्रमुखों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से या राजनयिक वार्ता के माध्यम से किसी तरह का सुलह हो जाता। लेकिन उनके पूर्वाग्रहों ने मामूली मुद्दों को भी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान होने पर भी वे आपस में कटु संघर्ष करते रहे।

भारत में भी कई राज्यों में सत्ता के लिए जबरदस्त हाथापाई हुई है, जो आजकल राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाई दे रही है। एक तरफ, हम देखते हैं कि एक राज्य की विपक्षी पार्टी जल्द से जल्द सत्ता हथियाना चाहती है और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल सत्ता बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन राजनीतिक समूहों में से अधिकांश जिन्होंने पहले घोषित किया था कि वे मूल्य-आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं, सभी मूल्यों को हवा में फेंकने के लिए तैयार हो गए और अन्य राजनीतिक दलों के विधायकों और सांसदों को अपने समूहों में शामिल होने के लिए या

कुछ अन्य पार्टी बनाने के लिए कहने के लिए तैयार हो गए। गठबंधन का प्रकार।

यह अब राजनीति में एक बहुत ही आम बात हो गई है, जिससे हर पार्टी अपने प्रदर्शन को उन राज्यों में दोहराना चाहती है जहां उसने पिछले चुनावों में उच्च स्कोर किया था। और इसके लिए वे मूल्यों या नैतिकता की परवाह किए बिना किसी भी हद तक चले जाते हैं। हालाँकि, इस पूरे आनंदमय दौर में, प्रत्येक दल के एक-दूसरे के प्रति अपने पूर्वाग्रह हैं और कुछ दल विपक्ष को राजनीतिक रूप से अछूत भी मानते हैं और इसलिए उनके खिलाफ गहरा पूर्वाग्रह है।

अंतिम विश्लेषण में, यह कहा जा सकता है कि ये सभी दलगत राजनीति में गहराई से शामिल हैं और राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को भूल गए हैं। वे गरीबों, दबे-कुचले और पिछड़े वर्गों के हितों की भी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, जिसके लिए वे फूट-फूट कर रोते रहे हैं। इन समूहों को इस बात की कभी चिंता नहीं होती है कि नए चुनावों से राष्ट्रीय खजाने पर भारी खर्च आएगा और हजारों पुलिसकर्मियों, पर्यवेक्षकों आदि के समय और ऊर्जा की खपत होगी। हालांकि, वे हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि नए चुनाव के मामले में उन्हें या उनकी पार्टी को क्या करना होगा। चुनाव। संक्षेप में, पार्टी हित और सत्ता और प्रतिष्ठा की लालसा उनमें इतनी गहराई से निहित है कि वे एक-दूसरे से नफरत करते हैं और फिर भी वे सत्ता के लिए सौहार्दपूर्वक मिलकर काम करने को तैयार हैं।

देश की स्थिति इतनी खराब क्यों है जितनी अभी है? राष्ट्रीय वातावरण इतना प्रदूषित क्यों है? सत्ता की लालसा, दलगत राजनीति, पूर्वाग्रहों जैसे ये सभी कारक किस कारण से हैं? बुद्धिमान लोग इतने नीचे क्यों गिर गए हैं? हर कोई स्वार्थी या संकीर्ण सोच वाला क्यों होता है? खैर, एक गहन और व्यावहारिक अध्ययन से पता चलेगा कि यह स्थिति न केवल राजनीति में बल्कि धर्म जैसे अन्य क्षेत्रों में भी व्याप्त है, जहां प्रतिष्ठा और स्थिति एक मुद्दा बन जाती है और इसके लिए सत्य की बलि दी जाती है। इसी प्रकार व्यापार में लोग धन को शक्ति मानते हैं और इसलिए उस शक्ति की ओर भागते हैं। अकादमिक क्षेत्र में, लोग डिग्री, डिप्लोमा और पुरस्कारों को शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतीक के रूप में मानते हैं और इसलिए, वे उस दिशा में काम करते हैं। इस प्रकार यह अफ़सोस की बात है कि आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति से वंचित, वे इस चूहे की दौड़ में भागते हैं और अंततः डिग्री और रुपये को छोड़कर खाली हाथ चले जाते हैं। इस विषय पर गहन चिंतन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वयं के प्रति अज्ञानता के कारण आत्म-सम्मान और संतोष का ह्रास हुआ है। और इसी नुकसान ने मनुष्य को सांसारिक शक्ति, पद और प्रतिष्ठा की अल्पकालिक प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है।

अतः वस्तुओं की उपयुक्तता में ही मनुष्य को स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और स्वाभिमान की भावना रखनी चाहिए। इस उथल-पुथल का कोई दूसरा समाधान नहीं है।

590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी

धवन, श्रेयस, अश्विन, कमिंस व रबाडा, शीर्ष मूल्य वर्ग में

●आईपीएल नीलामी में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी

भाषा | नई दिल्ली

अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर जैसे शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों के साथ पैट कमिंस और कागिसो रबाडा की तरह दिग्गज विदेशी खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग की आगामी नीलामी में दो करोड़ रुपये के उच्चतम आधार मूल्य वर्ग में शामिल हैं। इस बड़ी नीलामी का आयोजन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा।

दो दिवसीय नीलामी के दौरान 590 खिलाड़ियों के लिए बोली लगेगी। आईपीएल ने मंगलवार को अंतिम नीलामी सूची की घोषणा की, जिसमें पिछले महीने जारी किए गए 1,214 खिलाड़ियों की मूल सूची से आधे से अधिक खिलाड़ियों को हटा दिया है। यह सूची फ्रेंचाइजी टीमों की खिलाड़ियों में रुचि पर आधारित है।

इसमें शामिल 590 क्रिकेटरों में से कुल 228 कैप्ड (अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके) खिलाड़ी हैं, जबकि 355 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। इसमें सात सहयोगी (एसोसिएट) देशों के हैं। भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, इशांत शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने भी खुद को शीर्ष मूल्य वाली श्रेणी में रखा है। अय्यर और धवन शीर्ष वर्ग में हैं लेकिन नीलामी में हिस्सा लेने वाली 10 टीमें ईशान किशन, देवदत्त पडिकल, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, पिछले सत्र के शीर्ष विकेट लेने वाले हर्षल पटेल, स्पिनर युजवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए बोली लगाना चाहेंगी। यह सभी खिलाड़ी शीर्ष मूल्य वाले दो करोड़ रुपए के वर्ग में हैं। इस नीलामी में कुल 370 भारतीय खिलाड़ी और 220 विदेशी क्रिकेटर शामिल होंगे, जिनमें से 48 खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ रुपये के वर्ग में रखा है। विदेशी खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, कमिंस, रबाडा, ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला मिशेल मार्श और स्टीव स्मिथ, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन और दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस के लिए फ्रेंचाइजी टीमें बड़ी बोली लगा सकती है। ए सभी खिलाड़ी शीर्ष श्रेणी की सूची में है। सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा जैसे भारतीय दिग्गजों का भी आधार मूल्य दो करोड़ रुपए है लेकिन उनके लिए फ्रेंचाइजी शायद पहले जैसी दिलचस्पी ना दिखाए।

नीलामी सूची में 20 खिलाड़ी हैं जिनका आधार मूल्य डेढ़ करोड़ रुपये है जबकि 34 खिलाड़ी एक करोड़ रुपए के आधार मूल्य वाले क्रिकेटरों की सूची में हैं।

भारत के अंडर-19 सितारे, कप्तान यश धुल, विक्की ओस्तवाल और राजवर्धन हैंगरगेकर के साथ शानदार लय में चल रहे शाहरुख खान, दीपक हुड्डा और अवेश खान जैसे खिलाड़ी इस नीलामी के दौरान अपनी छाप छोड़ने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के 42 वर्षीय स्पिनर इमरान ताहिर नीलामी में सबसे उम्रदराज हैं जबकि अफगानिस्तान के 17 वर्षीय नूर अहमद सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। नूर फिलहाल वेस्टइंडीज में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।

अंडर -19 के सभी भारतीय खिलाड़ियों में मध्यम तेज गेंदबाज हैंगरगेकर का नीलामी आधार मूल्य 30 लाख रुपये है, जबकि अन्य के लिए यह 20 लाख रुपये है।

पंजाब किंग्स के पास सबसे अधिक 23 स्लॉट (खिलाड़ियों के लिए जगह) उपलब्ध हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस को कम से कम 21 खिलाड़ियों को टीम में जोड़ना होगा। बाकी टीमों के पास 22-22 स्थान हैं।

पंजाब किंग्स नीलामी में सबसे ज्यादा 72 करोड़ रुपये के साथ जाएगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास इसके लिए सबसे कम 47.5 करोड़ रुपए है। सबसे अधिक विदेशी खिलाड़ियों वाली सूची में 47 क्रिकेटरों के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है जबकि वेस्टइंडीज के 34 क्रिकेटर अपना दावा पेश करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के 33, श्रीलंका के 23, इंग्लैंड के 24, न्यूजीलैंड के 24 और अफगानिस्तान के 17 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं।

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज दर्शकों के बिना खेली जाएगी: जीसीए

अहमदाबाद। गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) ने मंगलवार को कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच छह से 11 फरवरी तक होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला कोविड-19 महामारी के कारण दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में खेली जाएगी। तीनों मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

जीसीए ने ट्वीट किया कि हम वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर एकदिवसीय श्रृंखला की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। छह फरवरी को पहला वनडे एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक मैच होगा क्योंकि भारत इस प्रारूप में अपना 1000 वां मुकाबला खेलेगा।

भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम होगी जो यह उपलब्धि हासिल करेगी। बोर्ड ने एक अन्य ट्वीट में बताया, मौजूदा हालात को देखते हुए सभी मैच दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे के बाद दोनों टीमों को कोलकाता में तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलनी है।

भारत के सामने आस्ट्रेलियाई चुनौती

●अंडर-19 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज

भाषा | कूलिज (एंटीगा)

मैदान पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को और मैदान के बाहर कोरोना वायरस को हराने वाली भारत और आस्ट्रेलिया की दिग्गज टीमें अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में यहां बुधवार को आमने सामने होंगी।

चार बार की चैम्पियन भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराकर टूर्नामेंट में आगाज किया। इसके बाद हालांकि कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आयरलैंड के खिलाफ बमुश्किल 11 खिलाड़ी जुट सके। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे ग्रुप मैच में पांच खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे।

कप्तान यश धुल, उपकप्तान शेख रशीद, आराध्य यादव, मानव पारख और सिद्धार्थ यादव कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। ए पांचों आयरलैंड और युगांडा के खिलाफ नहीं खेल सके जिसके बाद बीसीसीआई को वैकल्पिक खिलाड़ी भेजने पड़े। युगांडा के खिलाफ छह रिजर्व खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा गया। भारतीय टीम ने हालांकि आयरलैंड और युगांडा दोनों को हराया और क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को मात दी। अब भारत के पास पूरी मजबूत टीम है और निशांत सिंधु भी संक्रमण से उबर चुके हैं।

भारत को हालांकि आखिरी ओवरों में अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। उससे पहले भारत ने आयरलैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 307 और युगांडा के खिलाफ 405 रन बनाए जो अफ्रीकी टीम के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत थी।

अब सामने आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है। भारत का मनोबल इस बात से बढा होगा कि कोरोना से जूझते हुए भी सारे मैच जीतकर वह अंतिम चार में पहुंचा है। भारत लगातार चौथी बार सेमीफाइनल खेलेगा। भारत के पास हरनूर सिंह, अंगकृष रघुवंशी, राज बावा के अलावा धुल और रशीद जैसे बल्लेबाज हैं धुल ने पहले मैच में 82 रन बनाए थे। गेंदबाजी में रवि कुमार ने बांग्लादेश के खिलाफ पांच ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे। तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर, स्पिनर विक्की ओस्तवाल और कौशल तांबे के साथ मध्यम तेज गेंदबाज बावा पर नजरें होंगी।

दो बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया। उसके पास शानदार सलामी बल्लेबाज टीग वीली है जिन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है।पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 71 गेंद में 97 रन बनाए और भारत को उनके बल्ले पर अंकुश लगाना होगा। भारत ने अभ्यास मैच में आस्ट्रेलिया को हराया था।

टीमें

भारत : यश धुल (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, हरनूर सिंह, राज बावा, कौशल ताम्बे, दिनेश बाना, निशांत सिंधु, विकी ओस्तवाल, राजवर्धन हंगरगेकर, वासु वत्स, रवि कुमार।

आस्ट्रेलिया : कूपर कोनोली (कप्तान), कैंपबेल केलावे, टीग वीली, एडेन काहिल,कोरे मिलर, जैक सिनफील्ड, टोबियास स्नेल, विलियम साल्जमैन, जैक निसबेट, लाचलान शॉ, टाम व्हाइटनी।

बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी

●29 जुलाई को भारत का सामना आस्ट्रेलिया से होगा

भाषा | दुबई

राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी और 29 जुलाई को बर्मिंघम खेलों के पहले मैच में भारत का सामना आस्ट्रेलिया से होगा। लीग सह नाकआउट महिला टूर्नामेंट महिला 2020 टी-20 विश्व कप उपविजेता आस्ट्रेलिया और भारत के बीच 29 जुलाई को मैच से शुरू होगा। फाइनल और कांस्य पदक के मुकाबले सात अगस्त को खेले जाएंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में सभी प्रतिभागियों का ऐलान करने वाला क्रिकेट पहला खेल बन गया जिसमें महिला टी-20 टूर्नामेंट में श्रीलंका आठवीं टीम होगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कुआलालम्पुर में पिछले सप्ताह राष्ट्रमंडल खेल क्वालीफायर में श्रीलंका की जीत के बाद इसका ऐलान किया।

आस्ट्रेलिया, बारबाडोस, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट पहली बार खेला जा रहा है। इससे पहले 1998 में एक बार पुरुष क्रिकेट इन खेलों का हिस्सा था। उस समय शॉन पोलाक की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका टीम ने स्टीव वॉ की आस्ट्रेलियाई टीम को फाइनल में चार विकेट से हराया था। उन खेलों में सचिन तेंदुलकर, जाक कालिस और महेला जयवर्धने जैसे सितारों ने भाग लिया था। इस बार लीग सह नाकआउट टूर्नामेंट 29 जुलाई को आस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच से शुरू होगा। फाइनल सात अगस्त को खेला जाएगा। बारबाडोस, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया और भारत ग्रुप ए में हैं जबकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ग्रुप बी में हैं।

आईसीसी, सीजीएफ और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने श्रीलंकाई टीम को क्वालीफाई करने पर बधाई दी है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्यौफ अलार्डिस ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली सभी टीमों का ऐलान हो गया है।

ताइवान की टीम चीन में ओलंपिक समारोह में शिरकत करेगी

बीजिंग। ताइवान के ओलंपिक अधिकारियों ने होने वाले बीजिंग खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले को पलटते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उन पर ऐसा करने का दबाव डाला था। आईओसी के चीन के साथ दशकों पुराने समझौते के तहत ताइवान के खिलाड़ी ओलंपिक में चीनी ताइपे के तौर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। चीन ताइवान के स्व-शासित द्वीप के अपना क्षेत्र होने का दावा करता है।

आईओसी ने कहा कि चीनी ताइपे ओलंपिक समिति ने इस साल के शीतकालीन खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। ताइवान के अधिकारियों ने कहा कि ओलंपिक चार्टर के तहत दायित्वों को पूरा करने और आईओसी द्वारा अनुरोध करने के बाद उनका दल बीजिंग में उद्घाटन समारोह में भाग लेगा।

मिताली वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर

आईसीसी

भाषा | दुबई

भारतीय कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई जबकि तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी दूसरे स्थान पर बनी हुई है। हरफनमौलाओं में भारत की दीप्ति शर्मा एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर है।

मिताली के 738 रेटिंग अंक है और आस्ट्रेलिया की एलिसा हीली 750 अंक लेकर शीर्ष पर है। भारत की स्मृति मंधाना 710 अंक लेकर छठे स्थान पर बनी हुई है।

आस्ट्रेलिया की जोनासन गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर है जिनके 760 अंक है जबकि झूलन के 727 अंक है। आस्ट्रेलिया की मेगान शट 717 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। हरफनमौलाओं में इंग्लैंड की नटाली स्किवर शीर्ष पर है।

आस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी दूसरे और दक्षिण अफ्रीका की मरियाने काप तीसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद दो पायदान चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गई है।

टाटा ओपन में रामकुमार व अर्जुन हारकर पहले दौर से बाहर

पुणे। भारत के रामकुमार रामनाथन और अर्जुन काधे मंगलवार को यहां टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के शुरुआती दौर में हार के साथ बाहर हो गए। रामकुमार को आठवीं वरीयता प्राप्त स्टेफानो ट्रैवाग्लिया से 6-7, 6-4, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं स्थानीय खिलाड़ी काधे को जोआओ सूसा के खिलाफ 6-7, 7-6, 6-2 से पराजय का सामना करना पड़ा।

दक्षिण एशिया के एकमात्र एटीपी-250 टूर प्रतियोगिता के चौथे सत्र का आयोजन महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस संघ द्वारा किया जाता है। रामकुमार और ट्रैवाग्लिया दोनों ने शुरुआती सेट में आक्रामक खेल का सहारा लिया और अच्छे लय में दिख रहे थे।

पहले सेट में स्कोर जब 4-4 की बराबरी पर था तब चेन्नई के खिलाड़ी ने दमखम दिखाते हुए 6-5 की बढ़त ली लेकिन वे इस सेट को अपने पक्ष में नहीं कर सके।

खेल बजट में 305 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा

भाषा | नई दिल्ली

टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश की सफलता का प्रभाव खेल बजट में नजर आता है जब केंद्र सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तीन हजार 62 करोड़ 60 लाख रुपये आवंटित किए जो पिछले साल की तुलना में 305 करोड़ 58 लाख रुपये अधिक है।

पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने खेलों के लिए दो हजार 596 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए थे जिसे बाद में संशोधित करके दो हजार 757 करोड़ दो लाख रुपये कर दिया गया था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड में एतिहासिक स्वर्ण पदक सहित कुल सात पदक जीते। देश में चरणबद्ध तरीके से खेल गतिविधियां बहाल हो गई हैं और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल तथा हांगझू एशियाई खेलों के रूप में दो वैश्विक प्रतियोगिताओं को देखते हुए 2022 काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ने खेल गतिविधियों पर अधिक खर्च करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को पेश बजट में सरकार की अहम योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम में 316 करोड़ 29 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में 657 करोड़ 71 लाख रुपये आवंटित किए गए थे तो अब बढ़कर 974 करोड़ रुपये हो गए हैं।

खिलाड़ियों के कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है जो 245 करोड़ से 357 करोड़ रुपये हो गई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के बजट में सात करोड़ 41 लाख रुपये की कटौती की गई है जो अब 653 करोड़ रुपये होगा।

भारत ने महिला हाकी प्रो लीग में चीन को फिर दी शिकस्त

भाषा | मस्कट

भारतीय महिला हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को यहां चीन को 2-1 गोल से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। सोमवार को प्रो लीग में अपने पदार्पण मुकाबले में चीन को 7-1 से हराने के बाद मंगलवार को भारत ने इसी टीम को सुल्तान काबूस परिसर में 2-1 गोल से हराया।

भारतीय टीम इस मुकाबले में अधिक गोल तो नहीं कर सकी लेकिन टीम ने दिखाया कि वे बिना धैर्य खोए आक्रामक हॉकी खेलने में सक्षम हैं।

चीन की टीम को अनुभव की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा पहले हाफ में चीन की टीम गेंद को अधिक समय अपने कब्जे में नहीं रख सकी, उसके पास सटीक नहीं थे और डिफेंस भी कमजोर नजर आया।

आगरा के संभव ने राज्य स्तरीय ऑनलाइन ओपन शतरंज जीती

पायनियर समाचार सेवा | लखनऊ

यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में चल रही मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता के अंतर्गत ओपन वर्ग की राज्य स्तरीय ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम चक्र में नमन कुमार (गोरखपुर) को हराकर राज्य स्तरीय ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता जीती। दूसरे बोर्ड पर खेल रही सानवी शुक्ला ने श्रेयांश अलसीसरिया के साथ बाजी बराबरी के साथ समाप्त की।

तीसरे बोर्ड पर श्रेष्ठ यादव कानपुर ने प्रणव रस्तोगी (लखनऊ) को, चौथे बोर्ड पर सौम्या हसीजा ने भव्य जुनेजा को, पांचवीं बोर्ड पर वैष्णवी बागड़ी ने अक्षत अस्थाना को, छठे बोर्ड पर अहान अलसीसरिया ने आद्या गहलोत को, सातवें बोर्ड पर आयुष बिष्ट ने आनंद पंवार को, आठवीं बोर्ड पर सुवन देव ने श्रयांश को, नवें बोर्ड पर सुवांशी देव ने नीराजना निलय को और दसवीं बोर्ड पर स्वाति राणा ने कौशल किशोर को हराया।

प्रमुख खिलाड़ियों की अंक स्थिति

प्रथम स्थान पर संभव जैन (5 अंक), द्वितीय स्थान पर सौम्या हसीजा, तृतीय स्थान पर श्रेष्ठ यादव (दोनों के 4-4 अंक) चौथे स्थान पर सानवी शुक्ला, पांचवें स्थान पर वैष्णवी बागड़ी, छठे स्थान पर श्रेयांश अलसीसरिया (सभी के 3.5 अंक), सातवें स्थान पर प्रणव रस्तोगी और एनमन कुमार।

एकल खिलाड़ियों का युगल प्रारूप में खेलना खेल के लिए अच्छा: बोपन्ना

भाषा | नई दिल्ली

भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कहा है कि युगल ड्रॉ में एकल खिलाड़ियों की मौजूदगी खेल के लिए अच्छी है क्योंकि इससे अधिक प्रशंसक स्टेडियम में आते हैं और युगल प्रारूप का प्रचार करने में मदद मिलती है।

किसी भी टूर्नामेंट में एकल मुकाबले अधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं लेकिन दिन-प्रतिदिन युगल प्रारूप भी प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है क्योंकि शीर्ष एकल खिलाड़ी भी इसमें खेल रहे हैं और इससे युगल मुकाबले अधिक रोमांचक और कड़े हो रहे हैं।

प्रवेश के लिए जब सिर्फ युगल रैंकिंग पर विचार किया जाता था तो युगल खिलाड़ियों को दबदबा था। लेकिन एकल रैंकिंग पर भी गौर करने से शीर्ष एकल खिलाड़ी भी युगल मुकाबले खेलने लगे हैं जिससे युगल खिलाड़ियों के लिए दबदबा बनाए रखना मुश्किल हो गया है। बोपन्ना ने कहा कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह अच्छा है या बुरा लेकिन एकल खिलाड़ियों की मौजूदगी से फायदे की स्थिति होती है। यह पूछने पर कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इस प्रारूप में सिर्फ युगल विशेषज्ञों को खेलने की स्वीकृति मिले, बोपन्ना ने कहा, यह अजीब स्थिति है।

काफी एकल खिलाड़ी अपने खेल में सुधार के लिए युगल मुकाबले खेलते हैं। डेनिस शापोवालोव (बोपन्ना के जोड़ीदार) को युगल मुकाबले खेलना पसंद हैं और साथ ही साथ वह काफी कुछ सीख रहे हैं, चाहे रिटर्न में सटीकता हो या वॉली या रिटर्न, जिससे उसे एकल में काफी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आज मुझे पता है कि सभी टूर्नामेंट के लिए प्रवेश लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि काफी एकल खिलाड़ी भी युगल मुकाबले खेल रहे हैं।

भारत के शीर्ष युगल खिलाड़ी ने कहा, युगल खिलाड़ियों के लिए यह शानदार रहेगा अगर पुराना नियम लागू हो जाए जिसमें सिर्फ युगल रैंकिंग पर विचार किया जाता था लेकिन यह बदलाव नहीं होगा।

यही कारण है कि शीर्ष स्तर पर खेलते हुए रैंकिंग बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, अन्यथा 500 और 1000 स्तर के टूर्नामेंट में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा।

जापान ने विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में सऊदी अरब को हराया

सियोल। ताकुमि मिनामीनो और जुन्या इतो के गोल से जापान ने फुटबॉल विश्व कप क्वालीफायर्स ग्रुप बी के मैच में मंगलवार को यहां सऊदी अरब को 2-0 गोल से हराया। एशिया के ग्रुप बी क्वलीफाइंग में यह सऊदी अरब की पहली हार है। टीम ने अब तब आठ मुकाबलों में से छह में जीत दर्ज की है जबकि एक बराबरी पर छूटा है। सऊदी अरब की टीम अगर यह मैच जीतती तो विश्व कप का उसका टिकट पक्का हो जाता।

टीम ग्रुप की तालिका में 19 अंक के साथ शीर्ष पर है जबकि इस जीत के बाद जापान 18 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। मिनामीनो ने मैच के 31 वें मिनट में जुन्या इतो की मदद से जापान का खाता खोला। जुन्या इतो ने मध्यांतर के बाद मैच के 50वें मिनट में जापान की बढ़त को दोगुना कर दिया। दो ग्रुप में से प्रत्येक की शीर्ष दो टीमें विश्व कप के लिए स्वतः ही क्वालीफाई कर लेंगी।

वापसी करने की जल्दबाजी में नहीं हैं हार्दिक

●चयनकर्ता और टीम प्रबंधन मेरी स्थिति से अवगत हैं: पांड्या

भाषा | नई दिल्ली

पिछले कुछ वर्षों में हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी फिटनेस की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के साथ संवाद की कमी की अटकलें लगती रही हैं लेकिन इस हरफनमौला खिलाड़ी ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी स्थिति के बारे में हर कोई जानता है।

पंड्या पीठ में परेशानी के कारण पिछले दो साल से ज्यादा समय से नियमित गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वह आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान सभी को आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। वह सीवीसी के स्वामित्व वाली अहमदाबाद फ्रेंचाइजी की कप्तानी करेंगे। फ्रेंचाइजी की ओर से आयोजित बातचीत में पंड्या ने कहा कि गेंदबाजी फिटनेस के मामले में सभी को सूचित कर दिया गया है।

समझा जाता है कि पंड्या ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से स्पष्ट कर दिया है कि वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया जाए क्योंकि वह अभी अपने गेंदबाजी कार्यभार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज हार्दिक की तुलना में बल्लेबाज और गेंदबाज हार्दिक सुनने में काफी अच्छा लगता है।

हार्दिक से पूछा गया कि गेंदबाजी के लिहाज से वह खुद को कैसे परखते है तो उन्होंने कहा कि यह देखना सभी के लिए एक आश्चर्य की तरह होगा। मैं अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता हूं। उन्होंने हालांकि स्वीकार किया कि एक ऑलराउंडर के रूप में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होना चुनौतीपूर्ण रहा है। टी-20 विश्वकप के दौरान पंड्या की काफी आलोचना हुई थी लेकिन वह इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गेंदबाजी नहीं करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है और मैंने हमेशा खेल के तीनों प्रारूपों में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब मैंने तय किया था कि मुझे केवल बल्लेबाजी करनी है, तो मैं बस कुछ समय मैदान पर बिताना चाहता था और हां कि यह चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक आलोचना हमेशा अच्छी होती है, लेकिन आम तौर पर आलोचना मुझे परेशान नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने परिणाम को ज्यादा महत्व दिए बिना हमेशा प्रक्रिया को अपना कर कड़ी मेहनत की है। जब आप सच्ची मेहनत करते हैं तो परिणाम अपने आप तय हो जाते हैं।